चौथी दुनिया
www.chauthiduniya.com
मूल्य 5 रुपये
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार
1986 से प्रकाशित
25 मई-31 मई 2015
Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

मुस्लिम आतंकवाद का असली चेहरा

आतंकवाद एक गंभीर समस्या है, इस बात से किसी को इंकार नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हज़ारों लोगों को भेड़-बकरियों की तरह जेलों में ठूंस दिया जाए, एक विशेष वर्ग को इसके लिए निशाना बनाया जाए, प्रतिशोध की भावना के तहत कार्यवाही की जाए और मीडिया को हथियार बनाकर देश में नफरत का माहौल पैदा किया जाए. इस पर ध्यान देना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि आज वे लोग बाइज्जत बरी हो रहे हैं, जिन्हें आतंकवाद के झूठे आरोपों में 10 या 12 वर्ष पहले गिरफ्तार किया गया था. निचली अदालतों ने जिन्हें फांसी या उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी, आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें सभी आरोपों से बरी किया जा रहा है. ऐसे में, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये फर्ज़ी आतंकवादी थे, तो असली आतंकवादी कहां हैं? जिस समय ये लोग गिरफ्तार किए गए, उस समय पुलिस द्वारा बताई गई बातों पर विश्वास करते हुए मीडिया के एक बड़े हिस्से ने उन्हें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन और न जाने कौन-कौन से आतंकवादी संगठनों का सदस्य बताया था, लेकिन आज जब वे रिहा हो रहे हैं, तो कोई भी यह ख़बर चलाने को तैयार नहीं है. ऐसे में, चौथी दुनिया अपने पाठकों को उन पीड़ितों की दास्तां सुनाना चाहता है, जिन्हें निर्दोष होने की सज़ा मिली.

डॉ. क़मर तबरेज़

वर्ष 1975 में यश चोपड़ा के निर्देशन में बनने वाली फिल्म दीवार को ज़रा याद कीजिए, जिसमें विजय (अमिताभ बच्चन) के हाथ पर बचपन में ज़बरदस्ती लिख दिया जाता है कि मेरा बाप चोर है. इस कारण विजय को अपनी ज़िंदगी में तरह-तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. फिल्म देखने वालों ने इसे बहुत अच्छी तरह महसूस किया. अगर ऐसा ही कुछ वास्तविक जीवन में किसी बच्चे के साथ हो, तो वह किन तकलीफ़ों और परेशानियों का सामना करेगा, उसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है. हमारे देश में यह कहानी बार-बार दोहराई गई और सरकारी मशीनरी के भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण हज़ारों बच्चों को ऐसा दर्द झेलने पर मजबूर किया गया. सरकार और प्रशासन में बैठे मुट्ठी भर लोगों ने पूरी मुस्लिम बिरादरी को आतंकवाद के आरोप में घसीटने और देश के बहुसंख्यक वर्ग का ज़हन ख़राब करने का प्रयास किया, लेकिन शुक्र है कि वे सफल नहीं हो सके, क्योंकि देश के बड़े वर्ग ने उनकी झूठी कहानियों पर विश्वास नहीं किया. आज उन्हीं में से कोई वकील है, कोई जज है, कोई पुलिस वाला है, जो आतंकवाद के झूठे आरोपों में फंसने वाले निर्दोष मुसलमानों की रिहाई की वजह बन रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि उन निर्दोष मुसलमानों की रिहाई ऐसे समय में हो रही है, जब केंद्र में भाजपा की सरकार है, जिसे मुसलमान अपना दुश्मन समझते रहे हैं. दूसरी ओर एक सच्चाई यह भी है कि जिस समय उन मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा था, उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी, जिसे मुसलमान अपना हमदर्द समझते रहे हैं.

आइए, अब आपको कुछ फर्ज़ी आतंकवादियों की कहानी सुनाते हैं. मामला है गुजरात का, जहां 2002 के मार्च-अप्रैल महीने में गोधरा ट्रेन हादसे के बाद पूरे राज्य में सांप्रदायिक दंगे हुए और बड़ी संख्या में मुसलमानों की जान व माल की क्षति हुई. उसके लगभग पांच महीने बाद 24 सितंबर 2002 को गुजरात के ही गांधी नगर में स्थित प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर पर आतंकवादी हमला हुआ था. उस दिन शाम को लगभग साढ़े चार बजे दो आतंकवादी (फिदायीन) हैंड ग्रेनेड्स और एके-56 राइफलों के साथ मंदिर के गेट नंबर 3 से अंदर दाख़िल होते हैं और वहां मौजूद बच्चों, औरतों एवं अन्य श्रद्धालुओं पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं. हमले की ख़बर पाते ही सीआरपीएफ़ के जवान, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (डीआईजी) गुजरात और दूसरे उच्च पुलिस अधिकारी एसआरपी कमांडोज़ के साथ वहां पहुंचते हैं और अतिरिक्त पुलिस बल को वहां पहुंचने का आदेश देते हैं. देर रात तक पुलिस बल और फिदायीन के बीच गोलीबारी का सिलसिला जारी रहता है. उसी दौरान रात लगभग बारह बजे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) कमांडोज़ की एक टीम दिल्ली से वहां पहुंचती है. अगले दिन यानी 25 सितंबर, 2002 की सुबह दोनों फिदायीन मार दिए जाते हैं. उस हमले में 33 लोग, जिनमें एनएसजी कमांडोज़, स्टेट कमांडोज़ और एसआरपी ग्रुप के तीन अन्य लोग भी शामिल थे, मारे गए. लगभग 23 पुलिस जवानों और अधिकारियों समेत 86 लोग गंभीर रूप से घायल हुए.

एक नालिश (कंप्लेन) तत्कालीन एसीपी जीएल सिंघल (गवाह अभियोजन पक्ष पीडब्ल्यू-126) की ओर से 24 सितंबर, 2002 को गांधी नगर सेक्टर 21 के पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई. एनएसजी कमांडोज़ द्वारा मंदिर परिसर को राज्य पुलिस के हवाले करने के बाद प्राथमिकी सीआर नंबर 314/2002 दिनांक 29/09/2009 को गवाह अभियोजन पक्ष नंबर 126 की ओर से भारतीय दंड संहिता 302, 307, 153-ए, 451, 120 बी के तहत दर्ज कराई गई. उक्त रिपोर्ट 20 से 25 वर्षीय अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज की गई और गांधी नगर लोकल क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर वीआर तौलिया (पीडब्ल्यू-119) को जांच की ज़िम्मेदारी सौंपी गई. उनके नेतृत्व में कुछ दिनों तक जांच प्रक्रिया चलती रही. उसके बाद डीजीपी (गुजरात) की ओर से आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) को आदेश दिया गया कि वह इस केस की जांच करे, लेकिन लगभग 11 महीने तक भागदौड़ करने के बाद भी एटीएस यह पता लगाने में नाकाम रही कि कौन-कौन

(शेष पृष्ठ 2 पर)

आरोप जो साबित नहीं हुए

आरोपी नंबर-1

अल्ताफ़ मलिक पर आरोप लगाया गया कि उसने उन भारतीय मुसलमानों को एकत्र किया, जो सऊदी अरब गए हुए थे, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ संबंध स्थापित किए और जैश-ए-मोहम्मद से पैसा जुटाया. उसके बाद पोटा की धारा 22 (1) के तहत अल्ताफ़ मलिक को दोषी करार देते हुए उसे पांच वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई.

आरोपी नंबर-2

आदम भाई अजमेरी पर आरोप लगाया गया कि उसने स्थानीय लोगों की सहायता से शहर का जायज़ा लिया और (अक्षरधाम मंदिर पर हमला करने वाले) फिदायीन के ठहरने आदि की जानकारी के लिए बात की, इस केस के अन्य दो आरोपियों से फिदायीन की मुलाक़ात कराई, हवाला द्वारा पैसा मंगाया, दोनों फिदायीन को रेलवे स्टेशन से लिया और उन्हें शरण दी. ऑटो रिक्शा द्वारा फिदायीन को शहर में लेकर घूमा और वे सारे स्थान दिखाए, जहां पर हमला किया जा सकता था तथा फिर रात में अपने भाई के घर पर फिदायीन के ठहरने की व्यवस्था की. हमले के समय अक्षरधाम पर मौजूद रहा और गोलीबारी शुरू होने के समय तक वहां सक्रिय था. उसे भी पोटा अदालत ने दोषी करार देते हुए फांसी की सज़ा सुनाई.

आरोपी नंबर-3

मोहम्मद सलीम हनीफ़ शेख़ पर आरोप लगाया गया कि उसने सऊदी अरब में काम कर रहे कुछ भारतीय मुसलमानों को अपने घर पर एकत्र किया और उन्हें उकसाने वाले वीडियो दिखाए. वह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य है और उसने उक्त संगठनों से पैसा जुटाया. उसने भारत की अखंडता एवं संप्रभुता को ख़तरे में डालने के इरादे से भड़काऊ भाषण दिए. पोटा की विशेष अदालत ने उसे उम्रकैद (मृत्यु तक) की सज़ा सुनाई.

आरोपी नंबर-4

अब्दुल कय्यूम मुफ्ती साहब मोहम्मद भाई पर आरोप लगाया गया कि उसने फिदायीन को शरण दी, उर्दू में दो पत्र लिखे, जो अक्षरधाम हमले में मारे गए फिदायीन की जेब से पाए गए. उन पत्रों में दंगे भड़काने और सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने की बात थी. लिहाज़ा पोटा अदालत ने मुफ्ती अब्दुल कय्यूम को भी दोषी करार देते हुए फांसी की सज़ा सुनाई.

आरोपी नंबर-5

आरोपी नंबर 5 अब्दुल्लाह मियां यासीन मियां को जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य बताते हुए उस पर आरोप लगाया गया कि उसने फिदायीन को अपने यहां शरण दी और एंबेसडर कार में बैठाकर अक्षरधाम मंदिर तक छोड़ा. लिहाज़ा, पोटा की धारा (3) 3 के तहत उसे उम्रकैद की सज़ा दी गई.

आरोपी नंबर-6

चांद ख़ान के बारे में कहा गया कि वह मरने वाले आतंकवादियों (फिदायीन) से मिला, एक एंबेसडर कार 40 हज़ार रुपये में ख़रीदी और विस्फोटक सामग्री एवं हथियार रखने के लिए एक ख़ुफिया घर बनाया. बरेली से विस्फोटक सामग्री लेकर अहमदाबाद आया, फिदायीन को ऑटो रिक्शा में घुमाया और हथियार लाने-ले जाने में मदद की. विशेष पोटा अदालत ने उसे भी दोषी करार देते हुए मृत्यु दंड दिया.

मराठवाड़ा : सहकारी चीनी मिलों को दफ़नाने की साज़िश | P-4

बिहार विधान परिषद चुनाव : प्रत्याशियों की नहीं, सुप्रीमो की अग्नि परीक्षा | P-5

अब राज्यसभा में बहुमत न होने की आड़ | P-6

मुस्लिम आतंकवाद का असली चेहरा

पृष्ठ 1 का शेष

लोग इस साजिश में शामिल थे और हमले में मारे गए फिदायीन मंदिर तक किसकी सहायता से पहुंचे और इसके अलावा किन–किन अपराधों को अंजाम दिया. लिहाज़ा, एटीएस के डीजीपी केके पटेल के निर्देश पर 28 अगस्त, 2003 को इस केस की जांच की ज़िम्मेदारी क्राइम ब्रांच के तत्कालीन एसीपी जीएल सिंघल (जो स्वयं इस केस के गवाह नंबर 126 थे और जिन्होंने इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज कराई थी) को सौंपी गई.

यहीं से शुरू होती है, झूठे आतंकवादियों को गिरफ्तार करने की कहानी. कमाल की बात यह है कि जिस साजिश का पता लगाने में गुजरात एटीएस और दूसरे पुलिस अधिकारी 11 महीने तक हाथ–पैर चलाने के बावजूद नाकाम रहे, उसका पता क्राइम ब्रांच के एसीपी जीएल सिंघल ने एक दिन में ही लगा लिया और अगले ही दिन यानी 29 अगस्त, 2003 को अक्षरधाम मंदिर में फिदायीन की मदद करने वाले छह आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा करते हुए उन्हें न केवल गांधी नगर के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर कर दिया, बल्कि सभी आरोपियों को मीडिया के सामने भी पेश किया. अब आइए देखते हैं कि वे छह झूठे आतंकवादी कौन थे और उन पर क्या–क्या आरोप लगाए गए थे?

इन छह आरोपियों के बारे में एक जून, 2006 को अपना फ़ैसला सुनाते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था, कुछ अज्ञात विदेशी नागरिकों ने, जिनके बारे में संशय यह है कि वे सऊदी अरब और पाकिस्तान के थे, अक्षरधाम मंदिर पर हमला करने की साजिश रची थी. सऊदी अरब में रह रहे भारतीय मुसलमानों को मार्च-अप्रैल 2002 में होने वाले दंगों का बदला लेने के लिए उकसाया गया और उन्हें आतंकवादी हमले के लिए पैसा उपलब्ध कराने का विश्वास दिलाया गया.

आरोपी नंबर–1 अल्ताफ़ मलिक पर आरोप लगाया गया कि उसने उन भारतीय मुसलमानों को एकत्र किया, जो सऊदी अरब गए हुए थे, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर–ए–तैयबा के साथ संबंध स्थापित किए और जैश–ए–मोहम्मद से पैसा जुटाया. उसके बाद पोटा की धारा 22 (1) के तहत अल्ताफ़ मलिक को दोषी करार देते हुए उसे पांच वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई.

आरोपी नंबर–2 आदम भाई अजमेरी पर आरोप लगाया गया कि उसने स्थानीय लोगों की सहायता से शहर का जायज़ा लिया और (अक्षरधाम मंदिर पर हमला करने वाले) फिदायीन के ठहरने आदि की जानकारी के लिए बात की, इस केस के अन्य दो आरोपियों से फिदायीन की मुलाक़ात कराई, हवाला द्वारा पैसा मंगाया, दोनों फिदायीन को रेलवे स्टेशन से लिया और उन्हें शरण दी. ऑटो रिक्शा द्वारा फिदायीन को शहर में लेकर घूमा और वे सारे स्थान दिखाए, जहां पर हमला किया जा सकता था तथा फिर रात में अपने भाई के घर पर फिदायीन के ठहरने की व्यवस्था की. हमले के समय अक्षरधाम पर मौजूद रहा और गोलीबारी शुरू होने के समय तक वहां सक्रिय था. उसे भी पोटा अदालत ने दोषी करार देते हुए फांसी की सज़ा सुनाई.

आरोपी नंबर–3 मोहम्मद सलीम हनीफ़ शेख़ पर आरोप लगाया गया कि उसने सऊदी अरब में काम कर रहे कुछ भारतीय मुसलमानों को अपने घर पर एकत्र किया और उन्हें उकसाने वाले वीडियो दिखाए. वह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश–ए–मोहम्मद और लश्कर–ए–तैयबा का सदस्य है और उसने उक्त संगठनों से पैसा जुटाया. उसने भारत की अखंडता एवं संप्रभुता को ख़तरे में डालने के इरादे से भड़काऊ भाषण दिए. पोटा की विशेष अदालत ने उसे उम्रक़ैद (मृत्यु तक) की सज़ा सुनाई.

आरोपी नंबर 4 अब्दुल कय्यूम मुफ्ती साहब मोहम्मद भाई पर आरोप लगाया गया कि उसने फिदायीन को शरण दी, उर्दू में दो पत्र लिखे, जो अक्षरधाम हमले में मारे गए फिदायीन की जेब से पाए गए. उन पत्रों में दंगे भड़काने और सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने की बात थी. लिहाज़ा पोटा अदालत ने मुफ्ती अब्दुल कय्यूम को भी दोषी करार देते हुए फांसी की सज़ा सुनाई.

आरोपी नंबर 5 अब्दुल्लाह मियां यासीन मियां को जैश–ए–मोहम्मद और लश्कर–ए–तैयबा का सदस्य बताते हुए उस पर आरोप लगाया गया कि उसने फिदायीन को अपने यहां शरण दी और एंबेसडर कार में बैठाकर अक्षरधाम मंदिर तक छोड़ा. लिहाज़ा, पोटा की धारा (3) 3 के तहत उसे उम्रक़ैद की सज़ा दी गई.

आरोपी नंबर 6 चांद ख़ान के बारे में कहा गया कि

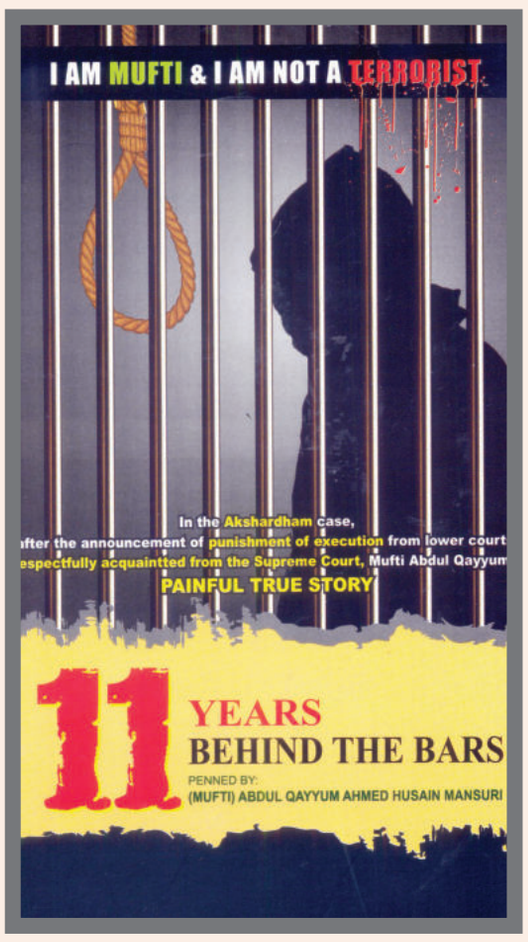

वह मरने वाले आतंकवादियों (फिदायीन) से मिला, एक एंबेसडर कार 40 हज़ार रुपये में ख़रीदी और विस्फोटक सामग्री एवं हथियार रखने के लिए एक ख़ुफिया घर बनाया. बरेली से विस्फोटक सामग्री लेकर अहमदाबाद आया, फिदायीन को ऑटो रिक्शा में घुमाया और हथियार लाने–ले जाने में मदद की. विशेष पोटा अदालत ने उसे भी दोषी करार देते हुए मृत्यु दंड दिया.

गुजरात की विशेष अदालत (पोटा) ने अक्षरधाम हमले से संबंधित पोटा केस नंबर 16/2003 की सुनावाई पूरी करते हुए ये तमाम निर्णय एक जुलाई, 2006 को सुनाए. उसके बाद सभी आरोपियों ने पोटा अदालत के फ़ैसले को चुनौती देते हुए 31 जुलाई, 2006 को गुजरात हाईकोर्ट में अपील (नंबर 1328/2006 और 1675/2006) दायर की. गुजरात हाई कोर्ट ने चार वर्षों के बाद इन दोनों अपीलों से

जस्टिस एके पटनायक एवं जस्टिस वी गोपाल गोडा की सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने 16 मई, 2014 को अक्षरधाम मामले में अपना फ़ैसला सुनाते हुए क्या कहा था. अदालत ने कहा था कि फ़ैसला सुनाने से पहले, देश की अखंडता एवं सुरक्षा को ख़तरे में डाल देने वाले इतने गंभीर मामले की जांच में एजेंसियों ने जिस अक्षमता का सुबूत दिया है, हम उस पर अपनी नाराज़गी का इज़हार करना भी आवश्यक समझते हैं.

संबंधित फौजदारी केस नंबर 02/2006 के तहत एक जून, 2010 को अपना फ़ैसला सुनाते हुए पोटा अदालत द्वारा दी गई सभी सज़ाओं को बरकरार रखा.

उसके बाद आरोपी नंबर 1 यानी अल्ताफ़ मलिक को छोड़कर शेष पांच आरोपियों ने छह अगस्त, 2010 को उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अर्ज़ी लगाई और स्वयं को गुजरात की अदालतों द्वारा दोषी करार दिए जाने के निर्णय और सज़ाओं का संशोधन करने की अपील की. सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई लगभग 4 वर्षों तक चली, जिसके बाद 16 मई, 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी लोगों को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया.

इन छह आरोपियों के बारे में एक जून, 2006 को अपना फ़ैसला सुनाते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था, कुछ अज्ञात विदेशी नागरिकों ने, जिनके बारे में संशय यह है कि वे सऊदी अरब और पाकिस्तान के थे, अक्षरधाम मंदिर पर हमला करने की साजिश रची थी. सऊदी अरब में रह रहे भारतीय मुसलमानों को मार्च–अप्रैल 2002 में होने वाले दंगों का बदला लेने के लिए उकसाया गया और उन्हें आतंकवादी हमले के लिए पैसा उपलब्ध कराने का विश्वास दिलाया गया. उपरोक्त मास्टर माइंड (आरोपी नंबर 6–चांद ख़ान) ने ट्रेन द्वारा कश्मीर से बरेली होते हुए अहमदाबाद का सफर किया, फिदायीन की भर्ती की. उन्हें राइफल्स, हैंड ग्रेनेड्स, बारूद और अन्य हथियार उपलब्ध कराए. उपरोक्त आरोपियों ने अहमदाबाद में ख़ुफिया स्थान की व्यवस्था करने में उनकी मदद की और अहमदाबाद के आसपास आने–जाने के लिए सवारी की भी व्यवस्था की. यहां तक कि हमला करने के लिए समय और जगह के चयन में भी मदद की. आरोपियों ने फिदायीन की सुरक्षा के मददेनज़र उन्हें नमाज़ पढ़ने का अंतिम अवसर भी उपलब्ध कराया.

यहां पर इस बात का जिक्र करना आवश्यक है कि गुजरात पुलिस ने जिस व्यक्ति को आरोपी नंबर 4 बनाया था यानी मुफ्ती अब्दुल कय्यूम, जिन्हें पोटा अदालत द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और फिर गुजरात हाईकोर्ट ने भी उस सज़ा को बरक़रार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया. उन्होंने 11 वर्ष सलाख़ों के पीछे शीर्षक से एक किताब लिखी है, जिसे जमीअत उलेमा हिंद के अध्यक्ष

(शेष पृष्ठ 3 पर)

टी शर्ट पहने हुए आरोपी चांद ख़ान, जो बाद में निर्दोष साबित हुए.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 12
दिल्ली, 25 मई–31 मई 2015
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060, +91–8451050786, +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

मुस्लिम आतंकवाद का असली चेहरा

पृष्ठ 2 का शेष

मौलाना अरशद मदनी ने आठ मई, 2015 को दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मीडिया के सामने रिलीज किया. इस किताब में मुफ्ती अब्दुल कय्यूम ने सारी बातें विवरण सहित लिखी हैं कि कैसे क्राइम ब्रांच के एसीपी जीएल सिंघल ने 17 अगस्त, 2003 को अहमदाबाद से उन्हें अगवा किया, फिर मारपीट करने और एन्काउंटर का ड्रामा करके उनसे जबरन इक़बालिया बयान लेकर इस केस में फंसाया. साथ ही क्राइम ब्रांच वालों ने किस प्रकार उन दो पत्रों की नक़ल मुफ्ती अब्दुल कय्यूम से कराई, जिनके बारे में अदालत को बताया गया कि ये अक्षरधाम हमले में मारे गए फिदायीन की जेब से मिले थे. आश्चर्य की बात तो यह है कि फिदायीन के जो कपड़े अदालत में पेश किए गए, वे ख़ून से लथपथ थे, लेकिन जेब से मिले दोनों पत्रों पर ख़ून का एक भी धब्बा नहीं था.

अब आइए देखते हैं कि जस्टिस एके पटनायक एवं जस्टिस वी गोपाल गोडा की सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने 16 मई, 2014 को अक्षरधाम मामले में अपना फ़ैसला सुनाते हुए क्या कहा था. अदालत ने कहा था कि फ़ैसला सुनाने से पहले, देश की अखंडता एवं सुरक्षा को ख़तरे में डाल देने वाले इतने गंभीर मामले की जांच में एजेंसियों ने जिस अक्षमता का सुबूत दिया है, हम उस पर अपनी नाराज़गी का इज़हार करना भी आवश्यक समझते हैं. इतनी अमूल्य ज़िंदगियों को मौत के घाट उतार देने वाले वास्तविक दोषियों को पकड़ने के बजाय पुलिस ने निर्दोष लोगों को पकड़ लिया और उन पर गंभीर आरोप लगा दिए, जिसके नतीजे में उन्हें आरोपी करार देकर कड़ी सज़ाओं का पात्र बना दिया गया. लिहाज़ा, हम विशेष पोटा अदालत के 2003 के मुक़दमा नंबर 16, दिनांक 01–07–2006 के फ़ैसले और आदेश को ख़ारिज करते हैं और अहमदाबाद स्थित हाईकोर्ट ऑफ गुजरात के दिनांक 01–06–2010 को दिए गए उन फ़ैसलों और आदेशों को ख़ारिज करते हैं, जो 2006 के क्रिमिनल कंफरमेशन केस नंबर 2, 2006 की क्रिमिनल अपील नंबर 1675 और 2006 की आपराधिक अपील नंबर 1328 के बाबत हैं. लिहाज़ा, हम सभी अपीलकर्ताओं को उन पर लगाए गए सभी आरोपों से बाइज्जत बरी करते हैं.

इस फ़ैसले के आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये फर्ज़ी आतंकवादी थे, तो असली आतंकवादी कहां हैं? क्या यह हमारे देश की निचली

शिवराज पाटिल की भूमिका

चौथी दुनिया से फोन पर एक लंबी बातचीत के दौरान जमीअत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बताया कि शिवराज पाटिल ने अपने दौर में साबित करना चाहा कि धार्मिक दृष्टिकोण से मुसलमान आतंकवादी हैं. हो सकता है कि इससे पहले भी लोग आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किए गए हों, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह साबित करना कि मुसलमान आतंकवादी हैं, इसकी शुरुआत शिवराज पाटिल के ज़माने से हुई. मैंने यह बात सोनिया गांधी को भी लिखकर भेजी थी कि आपके गृहमंत्री ने ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे लगता है कि पूरी मुस्लिम बिरादरी आतंकवादी है, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की सोच ऐसी नहीं है. जहां कहीं भी बम धमाका होता था, बिना किसी जांच के तुरंत ही गृह मंत्रालय से घोषणा हो जाती थी कि लश्कर–ए–तैयबा वालों ने यह सब किया है, हुजी (हिजबुल मुजाहिदीन) वालों लाजपत नगर एवं अन्य जगहों पर होने वाले बम धमाके हों या फिर बटला हाउस एन्काउंटर का मामला हो, ये सारी घटनाएं देश में उसी समय हुई थीं, जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी और शिवराज पाटिल गृहमंत्री थे.

राहुल गांधी चाहते, तो समस्या हल हो जाती

2006 में जब मौलाना अरशद मदनी जमीअत उलेमा हिंद के अध्यक्ष चुने गए, तो आतंकवाद के आरोपों में गिरफ्तार किए गए मुस्लिम युवकों के कुछ रिश्तेदारों ने उनसे मुलाकात करके इस ओर उनका ध्यान दिलाया. यह वह ज़माना था, जब बड़ी संख्या में मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया जा रहा था. जमीअत उलेमा हिंद ने महसूस किया कि पहले सांप्रदायिक दंगे में लोगों के घर जला दिए जाते थे, कुछ लोगों को मार दिया दिया जाता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद लोग मरने वालों को भूल जाते थे और दु:ख कम हो जाता था. पर अब जिस तरह और जितनी संख्या में मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि पूरी बिरादरी को आतंकवादी साबित करने का प्रयास किया जा रहा है. अपनी इसी चिंता के चलते जमीअत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने उस समय मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, पी. चिदंबरम, अहमद पटेल और के रहमान ख़ान जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका.

उसके बाद 2009 में राजस्थान के गोपालगढ़ में हुए सांप्रदायिक दंगे के समय मौलाना अरशद मदनी की मुलाक़ात राहुल गांधी से हुई. उल्लेखनीय है कि उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे. मौलाना ने राहुल गांधी से उस दंगे के संबंध में कहा कि मुसलमानों पर इतने अत्याचार हुए हैं, आपको इसकी सीबीआई जांच करानी चाहिए. राहुल गांधी ने उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से फोन पर बात की, जिस पर उन्होंने गोपालगढ़ मामले की सीबीआई जांच कराने की घोषणा कर दी. 2011 में मौलाना अरशद मदनी ने दोबारा राहुल गांधी से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की और आतंकवाद के नाम पर देश भर में हो रही मुसलमानों की गिरफ्तारियों पर उनके सामने अपनी चिंता व्यक्त की. इस पर राहुल गांधी ने मौलाना से पूछा कि क्या आपके पास कोई लिस्ट है, जिससे यह पता चल सके कि कितने मुसलमान आतंकवाद के आरोप में अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं?

मौलाना ने कहा कि हमारे पास उन लोगों की सूची तो है, जिनके मुक़दमे जमीअत उलेमा हिंद लड़ रही है, पूरे भारत की सूची नहीं है. यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सूची सरकार (उस समय कांग्रेस) के पास होनी चाहिए थी, वह सूची राहुल गांधी मौलाना अरशद मदनी से मांग रहे थे. ख़ैर, मौलाना ने राहुल गांधी से कहा कि वह एक सप्ताह या दस दिनों के अंदर सूची उन्हें ज़रूर दे देंगे. वहां से वापस आने के बाद मौलाना ने कई मुस्लिम संगठनों और जेलों में बंद निर्दोषों के मुक़दमे लड़ने का दावा करने वाले विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों (एनजीओज़) से संपर्क किया और उनसे निवेदन किया कि अगर उनके पास आतंकवाद के आरोप में बंद किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी है, तो वे उन्हें मुहैया कराएं. लेकिन अफ़सोस! किसी ने भी ऐसा कोई विवरण जमीअत उलेमा हिंद को उपलब्ध नहीं कराया.

अंत में विवश होकर जमीअत उलेमा हिंद ने अपने कार्यालय में एक बैठक बुलाकर यह निर्णय लिया कि उर्दू अख़बारों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर आतंकवाद के आरोप में फंसे लोगों की जानकारी इकट्ठा की जाए. यह विज्ञापन कुछ हिंदी अख़बारों में भी प्रकाशित हुआ, जिस पर जमीअत उलेमा हिंद के लगभग 15 लाख रुपये ख़र्च हुए. उसका नतीजा यह हुआ कि लगभग 15 दिनों के अंदर ही जमीअत उलेमा हिंद के पास ऐसे एक हज़ार से अधिक लोगों की सूची नाम, पता, मोबाइल नंबर, वकील का नाम एवं अन्य विवरण के साथ तैयार हो गई. इस सूची में एक नाम ऐसा भी था, जो पिछले 18 वर्षों से जेल के अंदर बंद था और अब भी है. मामला अदालत के सामने विचाराधीन होने के कारण हम उसका नाम ज़ाहिर नहीं कर सकते. इसी तरह कुछ लोग पिछले 15 वर्षों, 12 वर्षों, 10 वर्षों और पांच वर्षों से आतंकवाद के आरोप में जेलों में बंद थे. दो–तीन वर्ष पहले गिरफ्तार हुए लोगों की संख्या तो सबसे अधिक थी.

ख़ैर, उसके बाद मौलाना अरशद मदनी उस सूची को लेकर एक बार फिर राहुल गांधी के पास गए. राहुल गांधी ने सूची देखकर काफी हैरानी जताई कि जो काम गृह मंत्रालय नहीं कर सका, उसे आपने कैसे अंजाम दिया? बहरहाल, राहुल गांधी ने तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से फोन पर बात करके उन्हें उस सूची से संबंधित जानकारी दी. जितेंद्र सिंह ने उस समय मौलाना अरशद मदनी से अपने कार्यालय में इंटेलिजेंस ब्यूरो एवं अन्य जांच एजेंसियों के अधिकारियों की उपस्थिति में बातचीत की. उक्त सभी अधिकारियों ने मौलाना अरशद मदनी से पूछा कि आपकी नज़र में इसका हल क्या है? जवाब में मौलाना अरशद मदनी ने दो महत्वपूर्ण हल बताए. पहली बात तो उन्होंने यह कही कि आतंकवाद जैसे गंभीर मामले में भारतीय मुसलमानों की किस्मत का फ़ैसला करने का पूर्ण अधिकार पुलिस को न दिया जाए, बल्कि केंद्रीय स्तर पर एक ऐसी समिति गठित की जाए, जिसमें साफ़–सुथरी छवि के क़ानूनविद्, सेवानिवृत्त जज एवं अन्य प्रसिद्ध हस्तियां शामिल हों. आतंकवाद के आरोप में जब भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करे, तो उसके ख़िलाफ़ एकत्र किए गए सभी सुबूतों और अन्य विवरण पर आधारित फाइल वह पहले इस समिति को भेजे. फिर समिति उस फाइल का अध्ययन करने के बाद, अगर उसमें सच्चाई है, तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के ख़िलाफ़ आगे की क़ानूनी कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दे, वरना पुलिस को केस आगे बढ़ाने से मना कर दे.

दूसरा हल मौलाना अरशद मदनी ने गृह मंत्रालय के उन अधिकारियों को यह बताया कि आम तौर पर ऐसा देखा जाता है कि जब भी किसी को आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, तो पुलिस उसके ख़िलाफ़ सैकड़ों की संख्या में फर्ज़ी गवाहों के नाम दे देती है और जब अदालत में उन्हें पेश करने का समय आता है, तो पुलिस कोई न कोई बहाना कर देती है. इस प्रकार गवाह के हाज़िर न होने की वजह से तारीख़ पर तारीख़ पड़ती रहती है और फ़ैसला आने में काफी देर हो जाती है. मौलाना ने उन अधिकारियों से कहा कि एक वर्ष, दो वर्ष या फिर तीन वर्ष की अवधि तय की जाए और फिर पुलिस से कहा जाए कि वह इस अवधि के अंदर सभी गवाहों को अदालत में पेश करे. अगर पुलिस तय अवधि के अंदर गवाहों को अदालत में पेश करने में नाकाम रहती है, तो आरोपी को उसका फ़ायदा देते हुए ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए, भले ही उसके ख़िलाफ़ मुक़दमे की सुनवाई अदालतों में ज़िंदगी भर चलती रहे.

तीसरा मशविरा उन्होंने ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने का दिया, ताकि आतंकवाद से संबंधित मामलों का निबटारा शीघ्र से शीघ्र हो सके. जो लोग दोषी पाए जाएं, उन्हें उम्रक़ैद या फांसी हो सके और जो निर्दोष हों, उन्हें शीघ्र से शीघ्र रिहा किया जा सके. इस पर राहुल गांधी ने कहा कि हर राज्य में चूंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन संभव नहीं है. इसके जवाब में मौलाना ने उनसे कहा कि कांग्रेस इसकी शुरुआत उन राज्यों से तो कर ही सकती है, जहां पर उसकी सरकार है. लेकिन, उसके कुछ दिनों के बाद ही जितेंद्र सिंह को खेल मंत्रालय भेज दिया गया. राहुल गांधी या कांग्रेस अगर मुसलमानों को लेकर वाकई गंभीर होते, तो वह इस संबंध में कोई अच्छी पहल कर सकते थे, क्योंकि उस समय केंद्र में उनकी सरकार थी. लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. मौलाना अरशद मदनी ने उसके बाद यही सारी बातें पत्र द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी कहीं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं तत्कालीन अल्पसंख्यक मंत्री के रहमान ख़ान से भी कहीं और सबने उन्हें इन मशविरों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया, लेकिन व्यवहारिक रूप से किया कुछ भी नहीं. ■

feedback@chauthiduniya.com

अदालतों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए सोचने का विषय नहीं है कि सिस्टम में कहां चूक हो रही है, जिसके कारण असली आतंकवादियों की जगह फर्ज़ी आतंकवादी गिरफ्तार किए जा रहे हैं? अगर असली आतंकवादी अब भी ज़िंदा हैं और हमारे देश के ख़िलाफ़ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो क्या यह हम सबके लिए ख़तरे की घंटी नहीं है? आख़िर उन्हें कब पकड़ा जाएगा? अपनी अक्षमता छिपाने के लिए पुलिस और इंटेलिजेंस के लोग कब तक चोर–पुलिस का खेल खेलते रहेंगे? उनकी जवाबदेही आख़िर कब तय होगी? जब हम उन फर्ज़ी आतंकवादियों की असली कहानी सुनते हैं, तो विश्वास नहीं होता कि हमारा सिस्टम इतना बेरहम भी हो सकता है. अंग्रेज़ों ने पुलिस से भारतीयों को डराने और उनके ऊपर अत्याचार करने का काम लिया था, लेकिन अब तो हमारा देश आज़ाद है, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, तो फिर पुलिस अपने ही नागरिकों पर इतने अत्याचार क्यों कर रही है?

चौथी दुनिया ने 9 से 15 मार्च के अंक में घोटालों का कार्पोरेशन नाम से एक स्टोरी प्रकाशित की थी, जिसके जवाब में एनटीपीसी ने अपना पक्ष भेजा है, जिसे हम हूबहू प्रकाशित कर रहे हैं.

एनटीपीसी NTPC

एन टी पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
NTPC Limited
(A Govt. of India Enterprise)
केन्द्रीय कार्यालय/Corporate Centre

NTPC response to the Article "Ghotalon Ka Corporation", published in the weekly edition , 9th March-15th March, 2015 of 'Chauthi Duniya'.

NTPC has denied all the allegations, published in the said Article and clarifies that the allegations contained in the Article are far from the truth, baseless and without any proof. NTPC clarifies that till date not even an inch of land has been transferred to the Hinduja Group by NTPC and no agreement in this regard has been signed between the parties till date.

NTPC strongly refutes the allegations that CMD-NTPC has sold off reserved land in the Simhadri Scheme in Vishakha district of Andhra Pradesh to the Hinduja Group in a resolution passed during the Board meeting.

So far as the other allegations published in the same article of Chauthi Duniya against CMD, NTPC relating to the period during which CMD, NTPC was the CMD of NBCC are concerned, all such allegations if true would have gone into by the Government before he was selected as CMD, NTPC while issuing CBI and CVC clearance to him and hence there is no truth in such allegations.

In future, we expect such issues would not be published in your paper without checking with us.

(S. N. Ganguly)
Executive Director (Corp.Communication)

एन टी पी सी भवन स्कोप कामप्लेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, टेल/Tel.: 24360100, फैक्स/Fax : 011-24361018
NTPC Bhawan, SCOPE Comple, 7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003, वेबसाइट/Website : www.ntpc.co.in

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

सहकारी चीनी मिलों को तबाह करने में कई ऐसे राजनेता शामिल हैं, जो चुनाव के समय सहकारी उपक्रमों को मज़बूत बनाने की बात करते हैं. चौथी दुनिया का यह संवाददाता जब मराठवाड़ा में था, तो उस समय सूबे की सहकारी चीनी मिलों के लिए चुनाव होने वाले थे. विलासराव देशमुख, गोपीनाथ मुंडे और शरद पवार समेत कई नेताओं के पोस्टर इस दौरान देखने को मिले. विलासराव देशमुख और गोपीनाथ मुंडे का देहांत हो चुका है, लेकिन सहकारी चीनी मिलों पर अब उनके परिवारीजन क़ब्ज़ा जमाना चाहते हैं.

मराठवाड़ा

सहकारी चीनी मिलों को दफ़नाने की साज़िश

महाराष्ट्र में सहकारिता क्षेत्र के उद्योगों की हालत अच्छी नहीं है. मराठवाड़ा समेत सूबे की कई चीनी मिलें बंद हैं और इनकी संख्या हर साल बढ़ती जा रही है. केंद्रीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मंत्रालय ने कुछ महीने पहले राज्य में क़रीब सौ नई चीनी मिलें स्थापित करने संबंधी मंजूरी दी है. इनमें अधिकांश चीनी मिलें निजी क्षेत्र के स्वामित्व में होंगी, जबकि सहकारी क्षेत्र के हिस्से में आधा दर्जन से भी कम चीनी मिलें आएंगी. अव्वल यह कि निजी चीनी मिल स्थापित करने के लिए आईं तमाम अर्जियों के आवेदकों में ऐसे राजनेताओं की संख्या अधिक है, जो कभी सहकारी आंदोलन के ज़रिये सियासत में क़ामयाब हुए. महाराष्ट्र में सहकारी चीनी मिलों को ख़त्म करने के पीछे क्या मक़सद है और इसमें राजनेता किस तरह शामिल हैं, पढ़िए चौथी दुनिया की इस ख़ास रिपोर्ट में...

अभिषेक रंजन सिंह

सहकारिता आंदोलन के सहारे महाराष्ट्र की राजनीति में अपना दख़ल क़ायम करने वाले राजनेताओं को सूबे में मौजूद सहकारी चीनी मिलें अब रास नहीं आ रही हैं. यही वजह है कि निजी चीनी मिलों के प्रति बड़े राजनीतिक घरानों की दिलचस्पी बढ़ गई है. दरअसल, पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार को क़रीब 100 नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम हासिल हुआ है. इनमें आधा दर्जन से भी कम सहकारी चीनी मिलें स्थापित होंगी. बाकी सभी चीनी मिलें निजी स्वामित्व की होंगी.

सहकारिता से जुड़े नेताओं की मानें, तो यह फ़ैसला सहकारी चीनी मिलों को कमज़ोर करने की साज़िश है. उनके मुताबिक़, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी निजी क्षेत्र की चीनी मिलों का वर्चस्व हो जाएगा. लातूर से प्रकाशित एक मराठी दैनिक अख़बार से जुड़े पत्रकार अनिल समुद्रे बताते हैं कि सहकारी चीनी मिलों के लिए यह ख़तरे की घंटी है, क्योंकि नई चीनी मिलें उनके गन्ना क्षेत्र में सेंध लगाएंगी. इस समय महाराष्ट्र में 224 चीनी मिलें हैं, जिनमें सहकारी चीनी मिलों की संख्या 173 है, जबकि 51 चीनी मिलें निजी क्षेत्र की हैं. इनमें 66 चीनी मिलें बंद पड़ी हैं. बंद होने वाली चीनी मिलों में सहकारी चीनी मिलों की संख्या अधिक है. मराठवाड़ा और विदर्भ में सूखे की वजह से भी कई चीनी मिलें बंद हुई हैं, लेकिन सूखे की आड़ में सहकारी चीनी मिलों के साथ एक बड़ी साज़िश हो रही है. ग़ौरतलब है कि नई चीनी मिल स्थापित करने के लिए सरकार ने वर्ष 2006 में नई नीति लागू की थी. इससे पहले 1998 में सरकार ने चीनी मिलों के लिए लाइसेंस की बाध्यता हटा दी थी, लेकिन गन्ना नियंत्रण अधिनियम के तहत दो चीनी मिलों के बीच 15 किलोमीटर की दूरी का प्रावधान है. इसी आदेश के तहत गन्ना जोन रिजर्व भी किया जाता है. दरअसल, सहकारी चीनी मिलों के सामने कई चुनौतियां हैं. मसलन, इन चीनी मिलों की ज़्यादातर मशीनें पुरानी हो चुकी हैं और उनकी कार्यक्षमता भी बेहतर नहीं है. ऐसे में निजी क्षेत्र की आधुनिक मशीनों के सामने उनका टिकना मुश्किल है. उस्मानाबाद में एक सहकारी चीनी मिल में कार्यरत अशोक तावड़े ने बताया कि सहकारी चीनी मिलों की स्थिति अच्छी हो सकती है, लेकिन यहां के राजनेताओं की रुचि इनमें नहीं रह गई है, क्योंकि वे ख़ुद निजी चीनी मिलों की वक़ालत कर रहे हैं.

सहकारी चीनी मिलों को तबाह करने में कई ऐसे राजनेता शामिल हैं, जो चुनाव के समय सहकारी उपक्रमों को मज़बूत बनाने की बात करते हैं. चौथी दुनिया का यह संवाददाता जब मराठवाड़ा में था, तो उस समय सूबे की सहकारी चीनी मिलों के लिए चुनाव होने वाले थे. विलासराव देशमुख, गोपीनाथ मुंडे और शरद पवार समेत कई नेताओं के पोस्टर इस दौरान देखने को मिले. विलासराव देशमुख और गोपीनाथ मुंडे का देहांत हो चुका है, लेकिन सहकारी चीनी मिलों पर अब उनके परिवारीजन क़ब्ज़ा जमाना चाहते हैं. लातूर के ज़िलाधिकारी पांडुरंग पोले ने चौथी दुनिया से ख़ास बातचीत में बताया कि महाराष्ट्र में सहकारी और निजी दो तरह की चीनी मिलें हैं. सहकारी चीनी मिलों को शासन की ओर से समय-समय पर मदद दी जाती है. यह पूछे जाने पर कि सहकारी चीनी मिलें और बैंकों की हालत सूबे में काफ़ी ख़राब है, इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? तो उन्होंने कहा कि पचास और साठ के दशक की राजनीति में सहकारिता के लिए कई अच्छे काम किए गए, जिनका परिणाम यह हुआ कि राज्य में बड़े पैमाने पर चीनी और कपास की फैक्ट्रियां लगाई गईं.

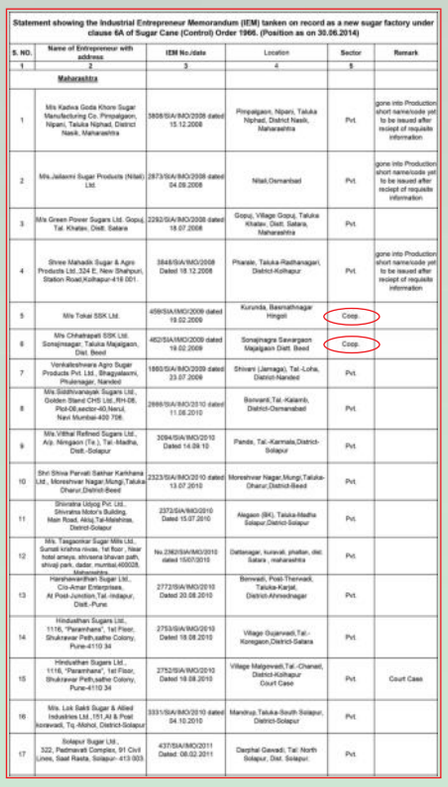

Statement showing the Industrial Entrepreneur Memorandum (IEM) tanken on record as a new sugar factory under clause 6A of Sugar Cane (Control) Order 1966. (Position as on 30.06.2014)

S. NO.	Name of Entrepreneur with address	IEM No./date	Location	Sector	Remark
1	2	3	4	5	
	Maharashtra				
1	M/s Kadwa Goda Khore Sugar Manufacturing Co. Pimpalgaon, Nipani, Taluka Niphad, District Nasik, Maharashtra	3808/SIA/IMO/2008 dated 15.12.2008	Pimpalgaon, Nipani, Taluka Niphad, District Nasik, Maharashtra	Pvt.	gone into Production short name/code yet to be issued after reciept of requisite information
2	M/s Jaliaxmi Sugar Products (Nitali) Ltd.	2873/SIA/IMO/2008 dated 04.09.2008	Nitali,Osmanbad	Pvt.	gone into Production short name/code yet to be issued after reciept of requisite information
3	M/s Green Power Sugars Ltd. Gopuj, Tal. Khatav, Distt. Satara	2292/SIA/IMO/2008 dated 18.07.2008	Gopuj, Village Gopuj, Taluka Khatav, Distt. Satara, Maharashtra	Pvt.	
4	Shree Mahadik Sugar & Agro Products Ltd. 324 E, New Shahpuri, Station Road,Kolhapur-416 001.	3848/SIA/IMO/2008 Dated 18.12.2008	Pharale, Taluka-Radhanagari, District-Kolhapur	Pvt.	gone into Production short name/code yet to be issued after reciept of requisite information
5	M/s Tokai SSK Ltd.	459/SIA/IMO/2009 dated 19.02.2009	Kurunda, Basmathnagar Hingoli	Coop.	
6	M/s Chhatrapati SSK Ltd. Sonajinagar, Taluka Majalgaon, Dist. Beed	462/SIA/IMO/2009 dated 19.02.2009	Sonajinagra Sawargaon Majalgaon Distt. Beed	Coop.	
7	Venkateshwara Agro Sugar Products Pvt. Ltd., Bhagyalaxmi, Phulenagar, Nanded	1860/SIA/IMO/2009 dated 23.07.2009	Shivani (Jamaga), Tal.-Loha, District-Nanded	Pvt.	
8	M/s Siddhivanayak Sugars Ltd., Golden Stand CHS Ltd.,RH-08, Plot-08,sector-40,Nerul, Navi Mumbai-400 706.	2666/SIA/IMO/2010 dated 11.08.2010	Bonvanti,Tal.-Kalamb, District-Osmanabad	Pvt.	
9	M/s.Vitthal Refined Sugars Ltd., A/p. Nimgaon (Te.), Tal.-Madha, Distt.-Solapur	3094/SIA/IMO/2010 Dated 14.09.10	Pande, Tal.-Karmala,District-Solapur	Pvt.	
10	Shri Shiva Parvati Sakhar Karkhana Ltd., Moreshwar Nagar,Mungi,Taluka Dharur,District-Beed	2323/SIA/IMO/2010 dated 13.07.2010	Moreshwar Nagar,Mungi,Taluka-Dharur,District-Beed	Pvt.	
11	Shivratna Udyog Pvt. Ltd., Shivratna Motor's Building, Main Road, Akluj,Tal-Malshiras, District-Solapur	2372/SIA/IMO/2010 Dated 15.07.2010	Alegaon (BK), Taluka-Madha Solapur,District-Solapur	Pvt.	
12	M/s. Tasgaonkar Sugar Mills Ltd., Sumati krishna nivas, 1st floor, Near hotel ameya, shivsena bhavan path, shivaji park, dadar, mumbai,400028, Maharashtra	No.2362/SIA/IMO/2010 dated 15/07/2010	Dattanagar, kuravali, phaltan, dist. Satara, maharashtra	Pvt.	
13	Harshawardhan Sugar Ltd., C/o-Amar Enterprises, At Post-Junction,Tal.-Indapur, Distt.-Pune	2772/SIA/IMO/2010 Dated 20.08.2010	Benwadi, Post-Therwadi, Taluka-Karjat, District-Ahmednagar	Pvt.	
14	Hindusthan Sugars Ltd., 1116, "Paramhans", 1st Floor, Shukrawar Peth,sathe Colony, Pune-4110 34	2753/SIA/IMO/2010 Dated 18.08.2010	Village Gujarwadi,Tal.-Koregaon,District-Satara	Pvt.	
15	Hindusthan Sugars Ltd., 1116, "Paramhans", 1st Floor, Shukrawar Peth,sathe Colony, Pune-4110 34	2752/SIA/IMO/2010 Dated 18.08.2010	Village Malgewadi,Tal.-Chandgad, District-Kolhapur Court Case	Pvt.	Court Case
16	M/s. Lok Sakti Sugar & Allied Industries Ltd.,151,At & Post Korawadi, Tq.-Mohol, District-Solapur	3331/SIA/IMO/2010 dated 04.10.2010	Mandrup,Taluka-South Solapur, District-Solapur	Pvt.	
17	Solapur Sugar Ltd., 322, Padmavati Complex, 91 Civil Lines, Saat Rasta, Solapur- 413 003	437/SIA/IMO/2011 Dated: 08.02.2011	Darphal Gawadi, Tal. North Solapur, Dist. Solapur	Pvt.	

पिछले बीस वर्षों के दौरान सहकारी क्षेत्र की कई चीनी मिलें और कपास आधारित उद्योग बंद हो गए. मराठवाड़ा क्षेत्र में चीनी मिलों की संख्या अधिक है, जबकि कपास की खेती भी यहां बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन धागा बनाने की एक भी फैक्ट्री इस इलाक़े में नहीं है. यहां सिर्फ़ कपास की गांठ बनाने के उद्योग हैं. हालांकि, सूखे की वजह से इस इलाक़े में कपास की खेती बुरी तरह प्रभावित हुई है, इसलिए गांठ बनाने वाली फैक्ट्रियां भी बंद पड़ी हैं. राष्ट्रीय स्तर पर कपास उत्पादन में महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है. सूबे में क़रीब 1,100 कॉटन जीनिंग-प्रोसेसिंग कारख़ाने हैं. निर्यात पर पाबंदी और मराठवाड़ा में भयंकर सूखे की वजह से पिछले साल राज्य में महज़ 500 कारख़ाने ही चालू हुए. बीड ज़िले की गेवराई तहसील में कभी कपास बेचने वाले किसानों की कतार लगी रहती थी, लेकिन गत वर्ष बाज़ार समिति में वीरानी छाई रही. औरंगाबाद मराठवाड़ा का प्रमंडलीय ज़िला है. यहां ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा, बीज, स्टील, कॉटन, पेपर मिल और शराब के कई कारख़ाने हैं. हालांकि, ये सभी कल-कारख़ाने निजी क्षेत्र के हैं. औरंगाबाद में कपास आधारित कई सहकारी उद्योग भी थे, लेकिन हाल के वर्षों में वे सभी बंद हो गए. मराठवाड़ा की ग़रीबी और पिछड़ेपन को दूर करने में राज्य की पिछली कई सरकारें नाक़ाम रही हैं. मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोगों को निराशा है, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे राज्य के लोगों को उनसे कोई उम्मीद बंध सके. कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस सरकार ने कुछ वर्ष पहले एक नई वस्त्रोद्योग नीति बनाई थी, जिसमें दावा किया गया था कि आगामी पांच वर्षों के दौरान सूबे में 40 हज़ार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. तत्कालीन सरकार का दावा था कि इस योजना से कम से कम 11 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा. दरअसल, उन दिनों कांग्रेस गठबंधन सरकार सिंचाई समेत कई घोटालों में फंस चुकी थी, इसलिए नई वस्त्रोद्योग नीति सरकारी फाइलों तक ही सीमित रह गई और उसका कोई लाभ राज्य की जनता को नहीं मिला.■

arsingh@chauthiduniya.com

सहकारी और निजी चीनी मिलों की स्थिति

ज़िला	मिलों की संख्या	सहकारी मिल	निजी मिल	चालू	बंद
औरंगाबाद	09	06	03	05	04
जालना	05	03	02	05	00
बीड	10	08	02	06	04
परभणी	06	00	06	05	01
हिंगोली	03	03	00	03	00
नांदेड़	08	06	02	05	03
उस्मानाबाद	16	08	08	10	06
लातूर	12	08	04	04	08

चीनी उत्पादन में मराठवाड़ा क्षेत्र का योगदान

ज़िला	फ़ीसद
उस्मानाबाद	4.92
लातूर	4.84
बीड	3.23
नांदेड़	2.50
औरंगाबाद	2.25
परभणी	2.01
जालना	1.71
हिंगोली	1.20

(वर्ष 2013-14 के आंकड़ों के मुताबिक़)

केंद्र सरकार निजी चीनी मिलों पर मेहरबान है

केंद्रीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मंत्रालय ने महाराष्ट्र में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के उपखंड (6-ए) के तहत इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम (आईईएम) दर्ज किए. 30 जून, 2014 और 30 सितंबर, 2014 के इन मेमोरेंडम पर निगाह डालें, तो महाराष्ट्र के विभिन्न ज़िलों में 77 नई चीनी मिलें स्थापित करने को मंजूरी दी गई है. 30 जून, 2014 के मेमोरेंडम में महाराष्ट्र में 64 नई चीनी मिलों का ज़िक्र है. दिलचस्प यह है कि स्थापित होने वाली इन नई चीनी मिलों में 60 निजी स्वामित्व वाली होंगी, जबकि महज़ चार चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र की होंगी. 30 सितंबर, 2014 के मेमोरेंडम में 13 नई चीनी मिलों का वर्णन है. इस मेमोरेंडम में सहकारी क्षेत्र की पूरी तरह उपेक्षा की गई है, क्योंकि स्थापित होने वाली सभी 13 नई चीनी मिलें निजी स्वामित्व वाली होंगी.

सहकारी चीनी मिलों पर राजनेताओं का क़ब्ज़ा

महाराष्ट्र की सहकारी संस्थाएं ओछी राजनीति के दलदल में फंस चुकी हैं. महाराष्ट्र में शरद पवार, विलासराव देशमुख, नितिन गडकरी और गोपीनाथ मुंडे जैसे राजनेता सहकारिता के ज़रिये अपनी राजनीति चमकाने वालों में शुमार हैं. एक वक्त ऐसा था, जब सहकारिता के कारण महाराष्ट्र के किसानों को नई दिशा मिली थी और उनके लिए तरक्की की राह प्रशस्त हो सकी थी. भ्रष्टाचार के कारण बड़ी जोत वाले किसानों का दबदबा सहकारी चीनी मिलों पर बढ़ता चला गया और छोटे किसान उनसे दूर होते चले गए. इन सहकारी चीनी मिलों में होने वाले चुनाव में धनवान और शक्तिशाली किसान अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जैसे पदों को हथियाने लगे. महाराष्ट्र में कोई भी ऐसी सहकारी संस्था नहीं है, जिस पर राजनीति एवं राजनीतिज्ञों का वर्चस्व न हो. आंकड़ों पर नज़र डालें, तो महाराष्ट्र की पांच फ़ीसद चीनी मिलों पर भारतीय जनता पार्टी, साठ फ़ीसद पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और पैंतीस फ़ीसद चीनी मिलों पर कांग्रेस से जुड़े नेताओं का क़ब्ज़ा है.

विधान परिषद की चौबीस सीटों के निर्वाचन का ताप महीनों से महसूस किया जाता रहा है. यह ताप पहले ज़िलों तक ही सीमित था, पर पिछले एक–डेढ़ महीने से राजधानी के राजनीतिक हलकों को सरगर्म कर रहा है. राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले हो रहे इस चुनाव को कई हलकों में सत्ता के सेमी फाइनल की संज्ञा दी जाने लगी है और यह अनायास भी नहीं है. राज्य की सत्ता और पक्ष–विपक्ष के घटक बगैर कुछ कहे इसे सेमी फाइनल के तौर पर ले रहे हैं तथा अपने प्रतिद्वंद्वियों को घेरने की तैयारी उसी शैली में कर रहे हैं. जनता परिवार के दोनों घटक जद(यू) एवं राजद के साथ–साथ भाजपा विरोध के नाम पर कांग्रेस एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गठबंधन के तहत ही परिषद चुनाव में उम्मीदवारों के समर्थन की घोषणा करना चाहती हैं.

बिहार विधान परिषद चुनाव

प्रत्याशियों की नहीं, सुप्रीमो की अग्नि परीक्षा

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

बिहार के राजनीतिक हलकों में लाख टके का सवाल है कि विधान परिषद चुनाव में क्या होगा? इसका उत्तर बहुत कठिन नहीं है. वे दिन कब के गुज़र गए, जब विधान परिषद की उम्मीदवारी राजनीति के लिए उपयोगी सार्वजनिक व्यक्तित्वों को दी जाती थी. और तो और, साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, वैज्ञानिक, शिक्षाविद् या समाजसेवियों के लिए सुरक्षित सीटों, जिनके लिए मनोनयन राज्यपाल करते हैं, पर भी उन लोगों को मनोनीत कर दिया जाता है, जिनका इन गुणों से छत्तीस का नाता होता है और जिनके संबंध काली दुनिया से होते हैं.

बिहार में विधान परिषद के चुनाव, कुछ अपवादों को छोड़कर, आम तौर पर उत्तेजनाविहीन ही गुज़रते रहे हैं, लेकिन इस बार परिषद के स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव उत्तेजना के सारे कीर्तिमान तोड़ने को बेताब हैं. परिषद के इस क्षेत्र की सभी चौबीस सीटों के चुनाव की अधिसूचना अगले कुछ दिनों में जारी हो जाएगी और फिर डेढ़–पौने दो महीने यानी जुलाई के पहले हफ्ते तक ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे. विधान परिषद के जिन चौबीस निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव होने हैं, उनमें से तीन सीटों यानी दरभंगा, समस्तीपुर और मुंगेर–जमुई–लखीसराय–शेखपुरा पर राष्ट्रीय जनता दल काबिज है. भारतीय जनता पार्टी के ज़िम्मे कटिहार, पूर्णिया–अररिया–किशनगंज, सीतामढ़ी–शिवहर, बेगूसराय–खगड़िया एवं सीवान हैं. इसके अलावा दो सीटों पटना और आरा–बक्सर पर निर्दलीय काबिज हैं. शेष चौदह सीटें सत्तारूढ़ जनता दल (यू) के ज़िम्मे हैं. निर्दलीय विधान पार्षदों में एक जद (यू) के बाहुबली विधायक सुनील पांडेय के भाई हुलास पांडेय हैं, जिन्हें अपने भाई से कमतर नहीं माना जा रहा है. दूसरे वाल्मीकि सिंह हैं. ये दोनों सत्तारूढ़ दल के साथ हैं. यानी जनता परिवार की 19 सीटें दांव पर हैं. कांग्रेस की कोई सीट नहीं है. एनडीए के ग़ैर भाजपा घटक दलों यानी लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के पास भी कोई सीट नहीं है. वामपंथी दलों की हालत भी कांग्रेस से बेहतर नहीं है.

विधान परिषद की इन चौबीस सीटों के निर्वाचन का ताप महीनों से महसूस किया जाता रहा है. यह ताप पहले ज़िलों तक ही सीमित था, पर पिछले एक–डेढ़ महीने से राजधानी के राजनीतिक हलकों को सरगर्म कर रहा है. राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले हो रहे इस चुनाव को कई हलकों में सत्ता के सेमी फाइनल की संज्ञा दी जाने लगी है और यह अनायास भी नहीं है. राज्य की सत्ता और पक्ष–विपक्ष के घटक बगैर कुछ कहे इसे सेमी फाइनल के तौर पर ले रहे हैं तथा अपने प्रतिद्वंद्वियों को घेरने की तैयारी उसी शैली में कर रहे हैं. जनता परिवार के दोनों घटक जद(यू) एवं राजद के साथ–साथ भाजपा विरोध के नाम पर कांग्रेस एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गठबंधन के तहत ही परिषद चुनाव में उम्मीदवारों के समर्थन की घोषणा करना चाहती हैं. राजग में भी इसी तर्ज पर परिषद चुनाव में उतरने का दबाव है. दोनों खेमों में विभिन्न स्तरों पर बातचीत कई चरणों में हो चुकी है. भाजपा विरोधी राजनीति मजबूत बनाने के ख्याल से सत्तारूढ़ जद (यू) अपनी कुछ सीटें त्यागने तक के लिए तैयार हो गया है. इस खेमे में जो फॉर्मूला आकार ले रहा है, उसके अनुसार जद (यू) और राजद दस–दस सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जबकि चार सीटें कांग्रेस और वामपंथी दलों के लिए रखी जाएंगी. इसका विकल्प भी पेश किया गया है, जिसमें कहा गया कि जद (यू) एवं राजद नौ–नौ सीटों पर लड़ें और बाकी छह सीटें कांग्रेस एवं अन्य सहयोगी दलों को दे दी जाएं. चूंकि इस भाजपा विरोधी राजनीतिक ध्रुव में सबसे अधिक सीटें जद (यू) के पास ही हैं, लिहाजा उसे अपनी सीटें छोड़नी पड़ सकती हैं.

जद (यू) के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपनी कुछ सीटें छोड़ने का संकेत भी दिया है. कांग्रेस चार सीटें मांग रही है, जबकि भाकपा भी दो से कम पर राजी होने को तैयार नहीं है. हालांकि, जनता परिवार वामपंथी समूह को अपने साथ रखने को तैयार है, पर भाकपा (माले) के इस गठबंधन से बाहर ही रहने की संभावना है. उसने दस सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर रखी है. दूसरी ओर, राजग में भी लोजपा छह सीटें मांग रही है. उसका कहना है कि 2009 में तीन जगहों यानी हाजीपुर, सहरसा–सुपौल–मधेपुरा और नालंदा से उसके समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई थी. लिहाजा इन तीनों के अलावा तीन और सीटें उसे चाहिए. रालोसपा की फिलहाल विधान परिषद में कोई उपस्थिति नहीं है, पर वह भी इस सदन में अपनी उपस्थिति चाहती है और चार सीटें मांग रही है. राजग में इस मसले पर किसी फॉर्मूले को लेकर सहमति जैसा माहौल अभी तक नहीं बना है, लेकिन माना जा रहा है कि भाजपा अपने सहयोगी दलों को निराश नहीं करेगी. विधान परिषद चुनाव में भाजपा द्वारा (राजग भी कह सकते हैं) अपनी ताकत बढ़ाने और जनता परिवार द्वारा (भाजपा विरोधी राजनीतिक समूह कहना ज़्यादा बेहतर होगा) अपनी ताकत बचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है. विधान परिषद में अभी जद (यू) ही सबसे बड़ी पार्टी है. राजद, कांग्रेस और भाकपा सहित उसे समर्थन देने वालों को जोड़ लिया जाए, तो 75 सदस्यीय विधान परिषद में उसकी ताकत दो तिहाई से अधिक हो जाती है. भाजपा के सदस्यों की संख्या उसकी तुलना में काफी कम है. राजग के अन्य दलों की बात ही बेमानी है.

बिहार के राजनीतिक हलकों में लाख टके का सवाल है कि विधान परिषद चुनाव में क्या होगा? इसका उत्तर बहुत कठिन नहीं है. वे दिन कब के गुज़र गए, जब विधान परिषद की उम्मीदवारी राजनीति के लिए उपयोगी सार्वजनिक व्यक्तित्वों को दी जाती थी. और तो और, साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, वैज्ञानिक, शिक्षाविद् या समाजसेवियों के लिए सुरक्षित सीटों, जिनके लिए मनोनयन राज्यपाल करते हैं, पर भी उन लोगों को मनोनीत कर दिया जाता है, जिनका इन गुणों से छत्तीस का नाता होता है और जिनके संबंध काली दुनिया से होते हैं. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से ज़रूर अब तक शिक्षक चुने जाते रहे हैं, पर स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों (जिसके मतदाता पंचायत और नगर निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं) के चुनाव, कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो मुख्यत: पैसों की बदौलत लड़े और जीते जाते हैं. इस बार स्थानीय निकाय के इन चौबीस निर्वाचन क्षेत्रों में भी, कुछ अपवादों को छोड़कर, आम तौर पर यही तस्वीर बन रही है. चुनाव आयोग के पास क्या और कैसी रिपोर्ट है, नहीं पता, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि चुनावी दिग्गजों ने मतपत्रों की खरीददारी का काम काफी हद तक पूरा कर लिया है. इन चौबीस निर्वाचन क्षेत्रों में एक वोट की क़ीमत पांच हज़ार से लेकर दस हज़ार रुपये तक चल रही है. वोट के थोक व्यापारी के कमीशन की रकम अलग है. वोट की व्यवस्था (खरीददारी) का काम पिछले कई महीनों से चल रहा है और मतदाताओं को मतदान पूर्व की किस्त का भुगतान भी कर दिए जाने की ख़बर है. पटना के सत्ता गलियारे की चर्चा पर भरोसा करें, तो इस बार विधान परिषद के चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा दस–दस करोड़ रुपये तक खर्च किए जाने की संभावना है. सम्मानित राजनीतिक दल का समर्थन ही पहली समस्या है. इसके लिए दावेदार ढाई से साढ़े तीन करोड़ रुपये तक खर्च करने को तैयार बताए जाते हैं. राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी है कि राजनीतिक दल इस चंदे का उपयोग विधानसभा चुनाव में करना चाहते हैं. यह भी कोष जुगाड़ तकनीक का एक स्वरूप है. चूंकि पंचायत–नगर निकाय प्रतिनिधि निचले स्तर पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं के क़रीब और स्थानीय जोड़–तोड़ के जानकार होते हैं, लिहाजा दल के समर्थन से ज़मीनी स्तर पर उम्मीदवारों को कार्यकर्ता सहज उपलब्ध हो जाते हैं.

इस धनवादी माहौल में परिषद चुनाव में किसी राजनीतिक शुचिता की उम्मीद निरर्थक है. जो सत्ता में हैं, वे पंचायत एवं स्थानीय निकाय प्राधिकारों को पिछले वर्षों दी गई सुविधाओं और उन्हें अधिकार संपन्न करने के अपने उपायों की निरंतर चर्चा कर रहे हैं. नीतीश कुमार की पिछली सरकारों ने इन संस्थाओं में महिलाओं एवं अति पिछड़ों को आरक्षण दिया था. उनकी मौजूदा सरकार ने पिछले दिनों इन प्रतिनिधियों का भत्ता एवं मानदेय बढ़ाने का फ़ैसला लिया है. हालांकि, इन फ़ैसलों के कारण राज्य के खजाने पर प्रति वर्ष दो–ढाई सौ करोड़ रुपये का खर्च बढ़ गया है. इसके अलावा विकास योजनाओं में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सांसद–विधायक योजना की तर्ज पर रकम तय की गई है. इस पंचायती राज एवं नगर निकाय यानी ग्राम सरकार एवं नगर सरकार को सशक्त बनाने के लिए और भी कई घोषणाएं की गई हैं. एक फ्रंट पर यह सरकार अब भी पिछड़ती दिख रही है और वह यह है कि सरपंचों एवं पंचों को विधान परिषद के इस निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मतदान का अधिकार दिलाने के संबंध में अब तक कोई ठोस क़दम नहीं उठाया गया है. कई क्षेत्रों में पंचायतों एवं नगर निकायों को पर्याप्त अधिकार देने के संबंध में सरकार के रवैये को भाजपा मुद्दा बना रही है. भाजपा नेताओं ने बार–बार कहा है कि बिहार में उनकी सरकार बनेगी, तो पंचायत प्रतिनिधियों के लिए सुख–सुविधाओं में आशातीत बढ़ोतरी की जाएगी, साथ ही पंचायतों एवं नगर निकाय प्राधिकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाया जाएगा और उनका विकास कोष बढ़ाया जाएगा. लेकिन, दावों और वादों से क्या होता है? वस्तुत: होता तो वही है, जो धनबली–बाहुबली चाहता है. धनबली–बाहुबली क्या चाहता है, उसकी क्या और कैसी तैयारी है, इसे जानने के लिए अभी प्रतीक्षा करनी होगी.■

धरती के साथ हिला दिल और दिमाग

वाल्मीकि कुमार

पिछले 25 अप्रैल को नेपाल के काठमांडू से शुरू हुए भूकंप की विनाश लीला थमने का नाम नहीं ले रही है. भूकंप का केंद्र नेपाल में होने के कारण भारत के सीमावर्ती ज़िलों में इसका व्यापक प्रभाव रहा. लगातार दो दिनों तक उत्तर बिहार के सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण समेत अन्य ज़िलों में त्राहिमाम की स्थिति बनी रही. अभी उस प्राकृतिक आपदा की पीड़ा लोग भूल भी नहीं पाए थे कि बीते 12 मई को आए भूकंप के तेज झटकों ने लोगों के होश उड़ा दिए. तक़रीबन सौ से ज़्यादा लोगों की मौत केवल उत्तर बिहार में हुई है. सरकारी एवं प्रशासनिक स्तर पर पीड़ितों के सहायता की जा रही है, लेकिन लगातार आ रहे झटकों के चलते लोगों का दिल–दिमाग हिल गया है.

प्राकृतिक आपदा किसी भी क्षण दुनिया की दिशा बदल सकती है. अब तक़रीबन सभी को इस बात पर पूरा भरोसा हो गया है. वर्ष 1934 के भीषण भूकंप के बाद 2015 में आए इस जोरदार झटके ने लोगों को भयभीत कर दिया है. प्राकृतिक असंतुलन का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है. जान–माल के नुक़सान के साथ ही मानसिक अशांति का सामना करना लोगों की विवशता हो गई है. भूकंप का कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चाहे जो हो, लेकिन प्राकृतिक संपदा की उपेक्षा एवं क्षति भी इसकी एक बड़ी वजह है. वन संपदा की कमी ने प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ कर रख दिया है. पेड़ों की धड़ल्ले से कटाई ने वन संपदा नष्ट कर दी है. नदी–नालों की दशा दयनीय हो गई है. आलम यह है कि अब लोग नदी के गर्भ में भी भवन निर्माण से परहेज नहीं कर रहे हैं. शासन–प्रशासन स्तर पर भी इस बाबत चिंतनीय उदासीनता है. नतीजतन, खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है.

भूकंप की दहशत का आलम यह है कि लोग अपने घरों में रहने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं. बच्चे स्कूल जाने से कतरा रहे हैं. अस्पतालों में भर्ती मरीज डर के मारे भाग खड़े हुए. सरकारी एवं ग़ैर सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग हर पल आशंकित रहते हैं. भूकंप के चलते रहना, खाना, सोना काफी मुश्किल हो रहा है. शहरी क्षेत्रों में परेशानी की एक और बड़ी वजह इमारतों पर लगे मोबाइल टॉवर हैं. कोई जब भूकंप के बाद घर से खुले मैदान में भागना चाहता है, तब उस वक्त उसे लगता है कि सिर पर तलवार लटक रही है. दूसरी तरफ़ बिजली के खंभे पर झूलते तार और भी डरा देते हैं. दिल के मरीजों को खासी परेशानी हो रही है. भूकंप के चलते दिल का दौरा पड़ने से अब तक दो दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. लोग इमारतों पर लगे मोबाइल टॉवर हटाने की मांग कई बार प्रशासन से कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई.■

महंत ज्ञान दास ने कहा कि वह चाहते हैं कि रामलला विराजमान स्थल पर गर्भगृह रखते हुए भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और उससे थोड़ी ही दूरी पर मस्जिद भी बन जाए. दास ने कहा कि पक्षकारों से उनकी कई चरणों में बात हो चुकी है. विवाद से जुड़े ज़्यादातर पक्षकार अधिग्रहीत परिसर के पास स्थित मस्जिद को वृहद रूप देकर उसका विस्तार कम से कम एक एकड़ में करने के पक्षधर हैं. उन्होंने कहा कि मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो, ताकि देश में अमन–चैन कायम रहे. इस बीच बाबरी मस्जिद के वयोवृद्ध पक्षकार मोहम्मद हाशिम अंसारी ने कहा कि वह मामले के सौहार्दपूर्ण हल के लिए ज्ञान दास के मत से सहमत हैं.

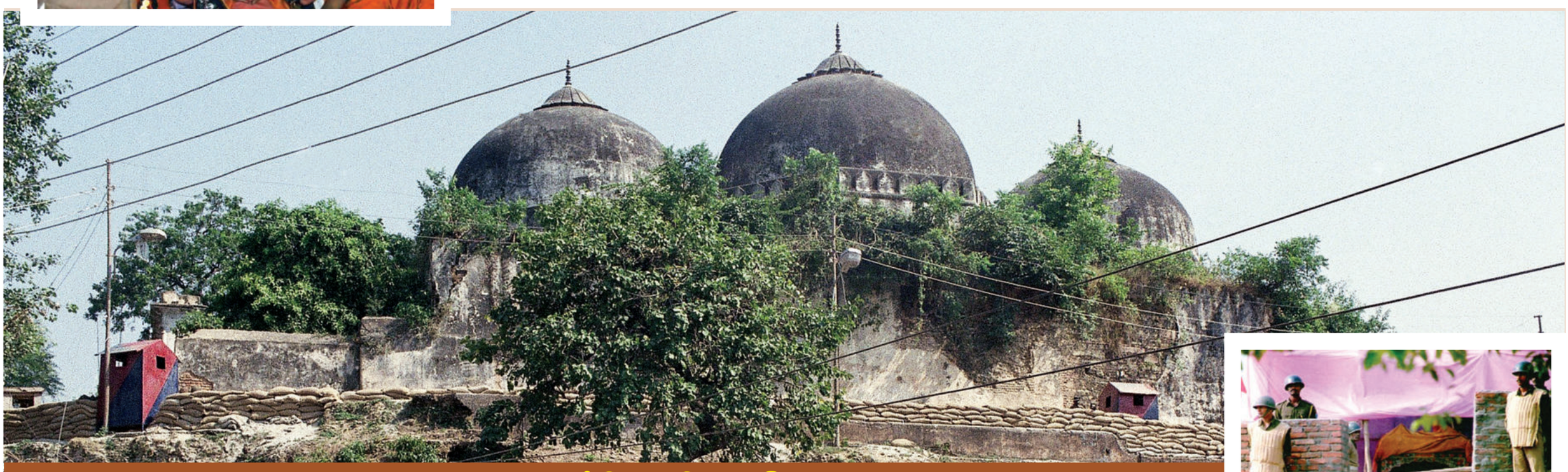

राम मंदिर निर्माण का मसला

अब राज्यसभा में बहुमत न होने की आड़

राजनाथ सिंह से जब यह पूछा गया कि यदि भाजपा को राज्यसभा में बहुमत हासिल हो जाए, तो क्या वह राम मंदिर के लिए प्रस्ताव लाएगी? इस पर उन्होंने कहा, यह काल्पनिक सवाल है. केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के पास संसद के ऊपरी सदन में 45 सदस्य हैं और मौजूदा कार्यकाल में उसे राज्यसभा में बहुमत हासिल होने की कोई संभावना नहीं है. 243 सदस्यीय सदन में विपक्ष के पास कम से कम 132 सदस्य हैं. राजनाथ का इशारा था कि अगले लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा को राज्यसभा में भी बहुमत मिल जाए, तो सारे मसले हल हो जाएंगे. राजनाथ सिंह ने कहा, अयोध्या में राम जन्मभूमि से जुड़ा विवाद निपटाने के लिए दो रास्ते हैं. पहला यह कि अदालत के ज़रिये इस मुद्दे का फ़ैसला हो और दूसरा रास्ता यह है कि संसद इसके लिए क़ानून बनाए.

प्रभात रंजन दीन

अयोध्या जाकर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया कि राम मंदिर निर्माण के लिए क़ानून बनाने की लोकतांत्रिक शक्ति भाजपा के पास नहीं है, लिहाजा राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार करना होगा. इस तरह केंद्र की सत्ता पर आसीन भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर मुद्दे पर अपनी विवशता तो जता दी, लेकिन अगले लोकसभा चुनाव की सियासत की भूमिका भी रख दी. राजनाथ सिंह ने कहा, भाजपा के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, इसलिए इस मुद्दे पर इस बार भाजपा सरकार कुछ नहीं कर सकती. यानी लोकसभा का एक चुनाव और. गृहमंत्री ने यह ज़रूर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रामलला के दर्शन करने ज़रूर आएंगे. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संसद के शीर्ष सदन राज्यसभा में बहुमत की कमी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में बाधा है. इस वजह से भाजपा न कोई प्रस्ताव ला सकती है और न कोई क़ानून. लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के घोषणा–पत्र में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी शामिल था और जम्मू–कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 समाप्त करने एवं समान नागरिक संहिता जैसे मसले भी शामिल थे. लेकिन, उक्त सारे मसले भाजपा के केंद्र की सत्ता में आने के बाद भी अनछुए रह गए, क्योंकि राज्यसभा में भाजपा को बहुमत हासिल नहीं है. राजनाथ सिंह अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष संत नृत्यगोपाल दास के बुलावे पर आए थे. उन्होंने दीनबंधु नेत्र चिकित्सालय में ओपीडी एवं चिकित्सक आवास निर्माण के लिए आयोजित भूमि पूजन–शिलान्यास समारोह में भी हिस्सा लिया और महंत नृत्यगोपाल दास समेत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत ज्ञान दास एवं महंत संतराम दास से बातचीत की. राजनाथ ने राम जन्मभूमि और हनुमान गढ़ी के दर्शन भी किए.

राजनाथ सिंह से जब यह पूछा गया कि यदि भाजपा को राज्यसभा में बहुमत हासिल हो जाए, तो क्या वह राम मंदिर के लिए प्रस्ताव लाएगी? इस पर उन्होंने कहा, यह काल्पनिक सवाल है. केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के पास संसद के ऊपरी सदन में 45 सदस्य हैं और मौजूदा कार्यकाल में उसे राज्यसभा में बहुमत हासिल होने की कोई संभावना नहीं है. 243 सदस्यीय सदन में विपक्ष के पास कम से कम 132 सदस्य हैं. राजनाथ का इशारा था कि अगले लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा को राज्यसभा में भी बहुमत मिल जाए, तो सारे मसले हल हो जाएंगे. राजनाथ सिंह ने कहा, अयोध्या में राम जन्मभूमि से जुड़ा विवाद निपटाने के लिए दो रास्ते हैं. पहला यह कि अदालत के ज़रिये इस मुद्दे का फ़ैसला हो और दूसरा रास्ता यह है कि संसद इसके लिए क़ानून बनाए. लेकिन, दूसरे रास्ते में अड़चन यह है कि राज्यसभा में भाजपा के पास बहुमत का अभाव है. अब सुप्रीम कोर्ट को ही तय करना है कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा या नहीं. राजनाथ के इस बयान पर संघ एवं विहिप से जुड़े लोग मुंह बना रहे थे और भाजपा के प्रति निराशा जता रहे थे. लेकिन, वे संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान भूल गए, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अयोध्या में क़ानून एवं संविधान के माध्यम से राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि अदालत के फ़ैसले पर संघ की प्रतिक्रिया भी क़ानून, संविधान एवं लोकतांत्रिक सीमाओं में ही होगी. संघ प्रमुख का विचार था कि अयोध्या मुद्दे का सही समाधान केवल संसद में क़ानून बनाकर ही हो सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

मंदिर–मस्जिद: शह–मात का खेल

अयोध्या में मंदिर और मस्जिद का मसला राजनीतिक दलों से लेकर धार्मिक संगठनों एवं क़ानूनी पक्षकारों, सबके बीच शह–मात का खेल बन गया है. मसले का समाधान तलाशने के बहाने सब अपनी–अपनी गोटियां आगे–पीछे करने में ही लगे हैं. कभी विश्व हिंदू परिषद को किनारे लगाने की कोशिश होती है, तो कभी विहिप सबको पीछे करके मुलायम के कंधे के ज़रिये श्रेय हासिल करने की कोशिश करने लगती है. पिछले दिनों भी ऐसा ही एक फॉर्मूला सामने आया और 70 एकड़ के विवादित परिसर में मंदिर एवं मस्जिद दोनों बन गए और सौ फीट की ऊंची दीवार से बांट भी दिए गए. अयोध्या प्रकरण के मूल वादी हाशिम अंसारी खुद चलकर हनुमान अखाड़ा आ गए और अखाड़ा परिषद के मुखिया महंत ज्ञान दास से मुलाकात कर उन्होंने यह फॉर्मूला निकाल लिया. फिर हाशिम अंसारी एवं महंत ज्ञान दास, दोनों ने कहा कि समाधान की बातचीत में विश्व हिंदू परिषद को किसी भी रूप में शामिल नहीं किया जाएगा. महंत ज्ञान दास ने उस समय कहा भी कि उन्होंने इस प्रस्ताव को लेकर लगभग सारे हिंदू प्रतिष्ठानों एवं मुख्य आध्यात्मिक गुरुओं से चर्चा की है, लेकिन इसमें विश्व हिंदू परिषद शामिल नहीं है. महंत बोले, हम ऐसे किसी भी कार्य के पक्ष में नहीं हैं, जिससे हमारे मुस्लिम भाइयों को लगे कि वे हार गए हैं. हमें मुट्ठी भर विहिप नेताओं की कोई परवाह नहीं है. महंत ज्ञान दास और हाशिम अंसारी के बयान को भी राजनीतिक प्रेक्षकों ने स्पष्ट रूप से राजनीति प्रेरित बताया था. उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद इस प्रकरण से जुड़े पक्ष अदालत से बाहर समझौते के रास्ते पर माथापच्ची करते रहे हैं. अदालत को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं है. अयोध्या का मसला 1950 से ही विवाद में फंसा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मसले पर 30 सितंबर, 2010 को अपना फ़ैसला सुनाया था. उस फ़ैसले में हाईकोर्ट ने विवादित स्थल को भगवान राम का जन्मस्थल बताया था और विवादित परिसर का दो–तिहाई हिस्सा हिंदू पक्षकारों को देकर बाकी एक–तिहाई हिस्सा मुस्लिम पक्षकारों को दे दिया था. इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया.■

दोनों पक्ष चाहते हैं मंदिर–मस्जिद दोनों बनें

सुलह–समझौते से अयोध्या के मंदिर–मस्जिद विवाद के निपटारे में जुटे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं हनुमान गढ़ी के महंत ज्ञान दास ने कहा कि वह राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं, लेकिन खून के गारे से नहीं. दास ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह उनके पास आए थे. वह भी आपसी सहमति या न्यायालय के आदेश से ही मंदिर निर्माण के पक्षधर हैं. राजनाथ सिंह को बता दिया गया है कि उनका (दास का) इस मसले के हल के लिए सुलह–समझौते का प्रयास चल रहा है. वह पक्षकारों के लगातार संपर्क में हैं. ज्ञान दास का दावा है कि मोहम्मद हाशिम अंसारी समेत ज़्यादातर पक्षकारों का समर्थन उनके साथ है. इसलिए वह इस मसले के शांतिपूर्ण हल के लिए निश्चिंत हैं. ज्ञान दास ने कहा, हम चाहते हैं कि मंदिर का निर्माण दूध के गारे से हो. यह कभी नहीं चाहेंगे कि मंदिर का निर्माण खून के गारे से हो.

महंत ज्ञान दास ने कहा कि वह चाहते हैं कि रामलला विराजमान स्थल पर गर्भगृह रखते हुए भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और उससे थोड़ी ही दूरी पर मस्जिद भी बन जाए. दास ने कहा कि पक्षकारों से उनकी कई चरणों में बात हो चुकी है. विवाद से जुड़े ज़्यादातर पक्षकार अधिग्रहीत परिसर के पास स्थित मस्जिद को वृहद रूप देकर उसका विस्तार कम से कम एक एकड़ में करने के पक्षधर हैं. उन्होंने कहा कि मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो, ताकि देश में अमन–चैन कायम रहे. इस बीच बाबरी मस्जिद के वयोवृद्ध पक्षकार मोहम्मद हाशिम अंसारी ने कहा कि वह मामले के सौहार्दपूर्ण हल के लिए ज्ञान दास के मत से सहमत हैं. अंसारी ने कहा कि यदि मसले के हल में सभी पक्षों के अधिकारों का ध्यान रखकर शांतिपूर्ण हल निकलता है, तो वह दास के साथ हैं. ग़ौरतलब है कि इस मसले के शांतिपूर्ण हल के लिए अंसारी और ज्ञान दास के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं. इसके पहले भी अंसारी एवं महंत ज्ञान दास मिलकर राम मंदिर और मस्जिद के निर्माण का फॉर्मूला सुझा कर सुर्ख़ियों में आ चुके हैं. ■

भाजपा गुमराह कर रही है: महंत नरेंद्र

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी ने तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि राम मंदिर मुद्दे पर भाजपा लोगों को गुमराह कर रही है. महंत नरेंद्र ने कहा कि राम मंदिर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ़ नहीं है और पार्टी संतों के साथ जनता को भी गुमराह कर रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा पहले लोकसभा में राम मंदिर बिल पास कराए और फिर कहे कि राज्यसभा में उसके पास बहुमत नहीं है. उन्होंने कहा कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह का यह कहना कि राम मंदिर के लिए क़ानून इसलिए नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि भाजपा के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, यह सोचे–समझे इरादे से गुमराह करने के लिए दिया गया बयान है. ■

विहिप ने मुलायम से मदद मांगी थी

वर्ष 2013 में अयोध्या की बहुचर्चित चौरासी कोसी परिक्रमा के दरम्यान विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव से मिलकर राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग मांगा था. विहिप नेता अशोक सिंघल ने मुलायम सिंह यादव से मध्यस्थता करने का अनुरोध किया था. विश्व हिंदू परिषद ने मुलायम सिंह यादव को राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ़ करने के लिए हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने का प्रस्ताव दिया था. बताया गया था कि मुलायम सिंह ने भी उस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन समय के अंतराल के साथ ही विहिप की यह पहल भी बेमानी की कवायद साबित हुई. उस समय विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल एवं स्वामी चिन्मयानंद ने मुलायम के साथ–साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी. मुलाकात के बाद विहिप नेताओं ने कहा था, हमने मुलायम सिंह को उनकी घोषणा के बारे में याद दिलाया कि जिस दिन अदालत कह देगी कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी दूसरे ढांचे को गिराकर किया गया था, वह मंदिर के निर्माण का समर्थन करेंगे. अशोक सिंघल ने कहा था कि दूसरे सभी नेताओं के मुकाबले मुसलमानों में मुलायम की स्वीकार्यता सबसे ज़्यादा है और उन्हें मध्यस्थता करने और इस प्रक्रिया की शुरुआत के लिए पहल करनी चाहिए, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था. विहिप से जुड़े एक सक्रिय नेता ने कहा कि भाजपा और संघ की नाराज़गी के कारण विहिप की यह पहल ठोस शक्ल नहीं ले सकी.■

विस्थापितों के पुनर्वास और मुआवज़ा संबंधी ज़मीनी सच्चाई जानने के लिए गठित उक्त छह सदस्यीय दल में भारतीय किसान सभा के महामंत्री एवं आठ बार सांसद रह चुके हन्नान मोल्लाह, राष्ट्रीय भारतीय महिला महासंघ की महासचिव एनी राजा, केरल के पूर्व वन मंत्री एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बिनोय विस्वम, अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त जल विशेषज्ञ राज कचरू, भूतपूर्व विधायक एवं समाजवादी समागम के मार्गदर्शक डॉ. सुनीलम और ऊर्जा एवं पर्यावरण विशेषज्ञ सौम्य दत्ता शामिल थे. अपने दो दिवसीय दौरे में सत्य शोधक दल ने धार ज़िले के खलघाट-गाजीपुर बस्ती, धरमपुरी नगर, एकल्वारा, चिखल्दा एवं निसरपुर, बडवानी ज़िले के भीलखेड़ा, राजघाट, पिपरी एवं खर्या भादल आदि गांवों का दौरा किया.

सरदार सरोवर प्रभावित क्षेत्र

पुनर्वास के खोखले दावे

चौथी दुनिया ब्यूरो

नर्मदा घाटी में सरदार सरोवर बांध से विस्थापितों का पूर्ण पुनर्वास (जैसा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है) और विस्थापितों के पुनर्वास एवं मुआवज़े की गुणवत्ता-वस्तुस्थिति समझने के लिए एक केंद्रीय सत्य शोधन दल (फैक्ट फाइंडिंग टीम) ने बीते दिनों नर्मदा घाटी के तीन ज़िलों के लगभग 10 गांवों में दौरा किया. उक्त दल ने मध्य प्रदेश एवं गुजरात की राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के उस दावे कि शत-प्रतिशत प्रभावित लोगों को पुनर्वास हो चुका है, की पड़ताल की. बेक वाटर लेवल, जिसके आधार पर सरकार ने लोगों का विस्थापन तय किया है और दावा किया है कि बांध की ऊंचाई बढ़ने से कोई अतिरिक्त डूब नहीं आएगी, उसकी भी जांच की गई. नर्मदा घाटी के लोगों से मिली शिकायत कि हज़ारों लोग अभी भी पुनर्वास से वंचित हैं, सरकारी दावे पर सवाल खड़े करते हैं.

विस्थापितों के पुनर्वास और मुआवज़ा संबंधी ज़मीनी सच्चाई जानने के लिए गठित उक्त छह सदस्यीय दल में भारतीय किसान सभा के महामंत्री एवं आठ बार सांसद रह चुके हन्नान मोल्लाह, राष्ट्रीय भारतीय महिला महासंघ की महासचिव एनी राजा, केरल के पूर्व वन मंत्री एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बिनोय विस्वम, अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त जल विशेषज्ञ राज कचरू, भूतपूर्व विधायक एवं समाजवादी समागम के मार्गदर्शक डॉ. सुनीलम और ऊर्जा एवं पर्यावरण विशेषज्ञ सौम्य दत्ता शामिल थे. अपने दो दिवसीय दौरे में सत्य शोधक दल ने धार ज़िले के खलघाट-गाजीपुर बस्ती, धरमपुरी नगर, एकल्वारा, चिखल्दा एवं निसरपुर, बडवानी ज़िले के भीलखेड़ा, राजघाट, पिपरी एवं खर्या भादल आदि गांवों का दौरा किया. इसके अलावा अलीराजपुर ज़िले के ककराना, सुगट एवं झंडाना, महाराष्ट्र के भादल, दुधिया, चिमाल्खेदी, झापी, फलाई एवं डनेल आदि गांवों के आदिवासियों और गुजरात के धरमपुरी वसाहत के प्रतिनिधियों ने दल के सामने अपने बयान दिए. दल ने बडवानी के वर्तमान विधायक रमेश पटेल और ज़िला अध्यक्ष से भी मुलाकात कर सच्चाई जानी.

> पुनर्वास नीति एवं पुनर्वास पर उच्चतम न्यायालय और नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के आदेश का उल्लंघन बड़े पैमाने पर चल रहा है, जो आगे चलकर विस्फोटक स्थिति पैदा कर सकता है. दल का कहना है कि वसाहट स्थलों की हालत दयनीय है, वहां सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं. साथ ही विद्यालय एवं स्वास्थ्य केंद्र का भी अभाव है, जिसके चलते विस्थापित लोग वहां रहने से इंकार कर रहे हैं.

प्रभावित लोगों के बयान, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों और विभिन्न क्षेत्रों में मौक़े पर जाकर जायजा लेने के बाद दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हज़ारों प्रभावित परिवार अभी भी मुआवज़े एवं पुनर्वास से वंचित हैं और सरकारें वर्षों से उनकी इस समस्या के प्रति उदासीन है. सैकड़ों परिवार, जिनके घर डूब क्षेत्र में आने वाले हैं, वे प्रभावितों के सरकारी आंकड़े से अभी भी बाहर हैं. सौम्य दत्ता के मुताबिक, सरदार सरोवर बांध की 122 मीटर की वर्तमान ऊंचाई पर भी ऐसे बहुत सारे परिवार प्रभावित हो रहे हैं, जो सरकारी आकलन से बाहर हैं. बांध की ऊंचाई 17 मीटर और बढ़ाने के केंद्र सरकार के फ़ैसले से निमाड़ का समतल क्षेत्रफल डूब क्षेत्र में आ जाएगा, जिससे एक बड़ी तबाही की शुरुआत हो सकती है. हज़ारों एकड़ उपजाऊ ज़मीन डूब क्षेत्र में चली जाएगी और खाद्य सुरक्षा के स्थानीय प्रबंधन को हानि पहुंचाएगी.

दल का कहना है कि पुनर्वास नीति एवं पुनर्वास पर उच्चतम न्यायालय और नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के आदेश का उल्लंघन बड़े पैमाने पर चल रहा है, जो आगे चलकर विस्फोटक स्थिति पैदा कर सकता है. दल का कहना है कि वसाहट स्थलों की हालत दयनीय है, वहां सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं. साथ ही विद्यालय एवं स्वास्थ्य केंद्र का भी अभाव है, जिसके चलते विस्थापित लोग वहां रहने से इंकार कर रहे हैं. पुनर्वास की अनिवार्य मांग ज़मीन के बदले ज़मीन है, जिसे पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ज़मीन को चिन्हित और उपलब्ध कराना सरकार की ज़िम्मेदारी है. लेकिन, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस दिशा में कोई प्रयास होता नहीं दिख रहा है और उसकी यह उदासीनता पुनर्वास में सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आ रही है. दल के अनुसार, कई लोगों ने यह बताया कि ज़मीन फर्जी तरीके से अपात्रों को दे दी गई. यही नहीं, कई विस्थापितों के मुआवज़े की धनराशि का एक बड़ा हिस्सा सरकारी अधिकारी और दलाल हजम कर गए.

दल के अनुसार, भारतीय संविधान द्वारा आदिवासियों के लिए बनाए गए विशेष प्रावधानों का सरकार खुल्लमखुल्ला उल्लंघन कर रही है. पुनर्वास के लिए गुजरात में डबोही नगर पंचायत के पास दी गई वसाहट की ज़मीन अब विस्थापितों से वापस ली जा रही है. आजीविका आधारित पुनर्वास के उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है. महाराष्ट्र की तरह मछुआरों को मछली मारने का अधिकार देने में मध्य प्रदेश सरकार नाकाम रही है. दल के सदस्य एवं जल विशेषज्ञ राज कचरू ने बताया कि बेक-वाटर से प्रभावित क्षेत्र सरकारी आकलन से काफी ज़्यादा है और बांध की ऊंचाई पूरी होने के बाद मानसून में घाटी में बाढ़ के कारण अप्रत्याशित क्षति होगी, जिसे सरकार मानने को तैयार नहीं है. ग़ौरतलब है कि 2012 और 2013 में बाढ़ का पानी कई गांवों में सरकारी अनुमानों को ध्वस्त कर चुका है. बावजूद इसके, सरकार सही तरीके से आकलन के लिए तैयार नहीं है. सत्य शोधन दल के अनुसार, इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारों एवं प्राधिकरणों को सौंपी जाएगी और देश की जनता के सामने सारी सच्चाई लाई जाएगी. इस संदर्भ में विभिन्न राजनीतिक दलों, किसान संगठनों एवं सामाजिक संगठनों ने दल को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

केंद्र की नीतियों से उत्तराखंड बेहाल

राजकुमार शर्मा

दिल्ली में मोदी सरकार का एक वर्ष पूरा होने का जश्न मनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन पिछले क़रीब 11 महीने से मोदी सरकार ने उत्तराखंड के शहरी विकास की रफ्तार थाम दी है. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की शहरी विकास संबंधी महत्वाकांक्षी योजनाएं बंद करने और उनके बदले नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा के बावजूद पुरानी योजनाओं को लेकर अस्पष्टता बनी हुई है. केंद्र सरकार न तो नई योजनाओं की गाइड लाइन के बारे में बताने को तैयार है और न पुरानी योजनाओं के लिए धन जारी कर रही है, जिससे सूबे में शहरी विकास की योजनाओं की रफ्तार थम-सी गई है. जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन (जेएनएनयूआरएम) और राजीव आवास योजना के बदले नई योजनाएं शुरू करने में हो रही देरी ने शहरी विकास की कई योजनाओं में अडंगा लगा दिया है. मोदी सरकार ने इन योजनाओं को लेकर जारी अनिश्चितता को लेकर कोई भरोसा नहीं दिया है और न इनके लिए कोई धनराशि जारी की. पिछले 11 महीने से शहरी विकास विभाग केंद्र से धनराशि मिलने का इंतज़ार कर रहा है. केंद्र के इस अनिर्णय वाले रवैये से राजधानी देहरादून की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, हरिद्वार की प्रस्तावित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना और विभिन्न शहरों में ग़रीबों के लिए आवास एवं बुनियादी सुविधाओं की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं. शहरी विकास सचिव डीएस गर्ब्याल का कहना है कि पैसा न मिल पाना तो दिक्कत है ही, सबसे बड़ी परेशानी यह है कि केंद्र सरकार ने जेएनएनयूआरएम एवं आरएवाई को लेकर अब तक कोई दिशा निर्देश नहीं दिए हैं, जबकि इन योजनाओं को वह दूसरी योजनाओं से स्थानापन्न करना चाहती है.

जेएनएनयूआरएम के तहत प्रदेश के तीन शहरों में 14 परियोजनाओं के लिए 425 करोड़ 54 लाख रुपये मंजूर किए गए थे, जिनमें से केवल चार परियोजनाओं का काम शत-प्रतिशत पूरा हो सका है. चार परियोजनाओं में 90 फ़ीसद, दो परियोजनाओं में 75 फ़ीसद और चार परियोजनाओं में 30 से 40 फ़ीसद काम हो चुका है. प्रदेश सरकार को इन परियोजनाओं के लिए केंद्र से क़रीब 70 करोड़ की तीसरी एवं चौथी किस्त अभी तक नहीं मिली है. यही नहीं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल-एनजीटी) में इंदिरा नगर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मसला उठने के बाद से उसका काम रोक दिया गया है. राजीव आवास योजना भी नई परिस्थितियों में दिशा निर्देश की अस्पष्टता के चलते ठप्प पड़ी है. गर्ब्याल का कहना है कि प्रदेश सरकार ने देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी एवं अल्मोड़ा को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की पहल की है, लेकिन बिना गाइड लाइन की इस केंद्रीय योजना को लेकर अब तक कुछ भी ठोस नहीं हो सका है. मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र पोषित योजनाओं के फंडिंग पैटर्न में बदलाव से प्रदेश को हो रहे नुक़सान की रिपोर्ट नियोजन विभाग से तलब की है. नियोजन विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि केंद्र पोषित योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता में किया जा रहा बदलाव चिंता का विषय है. इसके लिए सभी प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केंद्र के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि पांच वर्षों के लिए स्वीकृत योजनाओं की सहायता राशि में अचानक बदलाव करना राज्यों के प्रति नाइंसाफी है, इसके लिए सभी राज्यों को एक होकर अपनी बात रखनी चाहिए. उन्होंने प्रमुख सचिव नियोजन को इस संबंध में पूरा विवरण तथ्यों सहित प्रस्तुत करने को कहा. बीजापुर अतिथि गृह में मुख्य सचिव सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शिक्षा, नियोजन एवं कृषि से संबंधित योजनाओं पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उत्तर-पूर्व के राज्य हों या मध्य हिमालयी राज्य, सभी की अपनी-अपनी ज़रूरतें हैं. उन्होंने इस असमानता के लिए प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री को भी फिर से पत्र भेजने की बात कही. उन्होंने कहा कि फंडिंग पैटर्न बदलने से अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति, पेयजल सहित अन्य सामाजिक योजनाओं पर काफी प्रभाव पड़ेगा. ग़ौरतलब है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें मानते हुए केंद्र ने आठ केंद्रीय योजनाओं की फंडिंग में केंद्रीय मदद बंद कर दी है और 24 योजनाओं का फंडिंग अनुपात बदल दिया है. केंद्र से मिलने वाली ब्लॉक ग्रांट (एकमुश्त अनुदान) यानी एनसीए, एसपीए एवं एससीए ख़त्म करने की वजह से राज्य को हर साल 2,589 करोड़ रुपये का नुक़सान हो रहा है. 14वें वित्त आयोग से मिली अतिरिक्त धनराशि जोड़ने के बावजूद उत्तराखंड को हर साल 800 से 1,000 करोड़ रुपये का नुक़सान होने की आशंका है. केंद्र पोषित योजनाएं ख़त्म किए जाने से प्रदेश को हर साल 450 करोड़ रुपये के नुक़सान की आशंका है. इसी के साथ कृषि एवं अन्य विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं के फंडिंग पैटर्न में केंद्र के अंशदान को 90 और 100 फ़ीसद से घटाकर 50 फ़ीसद कर दिया गया है, जिससे उत्तराखंड को काफी नुक़सान होने की आशंका है. मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि फसलों को हुए नुक़सान को देखते हुए किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए 30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई है. ■

> जेएनएनयूआरएम के तहत प्रदेश के तीन शहरों में 14 परियोजनाओं के लिए 425 करोड़ 54 लाख रुपये मंजूर किए गए थे, जिनमें से केवल चार परियोजनाओं का काम शत-प्रतिशत पूरा हो सका है. चार परियोजनाओं में 90 फ़ीसद, दो परियोजनाओं में 75 फ़ीसद और चार परियोजनाओं में 30 से 40 फ़ीसद काम हो चुका है. प्रदेश सरकार को इन परियोजनाओं के लिए केंद्र से क़रीब 70 करोड़ की तीसरी एवं चौथी किस्त अभी तक नहीं मिली है.

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस सर्कुलर पर रोक लगा दी है, जिसमें दिल्ली सरकार ने अपने अधिकारियों एवं मंत्रियों से कहा था कि मीडिया की ऐसी रिपोर्ट्स को वे चिन्हित करें, जिनसे सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि उसके ख़िलाफ़ मानहानि का मुक़दमा किया जा सके. फिर से यह एक अतार्किक बात है. जो भी व्यथित महसूस करता है, वह अदालत जाएगा ही. अदालत फिर यह कहेगी कि मानहानि है या नहीं है. मुद्दा यह है कि केजरीवाल ने आपराधिक मानहानि क़ानून हटाने की बात कही थी. यदि एक बार ऐसा हो जाता है, तब तो हर कोई किसी के बारे में जो चाहेगा, बोल सकेगा.

हमें सरकार को वक्त देना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी विज्ञापनों में नेताओं की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. अच्छी बात है. लेकिन, अजीब बात यह है कि इसमें अदालत ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखा है. भारत के मुख्य न्यायाधीश तस्वीर में आ कैसे सकते हैं, किसी की समझ में नहीं आ सकता. क्यों सरकार कोई ऐसा विज्ञापन देगी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश की तस्वीर लगाने की ज़रूरत हो? फिर ऐसे मामले में स्पीकर या राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति को भी बाहर रखा जाना चाहिए. निर्णय तर्कसंगत नहीं है. मैं भी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार चाहता हूं, लेकिन लोकतंत्र में जब कोई पार्टी चुनाव जीतकर आती है, तो उसे पांच साल तक सरकार चलाने का जनादेश मिलता है. यदि इस बीच सरकार कुछ ग़लत करती है, तो मतदाता उसे दंडित करेंगे. यह काम अदालत का नहीं है. इसी तरह चुनाव के समय चुनाव आयोग बहुत कुछ निषेध कर देता है. अच्छा है. लेकिन, पूरे पांच साल के लिए सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश नहीं डाला जाना चाहिए और तस्वीरों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार नहीं है. लेकिन, अदालत ने कहा है, तो कहा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाता है. दूसरे निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस सर्कुलर पर रोक लगा दी है, जिसमें दिल्ली सरकार ने अपने अधिकारियों एवं मंत्रियों से कहा था कि मीडिया की ऐसी रिपोर्ट्स को वे चिन्हित करें, जिनसे सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही हो, ताकि उसके ख़िलाफ़ मानहानि का मुक़दमा किया जा सके. फिर से यह एक अतार्किक बात है. जो भी व्यथित महसूस करता है, वह अदालत जाएगा ही. अदालत फिर यह कहेगी कि मानहानि है या नहीं है. मुद्दा यह है कि केजरीवाल ने आपराधिक मानहानि क़ानून हटाने की बात कही थी. यदि एक बार ऐसा हो जाता है, तब तो हर कोई किसी के बारे में जो चाहेगा, बोल सकेगा.

यहां सब लोग यानी कांग्रेस और भाजपा आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों चुनाव में हार चुके हैं. उन्हें दिल्ली सरकार पर हमला करने के लिए मुद्दा मिल गया है, लेकिन यह एक नई पार्टी के साथ अनुचित है. मैं दिल्ली का मतदाता नहीं हूं और न केजरीवाल को जानता हूं. तथ्य यह है कि केजरीवाल ने नए प्रतिमान प्रस्तुत किए हैं और दिल्ली के लोगों ने उन्हें वोट दिया है. मैं नहीं समझता कि अदालत को उन्हें हतोत्साहित करने के इस अभियान में शामिल होना चाहिए. उनकी सरकार को अभी दो-तीन महीने हुए हैं. उन्हें दो-तीन साल तक अपना काम करने दें. तभी हम जान पाएंगे कि उनकी योजनाएं सफल हो पाती हैं या नहीं. पहले से ही दिल्ली में लोग कह रहे हैं कि पानी के बिल में कमी आई है, बिजली के बिल में कमी आई है, सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग के लिए भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है. यदि वह ऐसे अच्छे काम कर रहे हैं, तो इसमें क्यों किसी को बाधा डालनी चाहिए? क्या इसलिए कि इस पूरी तस्वीर से कांग्रेस और भाजपा गायब है? यह सही नहीं है.

सवाल यह है कि इस सर्कुलर में क्या आपत्तिजनक हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आता. उन्होंने अपने अधिकारियों एवं मंत्रियों से सतर्क रहने को कहा और कहा कि अगर किसी ख़बर से यह लगता है कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है, तो कार्रवाई करें. लेकिन, कार्रवाई केवल न्यायपालिका करेगी. तो क्यों इस सर्कुलर पर रोक लगी? जाहिर है, अब प्रशांत भूषण जैसे लोगों, जो इस परिदृश्य में नहीं हैं, ने इसका स्वागत किया है. प्रशांत भूषण एक ग़लत मिसाल स्थापित कर रहे हैं. उन्हें समझना चाहिए कि यह सर्कुलर मीडिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं देता है, यह सिर्फ़ न्यायपालिका के पास जाने के लिए शक्तियां देता है. तो फिर इसमें मुद्दा क्या है? मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत अधिक सक्रिय नहीं होना चाहिए और केवल ऐसे मामलों में निर्णय देना चाहिए, जिनका संबंध वास्तव में लोगों से हो.

दूसरी आलोचना प्रधानमंत्री द्वारा कई देशों का दौरा करने को लेकर है. कार्टून आ रहे हैं, ट्वीटर पर बातें हो रही हैं. एक देश के प्रधानमंत्री के प्रमुख देशों के साथ अच्छे संबंध होने ही चाहिए. श्री मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं. वह दूसरे देश के नेताओं को आमंत्रित करके या दूसरे देशों में खुद जाकर संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़्यादा आपत्ति नहीं होनी चाहिए. सभी प्रधानमंत्रियों ने विदेश दौरा किया है. पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के व्यापक अंतरराष्ट्रीय संपर्क रहे हैं. तुलनात्मक रूप से भाजपा के श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी इस मामले में बड़े कद तक पहुंचे. श्री मोदी एक राज्य के मुख्यमंत्री थे. उन्हें दूसरे देशों के नेताओं से परिचित होने के लिए वहां जाना या दूसरे देशों के नेताओं को आमंत्रित करना ही पड़ेगा. मुझे लगता है कि हमें उन्हें समय देना चाहिए. देखते हैं, इस सबसे क्या निकल कर आता है. अभी लोगों ने बहुत अधिक उम्मीदें लगा रखी हैं, यह अनुचित है. एक, दो या दस दौरे में भी भारत-चीन सीमा विवाद का निपटारा नहीं किया जा सकता. यह एक धीमी प्रक्रिया है. चीन भारत का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है और श्री मोदी उसे प्रोत्साहित करना चाहते हैं. लेकिन, यहां भी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है. भारत और चीन के बीच 70 बिलियन का व्यापार है. लेकिन, यहां थोड़ा समझना होगा कि जहां चीन 55 बिलियन का माल भारत भेजता है, वहीं भारत 15 बिलियन का माल ही चीन को निर्यात कर पाता है यह बेहद असंतुलित है. असल मुद्दा यही है कि आख़िर इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? यदि चीन अपने उत्पाद भारत भेजने के बजाय मेक इन इंडिया करे, तब तो कोई फ़ायदा है? चीन भारत में अपने स्वयं के उत्पादों की डंपिंग करता रहे और हम उसके लिए भुगतान करते रहें, तब इस व्यापार से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा.

अरुण शौरी ने एक इंटरव्यू दिया और भाजपा सर्कल में कहा जा रहा है कि चूंकि वह निराश हैं, इसलिए मोदी पर हमला कर रहे हैं. यह ग़लत है. उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए वित्त मंत्री द्वारा बहुत अधिक किया जाना चाहिए. वह सिर्फ़ यही याद दिला रहे हैं कि भाजपा इतने बड़े वादे के साथ सत्ता में आई है, लेकिन एक साल में उसके मुक़ाबले बहुत कम काम किया गया है. उन्होंने आगाह भी किया कि भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार के बारे में बहुत उम्मीद नहीं करनी चाहिए. यह एक बहुत जटिल काम है. इसलिए शौरी ने जो भी कहा है, उसका जो भी उद्देश्य हो, वह सही हो सकता है, ग़लत भी हो सकता है. वह अभी भी भाजपा के हिस्से हैं. वह चाहते हैं कि उनकी सरकार सफल हो. इसलिए वह सिर्फ़ सरकार को आगाह कर रहे हैं. मैं श्री शौरी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि सिर्फ़ तीन लोग सब कुछ चला रहे हैं, श्री मोदी, श्री शाह और श्री जेटली. मैं समझता हूं कि यह सही नहीं है. मुझे लगता है कि पीएमओ के अधिकारी पीएमओ चला रहे हैं और वही शक्तिशाली होते हैं और वही श्री मोदी के कान और आंख हैं. अगर ऐसा है, तो श्री मोदी को सावधान हो जाना चाहिए. आपके नौकरशाह आपके कितने भी क़रीबी क्यों न हों, लेकिन आपको सिर्फ़ किसी एक पर विश्वास करना होगा, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने पीएन हक्सर और श्री वाजपेयी ने बृजेश मिश्रा पर किया था. इसलिए आपके पास उस तरह का शक्तिशाली आदमी है, तब तो ठीक है, जिसे मैं अभी नहीं देख पा रहा हूं. लेकिन, अगर आपके पास नौकरशाहों की एक फौज है, जो गुजरात में आपके साथ काम कर चुकी है और वही लोग सारे मुद्दों पर काम कर रहे हैं, चाहे वह सियासी मुद्दा हो या अन्य कोई मुद्दा, तो आप अपने आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं.

उधर संघ परिवार और विहिप के अपने विचार हैं. जाहिर है, नौकरशाह इन विचारों को संतुलित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही सक्षम अधिकारी चाहिए. मुझे नहीं मालूम कि पीएमओ कौन चला रहा है और कौन प्रधानमंत्री को सलाह दे रहा है. लेकिन, अब एक साल पूरा हो चुका है. अगले छह महीने में सरकार को दिखाना होगा कि वह हर मुद्दे पर गंभीर है. ठीक है कि आपने एक साल सिर्फ़ चीजों को समझने में लगाया, लेकिन इसके बाद अब सिर्फ़ चार साल बचते हैं. नए रोज़गार सामने नहीं आ रहे हैं और इस तरह से नए रोज़गार आएंगे भी नहीं. आपकी नीतियां क्या हैं, इसे सही ढंग से नहीं बताया जा रहा है. वित्त मंत्री ने दो बजट पेश कर दिए हैं. इसे लेकर अलग-अलग तरह की राय आई. मसलन, इस बजट को वित्त मंत्री ने अपने विचार से बनाया या प्रधानमंत्री के विचार से या फिर इसे नौकरशाहों ने बनाया? यह भी चर्चा है कि वित्त मंत्रालय के भीतर नौकरशाहों के बीच जबरदस्त मतभेद है. वित्त सचिव, आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम और राजस्व सचिव, ये सब एक-दूसरे से नज़र तक नहीं मिलाते. जितनी जल्दी प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें और एक स्पष्ट नीति दें, देश के लिए उतना ही बेहतर होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

एक औघड़ लीक से हटकर-5

अजब-अनोखी दुनिया औघड़ों की

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

अन्य साधना पंथों और संप्रदायों के समान ही भारत में अघोरपंथियों के भी कई प्रसिद्ध केंद्र थे, जिन्हें स्थल कहते हैं. इनमें से कुछ प्रसिद्ध स्थल पश्चिम भारत में आबू पर्वत और गिरनार, पूर्व भारत में बोधगया तथा असम के कई स्थानों में, मध्य भारत में काशी तथा सिंध में हिंगलाज में विद्यमान हैं. अघोरियों का एक बहुत बड़ा केंद्र बड़ौदा में था, किंतु पिछले कई दशकों से वह निर्जन हो गया है. वहां अघोरेश्वर का मंदिर भी था, जिसके महंत अघोराचार्य थे. अघोर साधना की प्राचीनता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अरस्तू जैसे दार्शनिक एवं प्लिनी तथा मार्कोपोलो जैसे विश्व यात्रियों ने अघोरपंथियों के केंद्रों का उल्लेख किया है. ईरान देश में भी एक समय इनके केंद्र विद्यमान थे. संभवत: उन दिनों अघोरी शैव अपनी साधना, अपने सिद्धांत तथा अपने संप्रदाय के साथ सुदूर पश्चिम तक फैले हुए थे. इनमें पुरुष अघोरी साधु ही नहीं, अघोरिनें भी रहती थीं, जो दलों में स्थान-स्थान पर घूमा करती थीं. जो विवरण मिलते हैं, उनके अनुसार ये अघोरिनें सिर पर जटा बढ़ाए और फैलाए, गले में अनेक प्रकार की पत्थर एवं स्फटिक की मालाएं लटकाए, कमर में घाघरा बांधकर और हाथ में त्रिशूल लेकर चलती थीं.

ह्वेनसांग ने अघोरियों का वर्णन करते हुए लिखा है कि अघोरी लोग नंगे रहते हैं, भभूत रमाते हैं और हड्डियों की माला पहनते हैं. उसने निर्ग्रंथ (नग्न) कपालधारियों का भी उल्लेख किया है. संस्कृत के अनेक काव्यों और नाटकों में कापालिकों के अद्भुत वर्णन मिलते हैं. शंकर विजय में आनंद गिरि ने कापालिकों का वर्णन करते हुए लिखा है कि वे शरीर पर चिता-भस्म रमाए रहते हैं, गले में खोपड़ियों की माला डाले रहते हैं, माथे पर काली रेखा का तिलक लगाते हैं और कमर में कभी-कभी व्याघ्र चर्म लपेटते हैं. बाएं हाथ से कपाल और दाएं हाथ में घंटी बजाते हुए, बार-बार शंभु, भैरव, कालिनाथ आदि शिव के नामों का उच्चारण करते रहते हैं.

कापालिक अपनी साधना के क्रम में बलि भी देते थे. भवभूति ने अपने मालती माधव में अघोरघंट नामक एक इसी प्रकार के कापालिक का चित्रण किया है. प्रबोध चंद्रोदय में भी कापालिक वृत का उल्लेख मिलता है. 17वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में लिखित दविस्तां नामक ग्रंथ में ऐसे योगियों की चर्चा है, जो महामांस का सेवन तो करते ही थे, अन्य अखाद्य पदार्थों का प्रयोग भी इसलिए करते थे कि उनसे अद्भुत दृष्टि प्राप्त होती है. वाण ने अपने हर्षचरित में राजा पुष्पभूति के साथ अघोरी भैरवाचार्य की श्मशान साधना का अत्यंत विशद् वर्णन किया है, जिससे यह भी सिद्ध होता है कि तत्कालीन राजसभाओं पर इनका बड़ा प्रभाव था. कर्नल टॉड ने भी अपनी पुस्तक पश्चिम भारत की यात्रा में आबू पर्वत पर अवस्थित अघोरियों की टोली का वर्णन किया है.

पिछली तीन शताब्दियों से अघोरियों के जिस पंथ का व्यापक प्रचार हुआ, वह बाबा किनाराम द्वारा प्रवर्तित अघोर पंथ है, जिसका केंद्र काशी है. इस संप्रदाय के अघोरपंथियों को किनारामी भी कहा जाता है. इन साधकों ने इतनी तितिक्षा सिद्ध कर ली है कि इनके लिए सुख-दु:ख, शीत-उष्ण, भाव-अभाव सब समान हैं. इसीलिए ये साधक प्राय: नग्न और मौन रहते हैं. ये भिक्षाटन भी नहीं करते, जो कुछ उनके शिष्य उनके पास पहुंचा देते हैं, वही ग्रहण करके तृप्त रहते हैं. किनारामी पंथ में दीक्षित मुंडित मस्तक मुड़ियों को सरभंगी कहते हैं. सरभंगी और किनारामी दोनों ही महातत्वों का भक्षण करते हैं, किंतु केवल विरल अवसरों पर ही इस प्रकार का आचार विहित है.

शास्त्रीय ग्रंथों में देवानांप्रिय अयोध्या की चर्चा आती है, जिसका अर्थ है देवताओं की नगरी, जो अजेय है और जिसमें सभी देवताओं के साथ देवाधिपति शिव या राम का भी वास है. योगियों का कहना है कि आठ चक्र वाली और नौ द्वारों वाली शरीर नगरी ही गो अर्थात इंद्रियों अथवा देवताओं की शाश्वत आवास भूमि है. उसके बिना देवता प्रकट ही नहीं हो सकते. इसलिए शरीर अयोध्या है और आत्मा इस पुरी का राजा, शिव, इंद्र, ब्रह्मा या राम है. योगियों की शिवपुरी यही है. यही मन रूपी मणिकर्णिका है और अंत:करण रूपी ज्ञानवापी है, जिसमें षडरिपु रूपी म्लेच्छों से बचने के लिए आत्मा रूपी शिव का प्राकट्य हुआ है. यही मुक्ति भूमि काशी है और यह पंचकाशी (अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय कोश) के बीच अवस्थित है. योगीजन इसी काशी में सदा निवास करते हैं. शरीर में मध्य देश नितंब को कहते हैं. दोनों नितंबों से तिर्यक (ड) की आकृति बनती है, जिस प्रकार दोनों पसलियों से कलेजे के पास मनुष्य शरीर में देवनागरी (ल) की आकृति बनती है. मध्यमावाणी वहीं अवस्थित है और उसी से जाप करना विहित बताया है. नितंब को स्पर्श करके (ड) की आराधना होनी चाहिए. यह अक्षर शिव तथा शिवा या काली का स्वरूप और बीज में मंत्र रूप है. मुख से लेकर गुदा तक एक ही महान स्रोत है.■

क्रमश:

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

कांग्रेस के सिर पर मंडराता ख़तरा

मुझे नहीं पता, इस बार क्या होगा? लेकिन उसका पहला हिस्सा, जिसकी सूचना मुझे कांग्रेस के समर्थक उस बहुत बड़े वकील ने दी है, मैंने उसे क्रास चेक किया और वेरीफाई किया. मेरे सूत्रों ने मुझे बताया कि यह ख़बर सौ प्रतिशत सच है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले तीन महीने में प्रियंका गांधी के दरवाजे पर जांच कमेटी भेजने की योजना बना चुकी है.

देश के एक बड़े वकील, जो संसद के सदस्य रह चुके हैं, उनकी व्यथा मैं रखना चाहता हूं. उनका नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं, क्योंकि उनकी बात में कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं और बहुत सारे कार्यकर्ताओं की बात शामिल है. वह सज्जन सोनिया गांधी के लिए उन अवसरों पर मददगार साबित हुए, जब श्रीमती सोनिया गांधी के सामने कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था. उनका यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी बढ़त सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए मिली, क्योंकि कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी के ज़रिये तय ही नहीं कर पाई कि उसे नरेंद्र मोदी का मुक़ाबला किस शैली में और किस तरीके से करना है. नतीजे के तौर पर वह हड़बड़ाहट या घबराहट में लगातार अपने पैर पीछे खींचती रही. आज कांग्रेस वहां पहुंच गई है, जहां कांग्रेस उठने के लिए सिर्फ़ ईश्वर से प्रार्थना कर सकती है. कांग्रेस जिस एक बात को नहीं समझ पा रही है, वह है धारणा (परसेप्शन) या आपकी लोगों के ऊपर छाप. कोई नहीं जानता कि राजीव गांधी ने बोफोर्स कांड में 64 करोड़ रुपये की घूस ली थी या नहीं ली थी. लेकिन, देश में एक छाप पड़ गई कि राजीव गांधी उस घूस कांड के पीछे थे. बिना राजीव गांधी की सहमति के वह पैसा लिया ही नहीं जा सकता और चूंकि वह पहला बड़ा पैसा था, इसलिए वह पैसा ज़रूर राजीव गांधी ने लिया होगा. इस बात ने देश के इतिहास में बनी सबसे मजबूत सरकार यानी 412 सांसदों के समर्थन से बनी सरकार की साख जनता में शून्य कर दी. साख बहुत महत्वपूर्ण भी होती है और बहुत ख़तरनाक भी होती है. राजीव गांधी सत्ता में आते समय 412 सदस्यों के कंधे पर बैठकर प्रधानमंत्री बने थे और देश ने माना था कि यह शख्स निहायत ईमानदार है और इसके ऊपर किसी तरह का दाग नहीं है और यह देश को आगे ले जाएगा. जब राजीव गांधी ने कहा कि हमें 21वीं शताब्दी की तैयारी करनी है, तब सारे देश ने राजीव गांधी के इस वाक्य को हाथों हाथ लिया, लेकिन सफलता उनके हाथ से फिसलती रही और बोफोर्स कांड ने उस फिसलन को तेजी से अंधी सुरंग में धकेलने वाला रास्ता बना दिया.

अगर राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी की तरह शालीन शैली का इस्तेमाल करते, थोड़ी मुस्कराहट, थोड़ी हंसी उनके चेहरे पर रहती, तो देश शायद उन्हें ज़्यादा सुनता. लेकिन, आज देश में यह राय बन गई है, खासकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में यह राय बन गई है कि राहुल गांधी नॉन स्टार्टर हैं. वह जितना देश में घूम रहे हैं, प्रचार कितना हो, पर जनता उनके साथ खड़ी होने में हिचकेगी. श्रीमती सोनिया गांधी की तबीयत खराब है, यह सबको पता है. इस स्थिति ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को और चिंतित कर दिया है.

आज वही धारणा (परसेप्शन) कांग्रेस नेतृत्व के सामने है. कांग्रेस कार्यकर्ता और उससे ज़्यादा देश के लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस आख़िर करना क्या चाहती है, कांग्रेस खुद को किस तरीके से पुनर्संगठित करेगी? राहुल गांधी का चेहरा सौम्य है, लेकिन उनके शारीरिक हाव-भाव (बॉडी लैंग्वेज) उनके चेहरे के बिल्कुल विपरीत हैं. अगर राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी की तरह शालीन शैली का इस्तेमाल करते, थोड़ी मुस्कराहट, थोड़ी हंसी उनके चेहरे पर रहती, तो देश शायद उन्हें ज़्यादा सुनता. लेकिन, आज देश में यह राय बन गई है, खासकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में यह राय बन गई है कि राहुल गांधी नॉन स्टार्टर हैं. वह जितना देश में घूम रहे हैं, प्रचार कितना हो, पर जनता उनके साथ खड़ी होने में हिचकेगी. श्रीमती सोनिया गांधी की तबीयत खराब है, यह सबको पता है. इस स्थिति ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को और चिंतित कर दिया है.

इस स्थिति में उस बड़े वकील ने, जो देश के ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं के नज़दीक रहे हैं, मुझे एक ख़तरनाक बात बताई. उन्होंने कहा कि राबर्ट वाड्रा के ज़रिये भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रियंका गांधी तक पहुंचना चाहती है. उन्होंने कहा कि उनके पास यह निश्चित जानकारी है कि राबर्ट वाड्रा के लिए इन्क्वायरी सेटअप करके, कमीशन सेटअप करके केंद्र सरकार प्रियंका गांधी के पास इसलिए पहुंचेगी, क्योंकि राबर्ट वाड्रा ने प्रियंका गांधी को अपनी कई कंपनियों में हिस्सेदार बनाया हुआ है. जब मैंने कहा कि प्रियंका गांधी उनकी पत्नी हैं, तो वह उन्हें हिस्सेदार नहीं बनाते, तो फिर किसे बनाते? तब उस बड़े वकील ने कहा कि शायद राबर्ट वाड्रा ने इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि कभी मुसीबत आएगी, तो प्रियंका गांधी नामक ढाल उनकी रक्षा करेगी. इसलिए उन्होंने प्रियंका गांधी को अपनी उन कंपनियों में लिया है, जिनकी जांच आज भाजपा सरकार कराने का मन बना चुकी है.

इसका मतलब यह है कि गांधी परिवार एक भयानक मुसीबत में है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जब रास्ता नहीं सूझता है, तो वे प्रियंका गांधी को कांग्रेस में लाने और उन्हें पार्टी की कमान सौंपने की मांग छिटपुट जगहों से उठा देते है. उन्हें लगता है कि प्रियंका गांधी की बॉडी लैंग्वेज, प्रियंका गांधी का चेहरा, प्रियंका गांधी का अपनी बात को समझाने का तरीका राहुल गांधी से ज़्यादा असरदार है. लेकिन, अगर कांग्रेस के लिए आशा की किरण बनने वाली प्रियंका गांधी के ऊपर ही भाजपा अपनी मिसाइल छोड़ रही है और अगर वह मिसाइल कहीं सटीक ढंग से लग गई, तो कांग्रेस परेशानी में पड़ सकती है. कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने सबसे कमजोर काम यह किया कि उन्होंने कांग्रेस के भीतर पांच-छह सेकेंड रैंक के और नेता नहीं बनाए. किसी तरह दिग्विजय सिंह टिमटिमाते, लड़खड़ाते कांग्रेस नेतृत्व के लिए सहारे का काम करते रहे. लेकिन, आख़िर में उन्हें भी यह संदेश दिया गया कि आपने अगर ज़्यादा बयान दिए, तो आपको किनारे कर दिया जाएगा. वह चुप हो गए. जनार्दन द्विवेदी कांग्रेस के फ़ैसले लेने वाले सर्कल से बाहर हो गए हैं. शायद राहुल गांधी की टीम उन लोगों को पसंद नहीं करती, जो सोनिया गांधी के नज़दीक हैं.

लेकिन, राहुल गांधी उस ख़तरे को नहीं समझ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की वजह से उनके घर के दरवाजे तक आ पहुंचा है. वह ख़तरा है, प्रियंका गांधी को क़ानूनी दायरे में लेकर उनकी संपूर्ण साख समाप्त कर देना. हालांकि, यह काम एक बार मोरारजी देसाई की सरकार में चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गांधी के लिए किया था. उन्हें लगा था कि अगर इंदिरा गांधी को हम गिरफ्तार कर लेंगे, तो उनकी साख मिट्टी में मिल जाएगी और वह कभी दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएंगी. लेकिन विडंबना देखिए कि वह सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी की वजह से टूटी और चौधरी चरण सिंह भी श्रीमती इंदिरा गांधी की वजह से प्रधानमंत्री बने. ऐसे प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने संसद का चेहरा नहीं देखा और प्रधानमंत्री पद से विदा हो गए तथा उसके बाद इंदिरा गांधी ही देश की प्रधानमंत्री बनीं.

गांधी परिवार एक भयानक मुसीबत में है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जब रास्ता नहीं सूझता है, तो वे प्रियंका गांधी को कांग्रेस में लाने और उन्हें पार्टी की कमान सौंपने की मांग छिटपुट जगहों से उठा देते है. उन्हें लगता है कि प्रियंका गांधी की बॉडी लैंग्वेज, प्रियंका गांधी का चेहरा, प्रियंका गांधी का अपनी बात को समझाने का तरीका राहुल गांधी से ज़्यादा असरदार है.

मुझे नहीं पता, इस बार क्या होगा? लेकिन उसका पहला हिस्सा, जिसकी सूचना मुझे कांग्रेस के समर्थक उस बहुत बड़े वकील ने दी है, मैंने उसे क्रास चेक किया और वेरीफाई किया. मेरे सूत्रों ने मुझे बताया कि यह ख़बर सौ प्रतिशत सच है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले तीन महीने में प्रियंका गांधी के दरवाजे पर जांच कमेटी भेजने की योजना बना चुकी है.

अभी भी वक्त है कि कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति बनाए, अपने फ़ैसले बदले और उन लोगों को साथ ले, जिन्होंने मुसीबत के वक्त कांग्रेस को संकट से उबरने में योगदान किया है. अगर श्रीमती सोनिया गांधी ऐसा नहीं करती हैं, तो राहुल गांधी के बारे में एक धारणा देश में बन चुकी है और अगर प्रियंका गांधी के ऊपर भी हमला हो गया, तो यह मानना चाहिए कि गांधी परिवार की साख समाप्त करने में कांग्रेस के समापन का रास्ता खुल जाएगा. क्या इस बात को कोई जाकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बताएगा या उन्हें भारतीय जनता पार्टी की मिसाइल के निशाने पर बने रहने देगा?■

editor@chauthiduniya.com

कैमरन ने सबको हैरान कर दिया

लेबर पार्टी को पिछली बार के मुकाबले में 26 सीटों का नुक़सान उठाना पड़ा. उसे केवल 232 सीटें मिल सकीं. एड मिलिबंड को पार्टी के नेता पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन में जब कोई नेता चुनाव हार जाता है, तो वह उसके बाद पार्टी के नेता पद से चिपका नहीं रहता. लिबरल डेमोक्रेट्स (लिबडेम) का तो जैसे सफाया ही हो गया है. लेबेरल डेमोक्रेट्स पिछली कैमरन सरकार में हिस्सेदार थे. उनके पास 57 सीटें थीं, जिनमें से 49 सीटों पर उनकी हार हुई है. पार्टी के मुखिया निक क्लेग तो जीत गए, लेकिन लिबडेम के ज़्यादातर कैबिनेट मेंबर चुनाव हार गए हैं.

मेघनाद देसाई

डेविड कैमरन को बहुत आसानी से कम करके आंका गया. जब मैं दिल्ली में था, तो मुझसे कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और जर्मनी का दौरा किया, लेकिन वह ब्रिटेन नहीं गए, क्योंकि मोदी से कहा गया था कि कैमरन कामयाब नहीं हो पाएंगे. बहरहाल, मोदी दुनिया के उन नेताओं में से थे, जिन्होंने कैमरन को सबसे पहले बधाई दी. मतदान सात मई को 10 बजे शाम ख़त्म हुआ था. कुछ मिनटों के बाद टीवी स्क्रीन पर एग्जिट पोल नज़र आने लगे. एग्जिट पोल के नतीजे चौंकाने वाले थे. वे 2009 के भारतीय आम चुनाव के नतीज़ों की झलक पेश कर रहे थे. उनमें एक त्रिशंकु संसद की भविष्यवाणी की जा रही थी. गठबंधन की सभी संभावनाओं पर बहस हो रही थी. स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता निकोला स्टरजेन, जो अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार के हीरो थे और जिनकी पार्टी ने स्कॉटलैंड की 59 में से 56 सीटों पर कामयाबी हासिल की, कह रहे थे कि अगर लेबर पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर नहीं भी उभरती है या दूसरे नंबर की पार्टी रहती है, तो भी वह उसके साथ मिलकर सरकार बना लेंगे. लेकिन, सभी चुनाव सर्वेक्षण ग़लत साबित हुए. वे कह रहे थे कि दो प्रमुख पार्टियों, लेबर पार्टी और कंजरवेटिव पार्टी के मत प्रतिशत 34-35 के आसपास होंगे, उनकी सीटें 285-275 के आसपास होंगी, लेकिन कंजरवेटिव पार्टी को बढ़त हासिल होगी. हमें मालूम था कि स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी (एसएनपी) को 45 सीटें मिलेंगी. पिछली बार उसे छह सीटें मिली थीं. इसका अर्थ यह होगा कि लेबर पार्टी, जिसे पिछले चुनाव में कुल 258 सीटों में से 41 सीटें स्कॉटलैंड से मिली थीं, को स्कॉटलैंड में हार का सामना करना पड़ा और 41 सीटों की भरपाई उसे इंग्लैंड एवं वेल्स से करनी थी, जो अंतत: एक कठिन कार्य साबित हुआ.

लेबर पार्टी को पिछली बार के मुकाबले में 26 सीटों का नुक़सान उठाना पड़ा. उसे केवल 232 सीटें मिल सकीं. एड मिलिबंड को पार्टी के नेता पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन में जब कोई नेता चुनाव हार जाता है, तो वह उसके बाद पार्टी के नेता पद से चिपका नहीं रहता. लिबरल डेमोक्रेट्स (लिबडेम) का तो जैसे सफाया ही हो गया है. लेबेरल डेमोक्रेट्स पिछली कैमरन सरकार में हिस्सेदार थे. उनके पास 57 सीटें थीं, जिनमें से 49 सीटों पर उनकी हार हुई है. पार्टी के मुखिया निक क्लेग तो जीत गए, लेकिन लिबडेम के ज़्यादातर कैबिनेट मेंबर चुनाव हार गए हैं. निक क्लेग ने भी पार्टी प्रमुख के पद से त्यागपत्र दे दिया है. दरअसल, यह डेविड कैमरन थे, जिन्होंने सबको आश्चर्यचकित कर दिया. उनकी पार्टी ने न केवल सबसे अधिक सीटों पर जीत हासिल की, बल्कि सदन में बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लिया. इसमें एक बार फिर भारत के 2014 के आम चुनाव की झलक देखी जा सकती है. 650 में से 331 सीटों पर कामयाबी हासिल करके कैमरन ने अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया. उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के शुरुआती दौर में ही घोषणा कर दी थी कि वह तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिस पर उनकी खूब खिल्ली उड़ाई गई. लेकिन, उन्होंने वह कारनामा कर दिखाया, जिसकी मिसाल ब्रिटेन में बहुत ही कम है. उन्होंने लगातार दो चुनाव जीते. उनसे पहले थैचर एवं ब्लेयर यह कारनामा कर चुके हैं. लेकिन, इन तीन को छोड़कर 20वीं सदी में किसी को यह कामयाबी नसीब नहीं हो सकी.

मोदी और कैमरन के बीच बहुत सारी समानताएं हैं. दोनों रणनीतिकार हैं और वे विशेषज्ञों से सलाह लेने में भी गुरेज़ नहीं करते. ऑस्ट्रेलिया के चुनाव विशेषज्ञ लिंटन क्रोसबी ने कैमरन के चुनाव प्रचार को दिशा दी. मिलिबंड के साथ प्रत्यक्ष बहस में हिस्सा लेने से कैमरन को रोकने के लिए क्रोसबी की बहुत आलोचना भी हुई. मिलीबंड ने भी हज़ारों पौंड खर्च करके अमेरिकन सलाहकार डेविड अक्सेल्रोड की सेवाएं हासिल की थीं, लेकिन क्रोसबी की बुद्धिमता ने कैमरन को पुन: सत्ता तक पहुंचा दिया. लेकिन, कंजरवेटिव्स कैसे जीत गए? 2010 में उन्होंने मतदाताओं से कहा था कि आने वाले दिन मुश्किलों से भरे हुए हैं. राजस्व घाटा ऊंचे स्तर पर था और क़र्ज़ बढ़ता जा रहा था. राजकोष के चांसलर जॉर्ज ओस्बोर्न ने घाटा कम करने के लिए कठोर क़दम उठाए थे. इसकी वजह से जो मुश्किलें पेश आईं, उसके लिए उनकी भरपूर आलोचना हुई. आख़िरकार, वह राजकोषीय घाटे को 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत ही कर सके, लेकिन वह कभी रुके नहीं और न उन्होंने मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए कोई अल्पकालिक समझौता किया. अर्थव्यवस्था ने चौथे साल में संभलना शुरू कर दिया और अब तो यह जी-7 के देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है. मतदाताओं ने कंजरवेटिव्स के फ़ैसले की स्पष्टता को सराहते हुए उन्हें उसका इनाम दिया. इसमें अगर भारत के लिए कोई सबक है, तो वह यह है कि मतदाताओं को खुश करने के बजाय एक अनुशासनात्मक आर्थिक नीति को तरजीह देनी होगी. जो पार्टी अलोकप्रिय होने की चिंता छोड़कर बेलाग सच बोलने से परहेज़ नहीं करेगी, वही अंत में लोगों का समर्थन हासिल करेगी. किसी अर्थव्यवस्था से दीर्घकालिक संरचनात्मक कमजोरियां ख़त्म करने के लिए एक नेता को अल्पकालिक तौर पर कुछ अलोकप्रिय फ़ैसले लेने पड़ते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

> शरीर में विटामीन बी–12 की कमी से परनीसीयस एनीमिया होने का खतरा होता है. इस तरह का एनीमिया उन लोगों में सामान्य तौर पर देखा जाता है जो विटामिन बी–12 पचाने में असमर्थ होते हैं. यह परेशानी ज़्यादातर शुद्ध शाकाहारी व्यक्तियों को और लंबे वक्त से शराब का सेवन करने वालों को होती है. हरी सब्जियों की कमी, फलों की कमी से विटामिन बी–12 की माात्रा शरीर में कम हो जाती है, जिससे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है.

एनीमिया से बचें

मोनिशा भटनागर

एनीमिया शरीर में आयरन, फॉलिक एसिड व विटामिन–बी12 की कमी से होने वाला रोग है. इस बीमारी में शरीर में रेड ब्लड सेल्स का स्तर सामान्य से कम हो जाता है. आम भाषा में कहें तो आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है. हीमोग्लोबिन शरीर में आक्सीजन का संचार करता है, ऐसे में हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है. एनीमिया को रोज़मर्रा की भाषा में ख़ून की कमी के नाम से भी जाना जाता है. एनीमिया आजकल की जीवनशैली में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले रोगों में से एक है. एनीमिया से पीड़ित लोग पूरी ताकत के साथ काम नहीं कर पाते हैं और उनका शरीर हमेशा थका–थका महसूस करता है.

एनीमिया होने के कारण

एनीमिया होने के कई कारण हो सकते हैं. ज़्यादातर देखा गया है एनीमिया को अपने आप में बीमारी नहीं माना जाता बल्कि इसे किसी अन्य बीमारी के लक्षण या प्रभाव के रूप में देखा जाता है. जबकि केवल पौष्टिक और नियमित आहार नहीं लेने की वजह से भी एनीमिया हो सकता है. अल्पाहार या कुपोषण भी इसकी एक बड़ी वजह है. रेड–ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए कई प्रकार के विटामिन व मिनरल्स की ज़रूरत होती है. इनकी कमी से रेड– ब्लड सेल्स का निर्माण ज़रूरत के हिसाब से नहीं हो पाता है, फिर हीमोग्लोबिन बनने में परेशानियां आती हैं. ऐसे में व्यक्ति एनीमिया का शिकार बन सकता है. चोट लगने या किसी सर्जरी के कारण शरीर से बहुत ज्यादा रक्तस्राव, किसी भी प्रकार की दीर्घकालिक बीमारी से भी एनीमिया हो सकता है. किसी प्रकार के इंफेक्शन का यदि लंबे समय तक ठीक उपचार न कराया जाए तो उससे भी एनीमिया होने की आशंका होती है. शरीर में विटामीन बी–12 की कमी से परनीसीयस एनीमिया होने का खतरा होता है. इस तरह का एनीमिया उन लोगों में सामान्य तौर पर देखा जाता है जो विटामिन बी–12 पचाने में असमर्थ होते हैं. यह परेशानी ज़्यादातर शुद्ध शाकाहारी व्यक्तियों को और लंबे वक्त से शराब का सेवन करने वालों को होती है. भोजन में हरी सब्ज़ियों की कमी, फलों की कमी से विटामिन बी–12 की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, जिससे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है. इसके अलावा ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकेमेनिया या लींफोमास रेड–ब्लड सेल्स के निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है. इससे भी शरीर में खून की कमी होने की आशंका बढ़ जाती है.

> पौष्टिक और नियमित आहार नहीं लेने की वजह से भी एनीमिया हो सकता है. अल्पाहार या कुपोषण भी इसकी एक बड़ी वजह है. रेड–ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए कई प्रकार के विटामिन व मिनरल्स की ज़रूरत होती है. इनकी कमी से रेड– ब्लड सेल्स का निर्माण ज़रूरत के हिसाब से नहीं हो पाता है, फिर हीमोग्लोबिन बनने में परेशानियां आती हैं. ऐसे में व्यक्ति एनीमिया का शिकार बन सकता है. चोट लगने या किसी सर्जरी के कारण शरीर से बहुत ज्यादा रक्तस्राव, किसी भी प्रकार की दीर्घकालिक बीमारी से भी एनीमिया हो सकता है. किसी प्रकार के इंफेक्शन का यदि लंबे समय तक ठीक उपचार न कराया जाए तो उससे भी एनीमिया होने की आशंका होती है.

गर्भावस्था में अगर आयरन और फॉलिक एसिड का पर्याप्त मात्रा में सेवन नहीं किया जाए तो स्त्रियों में एनीमिया होने का खतरा खासतौर से बढ़ जाता है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु भी मां के शरीर से काफी मात्रा में आयरन और फॉलिक एसिड ग्रहण कर रहा होता है. रोगी की रक्त जांच के जरिए डॉक्टर आसानी से एनीमिया की पहचान कर लेते हैं. इसके अलावा वे रोगी की अन्य जांच भी करवाते हैं जिससे एनीमिया की मुख्य वजह का पता लगाया जा सके. एनीमिया का इलाज पूरी तरह से संभव है. एनीमिया के अन्य कारणों में दवाओं का दुष्प्रभाव, थायरॉयड की समस्या, कैंसर, लीवर की बीमारियां, वंशानुगत समस्याएं, एड्स व नियमित रक्तस्राव शामिल हैं. एनीमिया के कारण रोगी हमेशा थका हुआ महसूस करता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है. एनीमिया में रोगी को ज्यादा से ज्यादा आयरन युक्त आहार लेना चाहिए. इससे खून की कमी को जल्दी पूरा किया जा सकता है. बढ़ते बच्चों, स्तनपान कराने वाली महिलाओं व बीमार व्यक्तियों में एनीमिया का खतरा ज्यादा होता है. ध्यान रखें हीमोग्लोबिन का स्तर पुरुष और महिलाओं में अलग–अलग होता है.

लक्षण

शुरुआत में शरीर में खून की कमी होने पर कोई खास लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे–जैसे यह कमी बढ़ती जाती है इसके लक्षण भी बढ़ने लगते हैं. सिरदर्द, थकान और अक्सर नींद आना. चक्कर आना और आंखों के आगे अंधेरा छाना, हृदय गति का असामान्य होना, बेहोश हो जाना. इसके अलावा नाखूनों का सफेद या पीला पड़ना, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ना आदि भी इसके लक्षण हैं.

बचाव

एनीमिया से बचाव और इसके इलाज का सबसे कारगर तरीका संतुलित और पौष्टिक आहार खाना है. हरी पत्तेदार सब्जियों, फलों और अन्य खाद्य पर्दार्थों जैसे चुक्कंदर, गाजर, सेव, अनार, खजूर, मूंगफली, गुड़ और सूखे मेवों को खाना चाहिए. शरीर में फॉलिक एसिड की मात्रा बढ़ाने के लिए कुट्टू का आटा, ओटमील (जौ), गोभी, मशरूम और ब्रोकली को डाइट में शामिल किया जा सकता है. खाने में आयरन के साथ–साथ विटामिन सी भी खाएं क्योंकि यह शरीर में आयरन सोखने में मदद करता है. विटामिन सी और कैल्शियम के लिए दूध, दही, पनीर, चीज के अलावा संतरा, नींबू, मौसमी, चकोतरा और अंगूर जैसे विटामिन–सी युक्त फलों को भी खाना चाहिए. भुने चने और गुड़ भी शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ान में मदद करता है. लोहे के बर्तन में बनाई गई हरी सब्जियों में ज्यादा आयरन होता है जो हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है. बावजूद इसके हीमोग्लोबिन की मात्रा में सुधार न हो तो डॉक्टर की सलाह पर आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां लें.■

feedback@chauthiduniya.com

तानाशाही के खिलाफ थीं मारिया

> दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दोनों ही तरफ से खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान काफी कठिन था. युद्ध में शामिल देशों के लिए खुफिया सूचनाओं के बगैर युद्ध लड़ना मुश्किल था. ऐसे में दोनों तरफ केदेश गोपनीय सूचनाएं पहुंचाने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया करते थे. महिलाओं पर कोई जल्दी शक भी नहीं करता था. जिससे सूचना पहुंचाने में आसानी होती थी. हालांकि ऐसा नहीं था कि महिलाओं के लिए यह बहुत आसान काम था.

अरूण तिवारी

मारिया गुलोविच लियू स्लोवाकिया की रहने वाली थीं. उनका जन्म 19 अक्टूबर, 1921 को हुआ था. वे स्कूल टीचर थीं, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के खिलाफ विद्रोही सेना के लिए जासूसी का काम किया था. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्हें अपनी बेहतर सेवाओं के लिए अमेरिका के ब्रांज स्टार से सम्मानित किया गया था. इसके अलावा उन्हें ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से भी पुरस्कार दिया गया था.

गुलोविच का जन्म स्लोवाकिया के जाकूबनी में हुआ था. वे एक पादरी पिता की औलाद थीं. उनकी मां एक प्राथमिक स्कूल में टीचर थीं. उन्होंने वहीं पर अपनी शिक्षा–दीक्षा ग्रहण की. इसके बाद वह भी वहीं पर एक स्कूल में शिक्षक पद पर चयनित हो गईं. जब स्लोवाकिया पर जर्मनी की सेनाओं ने कब्जा कर लिया, उसके बाद भी गुलोविच ने अपने स्कूल में बच्चों को शिक्षा देना जारी रखा. जबकि उनके स्कूल के कई टीचर अपनी नौकरियां छोड़कर किसी अन्य जगह पर चले गए थे. इसी दौरान एक अजीब घटना घटी. उनके पास एक आदमी आया जिसने उनसे कहा कि मेरी बहन और उसकी बेटी को अपने स्कूल में छिपा लीजिए. इस घटना के बारे में गुलाविच ने एक किताब के जरिये खुद बताया कि किसी को छिपाकर रखना उनका ध्येय नहीं था. मतलब वे नहीं चाहती थीं कि देश जर्मनी की सेना के किसी भी चक्कर में फंसें. लेकिन जब उन्होंने उस महिला और उसकी छोटी बच्ची को देखा तो उन्हें लगा कि अगर वे इन दोनों की जिंदगी नहीं बचाती हैं तो यह उनकी बहुत बड़ी भूल होगी. उन्होंने उन दोनों को अपने स्कूल के क्वार्टर में रहने की जगह दी, और खुद

स्कूल की कक्षाओं में ही सोने लगीं. कुछ दिनों बाद वह आदमी अपनी बहन और भांजी को सुरक्षित स्थान पर लेकर चला गया. उनकी इस गतिविधि की जानकारी स्लोवाकिया के अधिकारियों को हो गई. उन्होंने इसकी जानकारी लेने के लिए एक अधिकारी को गुलोविच के पास भेजा.

किस्मत से स्लोवाकिया के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ के लिए जो फोर्स भेजा था, वह फासीवाद का विरोधी था. गुलोविच भी फासीवाद को पसंद नहीं करती थीं. उनका मानना था कि तानाशाही के साथ दुनिया का भला नहीं किया जा सकता है. उन्होंने उस अधिकारी को पूरी बात बताई. इसके बाद स्लोवाकिया के अधिकारियों ने गुलोविच के पास यह प्रपोजल भेजा कि क्या वह उनके लिए सूचनाएं पहुंचाने का काम कर सकती हैं. गुलोविच ने इसे स्वीकार कर लिया. गौर करने वाली बात यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दोनों ही तरफ से खुफिया सूचनाओं का आदान–प्रदान काफी कठिन था. युद्ध में शामिल देशों के लिए खुफिया सूचनाओं के बगैर युद्ध लड़ना मुश्किल था. ऐसे में दोनों तरफ के देश गोपनीय सूचनाएं पहुंचाने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया करते थे. महिलाओं पर कोई जल्दी शक भी नहीं करता था. जिससे सूचना पहुंचाने में आसानी होती थी. हालांकि ऐसा नहीं था कि महिलाओं के लिए यह बहुत आसान काम था. इसी तरह के काम करने के लिए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान न जाने कितनी महिला जासूसों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था. गुलोविच को पहला मिशन यह मिला कि उन्हें जर्मनी के खुफिया अधिकारियों के बीच से जानकारियां निकाल कर लानी थीं. उन्होंने इस काम को बहुत बहादुरी के साथ किया. इसके अलावा उन्हें अधिकारियों ने एक काम सौंपा कि एक शॉट वेव रेडियो देश में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था. गुलोविच के लिए मुश्किल उस समय खड़ी हो गई जब जर्मनी के गेस्टागपो अधिकारियों ने ट्रेन को रुकवाकर उसकी जांच करना शुरू कर दिया. गुलोविच ने किसी तरह जान बचाकर इस काम को पूरा किया और यह दिखा दिया कि जर्मनी के अधिकारियों की नजर से बचकर निकलने में अब उन्हें महारथ हासिल होने लगी है.

गुलोविच को कई भाषाओं की जानकारी होने के कारण अनुवादक काम भी दिया गया. वे जर्मन भाषा के दस्तावेजों का अनुवाद किया करती थीं. इसके कारण स्लोवाकिया के अधिकारियों को काफी मदद मिलती थी. कुछ महीनों बाद वे अमेरिका चली गईं और उन्हें वहां फिर एक बार खुफिया जासूसी का काम सौंपा गया. अमेरिकी अधिकारियों द्वारा दिए गए मिशन को गुलोविच ने बहुत ही बहादुरी के साथ पूरा किया इसी वजह से युद्ध के बाद उन्हें सम्मानित किया गया.

गुलोविच ने मानवता की सेवा के लिए काम किया. उनका मानना था कि अगर दुनिया को चलाना है तो सभी को साथ लेकर चलना होगा. इसके लिए बहुत जरूरी है सभी देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करें.■

feedback@chauthiduniya.com

कई मायनों में ऐतिहासिक रहा ब्रिटेन का चुनाव

शफ़ीक़ आलम

ब्रिटेन में चुनाव से पूर्व तमाम आकलनों को ग़लत साबित करते हुए प्रधानमंत्री डेविड कैमरन अपनी पार्टी को क़ामयाब बनाने में सफल रहे. हालांकि, कैमरन अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जा चुके हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने यह घोषणा कर दी थी कि वह तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे. बहरहाल जहां चुनाव पूर्व सभी सर्वेक्षण लेबर पार्टी और कंजरवेटिव पार्टी के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद जता रहे थे, वहीं लिबरल डेमोक्रेट्स (लिबडेम) और स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी (एसएनपी) जैसी छोटी पार्टियों को किंगमेकर की भूमिका पर भी खूब बहस चली. एसएनपी के नेताओं तो, यहां तक कह दिया कि वे लेबर पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं. अख़बारों और टेलीविज़न चैनलों पर भी चुनाव के बाद गठबंधन की अलग-अलग संभावनाओं की तलाश शुरू हो गई थी. जैसे-जैसे चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए वैसे-वैसे यह साफ़ होता गया कि यह मुक़ाबला बराबरी का नहीं है. जब सभी नतीजे घोषित हो गए, तो कंजरवेटिव पार्टी न केवल सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, बल्कि उसे स्पष्ट बहुमत भी मिल गया. उसे कुल 650 सीटों में से 331 सीटें मिलीं.

ऐसा नहीं है कि हाउस ऑफ़ कॉमन्स (पार्लियामेंट) में लगातार दूसरी जीत हासिल करने वाली कंजरवेटिव पार्टी पहली पार्टी है. साथ ही प्रधानमंत्री कैमरन दूसरा कार्यकाल हासिल करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं. इससे पहले भी यह कारनामा दोहराया जा चुका है. टोनी ब्लेयर और लेबर पार्टी इसकी मिसाल है, लेकिन फिर भी कई लिहाज़ से यह चुनाव न सिर्फ़ ऐतिहासिक रहा, बल्कि आश्चर्यजनक रहा. दरअसल, चुनाव पूर्व सभी सर्वेक्षण और एग्जिट पोल ग़लत साबित हुए. हालांकि, कैमरन सरकार की आर्थिक नीतियों से मतदाता बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे. उनके कार्यकाल में देश की जीडीपी में कोई वृद्धि नहीं हुई थी. बावजूद इसके जनता ने उनके नेतृत्व पर भरोसा किया.

दरअसल, इसके कई कारण हैं. पहला कारण पिछली कैमरन सरकार में भागीदार रही लिबरल डेमोक्रेट्स का इंग्लैंड और वेल्स से सफाया होना. लिबरल डेमोक्रेट्स के कई पूर्व मंत्री अपनी सीटें नहीं बचा पाए. इसका भरपूर फ़ायदा कंजरवेटिव पार्टी को मिला. दूसरा कैमरन परंपरागत लेबर वोटर्स समझे जाने वाले अप्रवासी लोगों ख़ास तौर पर भारतीय मूल के लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, जिसका लाभ उन्हें मिला. वैसे कंजरवेटिव पार्टी की इस जीत की एक बड़ी वजह दक्षिणपंथी विचारधारा की लोकप्रियता भी है. ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप में दक्षिणपंथी विचारधारा की लोकप्रियता के विषय पर चौथी दुनिया पहले भी कई रिपोर्ट प्रकाशित की हैं

पिछले साल अख़बारों में यह ख़बरें आ रही थीं कि अति दक्षिणपंथी पार्टी यूकेआईपी वोट हासिल करने के मामले में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी. यूकेआईपी देश के अप्रवास क़ानून में बदलाव लाने, ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन में शामिल होने और मुसलमानों का विरोध करती रही है. इसका फ़ायदा उसे पिछले साल क्लैक्टन के उपचुनाव में मिला. हालांकि, इस आम चुनाव में यूकेआईपी को केवल एक सीट से ही संतोष करना पड़ा. यहां तक कि पार्टी के बड़े नेता निगेल फराज चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी को ब्रिटेन में लगभग 12 प्रतिशत से अधिक वोट मिले हैं. पिछले आम चुनाव में उसे केवल 2 प्रतिशत मत मिले थे. इसके अलावा, 100 से अधिक सीटों पर यह पार्टी दूसरे स्थान पर रही. इससे साबित होता है कि देश में दक्षिणपंथी विचारधारा को ख़ासी लोकप्रियता मिली है. जून 2014 में बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, वर्ष 2010 के बाद 19 से 34 वर्ष के मतदाताओं में कंजरवेटिव पार्टी को वोट देने का रुझान बढ़ा है. इसमें वे मतदाता भी शामिल हैं, जिनके माता-पिता लेबर पार्टी के वोटर हुआ करते थे.

जहां तक लेबर पार्टी का सवाल है, तो चुनाव से पूर्व यह कहा जा रहा था कि एड मिलिबन्ड के नेतृत्व में यह पार्टी अगर सबसे बड़ी पार्टी नहीं तो, कम से कम इस स्थिति में ज़रूर रहेगी कि किसी दूसरी पार्टी के समर्थन से सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए. हालांकि, स्कॉटलैंड के नतीजों ने उन सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. एक लेबर नेता ने स्कॉटलैंड में पार्टी की हार को सियासी हिमस्खलन की संज्ञा दी. दूसरे अन्य राजनीतिक समीक्षकों ने भी इसे सुनामी क़रार दिया. वर्ष 2010 के चुनाव में लेबर पार्टी को यहां 41 सीटें मिली थीं. इस चुनाव में उसे केवल एक सीट से ही संतोष करना पड़ा. दरअसल, यही वजह थी कि वेल्स और इंग्लैंड में कुछ सीटों की बढ़त के बावजूद वर्ष 2010 के मुक़ाबले में पार्टी को 26 सीटों का नुक़सान उठाना पड़ा. ज़ाहिर है लेबर पार्टी ने स्कॉटलैंड में ऐसी हार की कल्पना नहीं की होगी. कुल मिलाकर देखा जाए तो लेबर पार्टी को 30 प्रतिशत वोट मिले, जो वर्ष 2010 से एक प्रतिशत अधिक था. बावजूद इसके पार्टी को 26 सीटों का नुक़सान उठाना पड़ा.

ब्रिटेन के चुनाव में राजनीतिक दलों का प्रदर्शन

पार्टी	जीते	मत प्रतिशत
कंजरवेटिव पार्टी	331	36.9
लेबर पार्टी	232	30.4
स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी	56	4.7
लिबरल डेमोक्रेट्स	08	7.9
डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी	08	0.6
यूकेआईपी	01	12.6
अन्य	14	6.99

वर्ष 2014 में ब्रिटेन से आज़ादी के लिए स्कॉटलैंड में जनमत संग्रह कराया गया. जिसे 45 के मुक़ाबले 55 प्रतिशत लोगों ने नकार दिया. हैरानी की बात यह है कि महज़ एक साल बाद ही स्कॉटलैंड के लोगों ने देश की बड़ी पार्टियों को सिरे से ख़ारिज कर एक तरह से यह जता दिया कि स्कॉटिश राष्ट्रवाद का असर अभी ख़त्म नहीं हुआ है. एसएनपी ने वर्ष 2014 के जनमत संग्रह का समर्थन किया था. इस चुनाव में एसएनपी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है. वर्ष 2010 के चुनाव में महज़ 6 सीटें हासिल करने वाली यह पार्टी स्कॉटलैंड की कुल 59 सीटों में से 56 सीटों पर अपना क़ब्ज़ा जमा लिया है. एक सोशल डेमोक्रेट पार्टी होने के नाते एसएनपी की जीत को यूरोप में बढ़ रही दक्षिणपंथी विचारधारा से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है, लेकिन स्कॉटिश राष्ट्रवाद से ज़रूर जोड़ा जा सकता है. हालांकि, पार्टी प्रमुख निकोला स्टर्जन ने साफ़ किया कि इस जीत का मतलब स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता के लिए फिर से जनमत संग्रह कराने की संभावना से उन्होंने इंकार भी नहीं किया. बहरहाल, अगर वरिष्ठ पत्रकार एमजे अकबर की बातों पर ग़ौर करें, तो कई चुनाव सियासी तब्दीली की वजह बनते हैं, लेकिन कुछ चुनाव ऐसे होते हैं, जो क्षेत्र की भू-राजनीति को भी बदलकर रख देते हैं. स्कॉटलैंड के चुनावी नतीजे कुछ ऐसे ही थे.■

feedback@chauthiduniya.com

इस जंग का अंजाम सिर्फ़ तबाही है

वसीम अहमद

feedback@chauthiduniya.com

यमन में जारी जंग को 12 अप्रैल को पांच दिनों के लिए रोक दिया गया था. अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव में सउदी अरब युद्ध विराम पर सहमत हुआ. युद्ध विराम की अवधि खत्म हो जाने के बाद सउदी अरब एक बार फिर अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करने लग चुका है. सऊदी अरब का इस जंग में केवल एक लक्ष्य है और वह है राष्ट्रपति मंसूर हादी को सत्ता वापस लाना लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि वह अपने लक्ष्य को कैसे पूरा करेगा. हालांकि, दुनिया के विभिन्न प्रतिख़ि लोगों के अलावा बहुत से सऊदी शहज़ादों ने भी यमन पर हमलों का विरोध किया था और इसे एक निरर्थक युद्ध बताया था, लेकिन शाह सलमान पर तो जैसे युद्ध का जुनून सवार था.

ओमान के शासक शाह क़ाबूस ने सऊदी अरब के शाह सलमान को मशविरा दिया था कि वह यमन में जंग न करें क्योंकि इससे वहां अराजकता पैदा होगी. यही मशविरा तत्कालीन शासक शहज़ादा मुक़रिन और विदेश मंत्री सऊद फैसल ने भी दिया था और सुल्तान सलमान को इस जंग में नहीं पड़ने की बात कही थी. ईराक के प्रधानमंत्री हैदर अलइबादी ने भी अपने संदेश में कहा था कि इस जंग से सिवाए संकट और नफरत के और कोई नतीजा नहीं निकलेगा. लेकिन शाह सुल्तान ने इन सभी मशविरों को ख़ारिज कर दिया और यमन में जंग छेड़ दी. इस जंग में अब तक तकरीबन एक हज़ार लोगों की मौत हुई है और 2 हज़ार से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि हज़ारों लोग बेघर हुए हैं.

जंग का आग़ाज़ करने के बाद सऊदी अरब ने यमन के हवाई अड्डे से लेकर बंदरगाहों तक सभी तरह की गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक वहां फंस गए थे. इसके बाद भारत ने शाह सलमान से बात करके फंसे हुए अपने सभी नागरिकों को विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के नेतृत्व में ऑपरेशन राहत चलाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया था. सभी वायु और समुद्री रास्ते बंद होने की वजह से राहत का काम रुक गया, इस वजह से वहां खाद्य समाग्री सहित दवाईयों की गंभीर किल्लत हो गई. इस वजह से सऊदी अरब के ऊपर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा कि वह युद्ध विराम की घोषणा करे. ताकि पीड़ितों तक राहत और सहायता सामग्री पहुंचाई जा सके. आख़िरकार पांच दिनों के लिए युद्धविराम की घोषणा की गई. यह एक अस्थायी युद्धविराम था. इसके बाद सऊदी अरब दोबारा युद्ध की कार्रवाई में लग गया. लेकिन यहां सबसे जरूरी सवाल यह उठता है कि क्या सऊदी अरब इस जंग में किसी नतीजे तक पहुंच पायेगा?

विश्लेषकों का मानना है कि सऊदी अरब यमन में एक ऐसी बेवजह की जंग लड़ रहा है, जिसका अंजाम 2006 में लेबनान की सीमा पर हिज्बुल्लाह के ख़िलाफ़ लड़ी जाने वाली जंग की तरह होगा, जिसमें इज़रायल को कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी. अगर इस जंग में सऊदी अरब सैन्य दृष्टि से सफल हो भी जाता है कि और हादी मंसूर के राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाते हैं तो भी वहां से हौतियों की बुनियादें ख़त्म नहीं की जा सकती हैं और हौतियों के लड़ाके हादी मंसूर के लिए मुश्किलें पैदा करते रहेंगे, जिससे गृहयुद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है. दूसरी बात यह है कि इस जंग ने मुस्लिम दुनिया बल्कि स्वयं सऊदी अरब की जनता में सरकार को लेकर अविश्वसनीयता पैदा कर दी है. इसलिए सऊदी अरब यदि इस जंग को जीत भी जाता है तो भी इसे उसकी नैतिक हार ही समझा जायेगा.

सऊदी अरब यमन पर निरंतर हवाई हमले कर रहा है, लेकिन इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता है कि हवाई हमलों से किसी युद्ध को जीता नहीं जा सकता है. इसके लिए ज़मीनी लड़ाई जरूरी होती है. यही कारण है कि अब तक सैकड़ों हवाई हमले हो चुके हैं, लेकिन सऊदी अरब न तो हौतियों से यमन को खाली करा सका है और न ही हादी को यमन के के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा सका है, और यह उस समय तक संभव नहीं है जब तक कि सऊदी अरब की सेना ज़मीन पर उतरकर हौतियों और अंसार उल्लाह के लड़ाकों का मुक़ाबला न करे, लेकिन ज़मीन पर उतरकर लड़ना सऊदी अरब और उसके सहयोगियों के लिए बहुत मुश्किल है. क्योंकि सऊदी अरब और उसके सहयोगियों को ज़मीनी लड़ाई लड़ने का अनुभव नहीं है. हां अगर पाकिस्तान सऊदी अरब के सहयोगियों में शामिल होता तो उसे ज़मीनी जंग में सफलता मिल सकती थी. क्योंकि पाकिस्तान की सेना को जमीनी लड़ाई के लिए ट्रेंड है, लेकिन उसने सऊदी अरब का साथ देने से साफ इंकार कर दिया है. इसलिए यह कहना सही होगा कि सऊदी अरब एक ऐसी जंग लड़ रहा है जो किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पायेगी. यह जंग जब भी ख़त्म होगी तो नाकामी सऊदी अरब के ही हिस्से में आयेगी. अब यह जंग जितनी जल्दी ख़त्म या जितनी देर से खत्म होगी उसी हिसाब से नाकामी सऊदी अरब के हाथ लगेगी.

बहरहाल, इस पांच दिन के युद्धविराम पर यूरोपी देशों समेत हौतियों की ओर से भी प्रसन्नता देखने को मिली, लेकिन अब सऊदी अरब की रणनीति क्या होती है और वह जंग के इस दलदल से बाहर कैसे निकलेगा, यह सऊदी अरब के नये शासक को सोचना है. जितने अनुभवी मंत्रियों ने इस युद्ध का विरोध किया था, उन्हें शाह सलमान ने बख़ास्त करके किनारे कर दिया है और अब जिनके हाथों में देश की बागडोर है वे राजनीतिक मैदान में अनुभवहीन हैं. पूर्व शहज़ादे मुक़रिन बिन अब्दुल अज़ीज़ और सऊद फैसल, जिन्होंने ने इस जंग का विरोध किया था, उन्हें इस परिदृश्य से हटा दिया गया है. अहमद बिन अब्दुल अज़ीज़ को भी ख़ारिज कर दिया गया है. अब इस स्थिति से निबटने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जायेगी यह तो आने वाला वक्त ही बतायेगा.■

रामेश्वरम में थोड़ा ही समय बीता था कि राम और रावण का युद्ध छिड़ गया और राम जी ने सिंधु में सेतु निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया. नल और नील के नेतृत्व में बन्दर और भालू समुद्र में पत्थर डालकर सेतु बनाने लगे. यह देखकर गिलहरी भी रेत के कण उठाकर समुद्र में डालने लगी. यह छोटा सा काम था लेकिन बड़े निर्माण में छोटे से छोटे काम का महत्व होता है, यह समझकर नल नील ने उसे टोका नहीं और वह अपना काम करती रही.

साई की लीला अपरंपार है

चौथी दुनिया ब्यूरो

साई बाबा अल्पाहारी थे और वे थोड़ा बहुत जो कुछ भी खाते थे, वह उन्हें केवल दो गृहों से ही भिक्षा में उपलब्ध हो जाया करता था, लेकिन जब उनके मन में सभी भक्तों को भोजन कराने की इच्छा होती तो प्रारम्भ से लेकर अन्त तक संपूर्ण व्यवस्था वे स्वयं किया करते थे. वे किसी पर निर्भर नहीं रहते थे. वे स्वयं बाजार जाकर सब वस्तुएं नगद दाम देकर खरीद लाया करते थे. यहां तक कि पीसने का कार्य भी वे स्वयं ही किया करते थे. मस्जिद के आंगन में ही एक भट्टी बनाकर उसमें अग्नि प्रज्जवलित करके हांडी के ठीक नाप से पानी भर देते थे. कभी वे मीठे चावल बनाते, कभी-कभी दाल और मुटकुले भी बना लेते थे. पत्थर की सिल पर महीन मसाला पीस कर हांडी में डाल देते थे. भोजन रुचिकर बने, इसका वे पूरा प्रयास करते थे. ज्वार के आटे को पानी में उबाल कर उसमें छांछ मिलाकर अंबिल (आमटीं) बनाते और भोजन के साथ सब भक्तों को समान मात्रा में बांट देते थे. भोजन ठीक बन रहा है या नहीं, यह जानने के लिए वे निर्भयता से उबलती हांडी में हाथ डाल देते और उसे चारों ओर घुमाया करते थे. ऐसा करने पर भी उनके हाथ पर न कोई जलन का चिन्ह और न चेहरे पर ही कोई व्यथा की रेखा प्रतीत हुआ करती थी. जब पूर्ण भोजन तैयार हो जाता, तब वे मस्जिद में बर्तन मंगाकर मौलवी से फातिहा पढ़ने को कहते थे, फिर वे म्हालसापति तथा तात्या पाटिल का प्रसाद रखकर शेष भोजन गरीब और अनाथ लोगों को खिलाकर उन्हें तृप्त करते थे. कितने भाग्यशाली थे वे, जिन्हें बाबा के हाथ का बना और परोसा हुआ भोजन खाने का मिला. अन्नदान के बिना सभी दान वैसे ही अपूर्ण है, जैसे कि चन्द्रमा बिना तारे, भक्तिरहित भजन, सिन्दूर बिना सुहागिन, मधुर स्वरविहीन गायन, नमक बिना पकवान. जिस प्रकार अन्य भोज्य पदार्थों में दाल उत्तम समझी जाती है, उसी प्रकार समस्त दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है. साई बाबा अल्पाहारी थे और वे थोड़ा बहुत जो कुछ भी खाते थे, वह उन्हें केवल दो गृहों से ही भिक्षा में उपलब्ध हो जाया करता था, लेकिन जब उनके मन में सभी भक्तों को भोजन कराने की इच्छा होती तो प्रारम्भ से लेकर अन्त तक संपूर्ण व्यवस्था वे स्वयं किया करते थे. यहां कोई यह शंका कर सकता है कि क्या वे शाकाहारी और मांसाहारी भोज्य पदार्थों का प्रसाद सभी को बांटा करते थे. यह एक अति पुरातन अनुभूत नियम है कि जब गुरुदेव प्रसाद वितरण कर रहे हों, अगर उस समय कोई शिष्य उसे ग्रहण करने में शंकित हो जाए तो उसका पतन हो जाता है. यह अनुभव करने के लिए कि शिष्यगण इस नियम का किस अंश तक पालन करते हैं, वे कभी-कभी परीक्षा भी ले लिया करते थे. उदाहरणार्थ एकादशी के दिन उन्होंने दादा केलकर को कुछ रुपये देकर मांस खरीद लाने को कहा. दादा केलकर पूरे कर्मकांडी थे और प्रायः सभी नियमों का जीवन में पालन किया करते थे. उनकी यह दृढ़ भावना थी कि द्रव्य, अन्न और वस्त्र इत्यादि गुरु को

भेंट करना पर्याप्त नहीं है. केवल उनकी आज्ञा ही शीघ्र कार्यान्वित करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं. यही उनकी दक्षिणा है. दादा शीघ्र कपड़े पहन कर एक थैला लेकर बाजार जाने के लिए तैयार हो गए. तब बाबा ने उन्हें वापस बुला लिया और कहा कि तुम न जाओ, अन्य किसी को भेज दो. दादा ने अपने नौकर पांडू को इस कार्य के निमित्त भेजा. उसको जाते देखकर बाबा ने उसे भी वापस बुलाने को कहकर यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया. ऐसे ही एक अन्य अवसर पर उन्होंने दादा से कहा कि देखो तो नमकीन पुलाव कैसा पका है. दादा ने यों ही मुंह देखी और कह दिया कि अच्छा है. तब वे कहने लगे कि तुमने न अपनी आंखों से ही देखा है और न जिह्वा से स्वाद लिया, फिर तुमने यह कैसे कह दिया कि उत्तम बना है. थोड़ा ढक्कन हटाकर तो देखो. बाबा ने दादा की बांह पकड़ी और बलपूर्वक बर्तन में डालकर बोले-थोड़ा सा इसमें से निकालो और अपना कट्टरपन छोड़कर चख कर देखो. जब मां का सच्चा प्रेम बच्चे पर उमड़ आता है, तब मां उसे दुलारती है, परन्तु उसका चिल्लाना या रोना देखकर वह उसे अपने हृदय से लगाती है. इसी प्रकार बाबा ने सात्विक मातृ प्रेम के वश होकर दादा का इस प्रकार हाथ पकड़ा. यथार्थ में कोई भी सन्त या गुरु कभी भी अपने कर्मकांडी शिष्य को वर्जित भोज्य के लिए आग्रह करके अपनी अपकीर्ति कराना पसन्द नहीं करेगा. साई भक्तों! आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें. इस प्रकार यह हांडी का कार्यक्रम सन 1910 तक चला और फिर स्थगित हो गया. दासगणू ने अपने कीर्तन द्वारा समस्त मुंबई प्रांत में बाबा की अधिक कीर्ति फैली. फलतः इस प्रान्त से लोगझुंड के झुंड शिरडी आने लगे और थोड़े ही दिनों में शिरडी पवित्र तीर्थ-क्षेत्र बन गया. भक्तगण बाबा को नैवेद्य अर्पित करने के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ लाते थे, जो इतनी अधिक मात्रा में एकत्र हो जाता था कि फकीरों और भिखारियों को सन्तोषपूर्वक भोजन कराने पर भी बच जाता था. साई की लीला अपरंपार है और उनके दर से कोई खाली नहीं जाता. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

रिश्वत पर रोक लगे

सभी सियासी पार्टियां मतदाताओं को लूभाने के लिए अनेक लोक लूभावन घोषणाएं करती हैं, लेकिन कीमती उपहार के बदले वोट मांगना तो सरासर बेईमानी है. दक्षिण भारत में तो राजनेताओं द्वारा वोटर्स के घर पर्चियों के साथ लिफाफे में रखकर नकद राशि भिजावाई जाती है. कांग्रेस स्वयं कर्जमाफी कर लोकसभा चुनाव जीत चुकी है. यह बात अलग है कि इसके बहुत दूरगामी दुष्परिणाम निकले. लोग अब कर्ज लेकर वापस नहीं करते. तमिलनाडु में प्रत्याशियों ने मतदाताओं को कलर टी.वी व मिक्सी देने का वादा कर चुनाव में जीत हासिल की. चुनाव में कोई दल मुफ्त बिजली का वादा करता है तो कोई मुफ्त सिचाई की और कोई दल लैपटॉप बांट रहा है. यह एक तरह का वोट के बदले रिश्वत ही है. सर्वोच्च न्यायालय को इस रिश्वत पर रोक लगानी चाहिए.

-राजकिशोर पांडेय, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.

प्रकृति से छेड़छाड़ बंद हो

नेपाल में आए भूकंप के बाद से धरती कई बार कांप चुकी है. 12 मई को एक बार फिर लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए. धरती का बार कांपना कोई बड़े खतरे की ओर इशारा तो नहीं कर रहा है. यह इंसान द्धारा प्रकृति से लगातार छेड़छाड़ का नतीजा ही है. चाहे वो उत्तराखंड में आई तबाही हो या नेपाल में भूकंप से आई त्रासदी. इसानों द्धारा लगातार प्रकृति का दोहन हो रहा है. पेड़ों का काटना, पहाड़ो का खोदना और नदियों पर बड़े-बड़े बांध बनाकर अप्रकृतिक तरीके से जल रोकना. इसी का नतीजा है कि कभी भूकंप से तबाही, तो कभी जल प्रलय से तबाही मच रही है. इसलिए इंसान को प्रकृति से छेड़छाड़ बंद करना चाहिए, नहीं तो इसके भयंकर परिणाम भुगतने होंगे.

-हिमांशु सिंह, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.

वादों पर अमल करे सरकार

भूमि अधिग्रहण बिल के साथ कई मुद्दों को लेकर विपक्ष संसद में हंगामा करता नजर आया. लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही अधिकतर हंगामें के कारण बाधित रहती है. विपक्ष केवल संसद में अपनी राजनीति चमकाने के लिए हंगामा करता है. उसे जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है. अगर केन्द्र सरकार का भूमि अधिग्रहण बिल किसान विरोधी है तो इस पर विपक्ष को सही तथ्यों के साथ संसद में चर्चा करनी चाहिए न की हो हल्ला मचाना चाहिए. विपक्षी सांसद जनता से जुड़े मुद्दे उठाने के बजाय केवल हंगामा करते नजर आते हैं. बेरजोगारी, मंहागाई और कई सारे जनता से जुड़े ऐसे मुद्दे थे जिसे लेकर संसद में विपक्ष को सरकार से सवाल करने चाहिए थे. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि उनकी सरकार 100 दिन के भीतर मंहगाई को कम कर देगी, लेकिन महंगाई कम होने के बजाय एक साल में और बढ़ गई. इसलिए सरकार अपने वादों पर अमल करें और विपक्ष सच्चाई के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाए.

-राहुल यादव, बक्सर, बिहार.

तथ्यपरक समाचार पत्र

चौथी दुनिया समाचार पत्र में प्रकाशित सभी खबरें तथ्यों पर आधारित होती हैं. यह समाचर पत्र पढ़कर सबसे अधिक खुशी होती है कि साप्ताहिक होने के बावजूद भी इसमें पूरे सप्ताह की खबरें पढ़ने को मिल जाती है. साथी उत्तर प्रदेश और बिहार की जो खबरें अन्य समाचार पत्रों में पढ़ने को नहीं मिलती हैं, वह चौथी दुनिया सामाचार पत्र में पढ़ने को मिल जाती हैं. समाचार पत्र में प्रकाशित कवर स्टोरी में हमेशा नई जानकारी होती है. चौथी दुनिया समाचार पत्र हमेशा जनहित के मुद्दों को उठाता रहा है और हमे उम्मीद है कि हमेशा ऐसे ही जनता से जुड़े मुद्दों को उठाता रहेगा.

-रवि वर्मा, दरभंगा, बिहार.

अपनी ही चिंता है

जब तोप मुकाबिल हो-माननीयों, इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा(11 मई-17 मई 2015)का अंक पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. संतोष भारतीय से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जिस तरह से हमारी संसद देश के हितों के प्रति असंवेदनशील हो गई है, उसे देखकर लगता है कि देश की चिंता से ज़्यादा सांसदों को अपनी चिंताएं हैं. सांसद केवल किसी विषय पर बहस से ज्यादा लोकसभा हो या राज्यसभा दोनों जगहों पर हंगामा करते हैं. उन्हें सच में जनता से कोई मतलब नहीं है. अगर हम संसद सत्र की बात करें तो हम टेलीविजन पर देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही लंच के बाद खाली नजर आती हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण समय होता है. जिस समय सांसदों संसद में होना चाहिए और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना चाहिए और सवाल करने चाहिए. वह उस समय वहां से नदारद रहते हैं. सांसदों को जनता अपने प्रतिनिधि के तौर पर संसद में भेजती है, लेकिन सांसद जनता के ही सवालों को संसद में नहीं उठाते है. सांसदों को अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए जो जनता ने उन्हें सौंपा है.

-सुचित्रा कुमारी, द्वारका, नई दिल्ली.

श्रम का पुरस्कार

चौथी दुनिया ब्यूरो

बहुत दिनों पहले की बात है, गिलहरी पूरी तरह काली हुआ करती थी. छोटी-छोटी झाड़ियों के बीच, घास के मैदानों में, ऊंचे बड़े पेड़ों पर रेंगती फिरती कूदती फांदती लेकिन लोग उसे सुंदर प्राणी नहीं समझते थे. गिलहरी को गांव के परिवारों के साथ रहना पसंद था लेकिन गांव वाले उसे पसंद नहीं करते थे. वह घरों में पहुंच जाती तो बच्चे डर जाते और लोग उसे भगाने लगते.

गांव में एक आश्रम था जिसमें साधू बाबा रहते थे. गिलहरी उनके पास रहने लगी. जो बाबा खाते वह गिलहरी खाती, जो वे यज्ञ हवन करते उसकी साक्षी बनती और जो वे जप मंत्र पढ़ते उसके पुण्य का लाभ उठाती. धीरे धीरे गिलहरी बीज, कंद और मूल खाने वाली साध्वी बन गई. कुछ समय बाद बाबा रामेश्वरम की तीर्थयात्रा पर निकले तो वह गिलहरी भी उनके साथ हो ली. रामेश्वरम के समुद्र तट पर बाबा ने जहां डेरा डाला वहीं किसी पेड़ पर एक कोटर में गिलहरी ने भी अपना घर बना लिया.

रामेश्वरम में थोड़ा ही समय बीता था कि राम और रावण का युद्ध छिड़ गया और राम जी ने सिंधु में सेतु निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया. नल और नील के नेतृत्व में बन्दर और भालू समुद्र में पत्थर डालकर सेतु बनाने लगे. यह देखकर गिलहरी भी रेत के कण उठाकर समुद्र में डालने लगी. यह छोटा सा काम था लेकिन बड़े निर्माण में छोटे से छोटे काम का महत्व होता है, यह समझकर नल नील ने उसे टोका नहीं और वह अपना काम करती रही. भगवान राम भी उसे चुपचाप काम करते देखते. जिस दिन पुल का निर्माण पूरा हुआ, उस दिन, नन्हीं सी गिलहरी द्वारा प्रदर्शित उत्तरदायित्व, लगन और श्रम की भावना को पुरस्कृत करने के लिये भगवान राम ने उसे अपने हाथों में उठाया और आशीर्वाद से भरी अपनी अंगुलियों को उस पर फेरा.

आश्चर्य ! भगवान राम के हाथ और ऊंगलियों के निशान जहां लगे वहां का रंग भगवान की त्वचा जैसा साँवला हो गया और वह अत्यंत आकर्षक दिखाई देने लगी. कहते हैं तभी से गिलहरी की

गणना सुंदर प्राणियों में होने लगी. गांव के बच्चे उसे देखकर खुश हो जाते, उसे बगीचों से कोई नहीं भगाता और लोग उससे खूब प्रेम करते. गिलहरी को मिले इस वरदान से उसके आगे की संतति भी सुंदर हुई. अंत में जब सेतु निर्माण का इतिहास लिखा गया तब हर कवि और रचनाकार ने उस नन्हीं गिलहरी का उल्लेख अपनी रचना में किया. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

क्रांतिवीर मार्क्सवादियों की हक़ीक़त

अनंत विजय

कार्ल मार्क्स. मार्क्सवाद. ये दो शब्द ऐसे हैं, जो भारत में बुद्धिजीवियों के एक बड़े तबके को बहुत लुभाते हैं. इन दो शब्दों के रोमांटिसिज्म में वे इसके आकलन में वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाते हैं. तमाम धाराओं को इन दो शब्दों की धारा में बहाने का दुराग्रह करते चलते हैं. आलोचना से लेकर रचना तक की कसौटी का मूल आधार यही दो शब्द रहते हैं. अभी हाल ही में कार्ल मार्क्स की एक सौ सत्तानवीं जयंती बीती है. इस मौक़े पर एक बार फिर से उनकी महानता का गुणगान करते हुए लेख छपे, भाषण दिए गए. सोशल मीडिया पर इस विचारधारा के अनुयायियों ने जमकर अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन किया. मार्क्सवाद एक अवधारणा के तौर पर, एक आदर्शवादी सिद्धांत के तौर पर बहुत अच्छा कहा या माना जा सकता है, लेकिन शुरुआत से लेकर अब तक मार्क्सवाद की जो व्यवहारिकता सामने आई है, उस पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया. मार्क्सवाद की जो अवधारणा है, उसमें धर्म को अफीम कहा गया है. यह लाइन इसके अनुयायियों को बहुत भाती है. वे लगातार इसका प्रचार करते हैं और इस लाइन के आधार पर धर्म को भला–बुरा कहते चलते हैं.

धर्म को अफीम मानने वाले यह भूल जाते हैं कि धर्म लोगों को एक मर्यादा में रहना भी सिखाता है. मार्क्सवाद की जो अवधारणा है, वह पूंजीवाद का निषेध करती है, लेकिन परोक्ष रूप से पूरे तौर पर भौतिकतावाद की वकालत करती है. वहां परिवार या सामाजिक बंधन या मान्यता नामक चीजें अमान्य हैं. सोवियत रूस में जब वर्ष 1917 में क्रांति हुई, तो यह मान्यता प्रचारित की गई कि शादी–विवाह आदि का कोई अर्थ नहीं है. जब जिसका मन करे, वह किसी से भी संबंध बनाए. यह भौतिकतावाद की ही एक मिसाल है. लगभग बीस सालों तक सोवियत रूस में यह बात चलती रही. आपको यह याद दिला दें कि 1917 से लेकर 1930 तक सोवियत रूस में एक गिलास पानी मुहावरा काफी प्रचलित था. यह उस बात के लिए कहा जाता था कि जब प्यास लगे, तो पानी पी लो और जब शरीर की मांग हो, तो उसे किसी के भी साथ पूरा कर लो. क़रीब बीस वर्षों तक रूस में यह चलता रहा और फिर धीरे–धीरे इस अवधारणा को बगैर किसी शोर–शराबे के दफन कर दिया गया.

मार्क्स के दो बड़े भारी अनुयायी हुए. एक तो चीन के माआत्सेतुंग और दूसरे क्यूबा के सर्वेसर्वा फिडेल कास्ट्रो. फिडेल

सोवियत रूस में जब वर्ष 1917 में क्रांति हुई, तो यह मान्यता प्रचारित की गई कि शादी-विवाह आदि का कोई अर्थ नहीं है. जब जिसका मन करे, वह किसी से भी संबंध बनाए. यह भौतिकतावाद की ही एक मिसाल है. लगभग बीस सालों तक सोवियत रूस में यह बात चलती रही. आपको यह याद दिला दें कि 1917 से लेकर 1930 तक सोवियत रूस में एक गिलास पानी मुहावरा काफी प्रचलित था. यह उस बात के लिए कहा जाता था कि जब प्यास लगे, तो पानी पी लो और जब शरीर की मांग हो, तो उसे किसी के भी साथ पूरा कर लो.

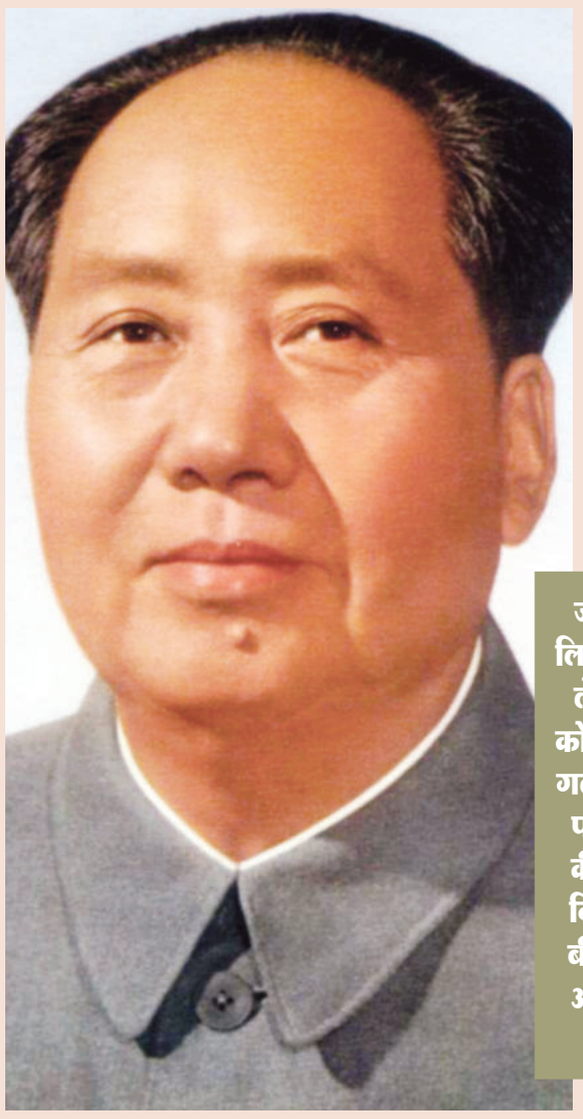

हालांकि पहले मार्क्सवादी नहीं थे, लेकिन बाद में सोवियत रूस से लेकर तमाम वामपंथी देशों ने सहयोग आदि देकर उन्हें अपने पाले में ले लिया. कालांतर में वह और उनका देश दोनों कम्युनिस्ट बन गए और वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा के 1961 से लेकर 2011 तक महासचिव रहे. इन दोनों के बारे में वामपंथी बहुत उच्च विचार रखते हैं. एक समय में तो हमारे देश में चेयरमैन माओ के समर्थन में नारे लगाने वाले भी खुलेआम मिल जाया करते थे. फिडेल कास्ट्रो में भी वामपंथी लगभग मूर्ति पूजा की हद तक आस्था रखते हैं. सवाल यही है कि किसी के व्यक्तित्व और कृतित्व का मूल्यांकन क्या भक्ति भाव के साथ किया जा सकता है? क्या किसी को आलोचना से ऊपर मानकर उसका मूल्यांकन किया जा सकता है? नहीं. भारत में हमारे वामपंथी बौद्धिकों ने माओ से लेकर कास्ट्रो तक का मूल्यांकन भक्ति भाव के साथ किया. लिहाजा, उन्हें उनके व्यक्तित्व में कोई खामी, उनके कार्यों में कोई कमी, उनके चरित्र में कोई खोट आदि दिखाई ही नहीं दिया. इस तरह की हर बात को षड्यंत्र पूर्वक दबा दिया गया.

धर्म को अफीम मानने वाले लोगों की अपने वैचारिक गुरुओं में इस तरह की आस्था उन्हें बौद्धिक रूप से लगातार बेईमान बनाती रही. भारत में इस तरह की बौद्धिक बेईमानी का खेल दशकों तक चलता रहा. कम्युनिस्टों को या वामपंथ में आस्था रखने वाले साहित्यकारों, लेखकों को साहित्य में बहुत ऊपर का दर्जा दिया गया, जबकि वामपंथ की परिधि से बाहर लेखन करने वालों को, भारतीय परंपरा, धर्म, पौराणिक कथाओं और मिथकों पर लिखने वालों को लगातार हाशिये पर रखा गया. ये सब एक सोची–समझी रणनीति के तहत किया गया. साहित्य में इस तरह की राजनीति करने वालों की पहचान करना आवश्यक है. खैर, हम वापस मार्क्सवाद के दो पुरोधाओं की ओर लौटते हैं. माओ और फिडेल कास्ट्रो. मैंने अभी हाल ही में इन दोनों पर कई किताबों और किताबों के अंशों का अध्ययन किया. जैसे माओ पर लिखी जंग चांग की किताब–द अननोन स्टोरी ऑफ माओ और फिडेल पर लिखी ब्रायन लैटल की किताब–कास्ट्रोज सीक्रेट, द सीआईए एंड क्यूबाज इंटेलिजेंस मशीन. इन दो किताबों के अलावा 1998 में वेंडी गिंबेल की एक किताब आई थी–हवाना ड्रीम्स, उसमें भी कास्ट्रो पर लिखा गया है.

अभी हाल ही में एक किताब आई है–द डबल लाइफ ऑफ फिडेल कास्ट्रो. इस किताब के लेखक हैं सत्रह वर्षों तक उनके अंगरक्षक रहे जुआन रियेनाल्डो सांचेज. इन सभी किताबों के लेखक अलग–अलग विचारधारा और पृष्ठभूमि के हैं. इन सारी किताबों या इनके अंशों को पढ़ने के बाद एक साझा सूत्र, जो इन दोनों मार्क्स के अनुयायियों को जोड़ता है, वह यह है कि दोनों लगभग तानाशाह थे. दोनों अपने विरोधियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे. दोनों को अपने विरोधियों को निबटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में कोई गुरेज नहीं था. दोनों की सेक्सुअल लाइफ बेहद रहस्यमयी थी. दोनों अपने लिए बेशुमार दौलत इकट्ठा करना चाहते थे. अब एक प्रसंग माओ के बारे में देखिए. जब अक्टूबर, 1941 में वांग मिंग ने माओ को लेख लिखकर चुनौती दी, तो माओ भन्ना गए. उन्होंने उनके लेखों को छपने से रोक दिया. मिंग ने अपने विचारों को पोस्टर के तौर पर प्रचारित किया. यह बात माओ के गले नहीं उतर रही थी. वह रात में बाहर निकल कर उन पोस्टरों को पढ़ने वालों की संख्या देखते थे.

पोस्टरों की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा कर उन्होंने मिंग को निबटाने की योजना बनाई. एक दिन अचानक मिंग बीमार पड़ते हैं और अस्पताल में भर्ती होते हैं. माओ ने अपनी पॉयजनिंग यूनिट के डॉक्टर जिन म्याओ को वांग मिंग के इलाज के लिए नियुक्त किया. उन्होंने मिंग के लिए कई ऑपरेशन सुझाए, लेकिन वे ख़तरनाक होने की वजह से नहीं हो पाए. जब मिंग को अस्पताल से छुट्टी दी जानी थी, तब डॉ. जिन ने उन्हें गोली खिलाई, जिसके बाद वह बीमार पड़ गए. बाद में जांच में पता चला कि यह मरकरी पॉयजनिंग का केस था. परिदृश्य पर एक रूसी डॉक्टर के आने के बाद यह बात खुली. इसी तरह से माओ ने सांस्कृतिक क्रांति के दौर में सिनेमा पर प्रतिबंध लगा दिया. 1950 में वहां 39 फीचर फिल्में बनीं, लेकिन दो साल बाद यह संख्या घटकर सिर्फ़ दो रह गई. सांस्कृतिक स्वतंत्रता की वकालत करने वाले इन माओ के समर्थकों ने इतिहास बोध को खूंटी पर टांग दिया है, ऐसा लगता है.

इसी तरह से अगर हम देखें, तो फिडेल कास्ट्रो के चेहरे से भी क्रांतिकारी नायक का नकाब लगातार उतरता चला जाता है.

जब अक्टूबर, 1941 में वांग मिंग ने माओ को लेख लिखकर चुनौती दी, तो माओ भन्ना गए. उन्होंने उनके लेखों को छपने से रोक दिया. मिंग ने अपने विचारों को पोस्टर के तौर पर प्रचारित किया. यह बात माओ के गले नहीं उतर रही थी. वह रात में बाहर निकल कर उन पोस्टरों को पढ़ने वालों की संख्या देखते थे. पोस्टरों की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा कर उन्होंने मिंग को निबटाने की योजना बनाई. एक दिन अचानक मिंग बीमार पड़ते हैं और अस्पताल में भर्ती होते हैं. माओ ने अपनी पॉयजनिंग यूनिट के डॉक्टर जिन म्याओ को वांग मिंग के इलाज के लिए नियुक्त किया.

फिडेल कास्ट्रो ने शादीशुदा होते हुए भी एक शादीशुदा महिला से न केवल संबंध बनाए, बल्कि उसके एक बच्चे के पिता भी बने. नटालिया नामक उक्त महिला और कास्ट्रो के बीच के प्रेम पत्रों के सार्वजनिक होने के बाद इस विवाहेत्तर संबंध का खुलासा हुआ. अब से चंद महीने पहले नटालिया की मौत हुई और उसे इस बात का मलाल था कि जिस शख्स ने 1953 में आक्रमण की रणनीति उनके घर पर रहकर बनाई, वही शख्स जब दो साल बाद क्यूबा की सत्ता पर काबिज होता है, तो उसे भूल जाता है. भूल तो वह अपनी बेटी को भी जाता है. यह मार्क्सवाद की एक गिलास पानी वाली अवधारणा का निकृष्टतम रूप है. अब उससे भी ख़तरनाक बात सामने आई है. सत्रह वर्षों तक क्यूबा के राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो के अंगरक्षक रहे जुआन रियेनाल्डो सांचेज की ताजा किताब–द डबल लाइफ ऑफ फिडेल कास्ट्रो ने यह खुलासा किया है कि किस तरह से कास्ट्रो ने एक ड्रग्स कारोबारी को पचहत्तर हज़ार डॉलर के एवज में क्यूबा में ऐश करने की अनुमति दी. इस किताब में इस बात के पर्याप्त सुबूत दिए गए हैं कि किस तरह से फिडेल कास्ट्रो अपने सीक्रेट रूम में बैठकर कोकीन कारोबारी के बारे में सौदेबाजी कर रहे थे. इस किताब के लेखक ने इस बात का भी खुलासा किया है कि कास्ट्रो की हवाना में बीस आलीशान कोठियां हैं, वह एक कैरेबियन द्वीप के भी मालिक हैं. इस तरह के खुलासों से साफ़ है कि मार्क्सवाद की आड़ में उनके रहनुमा रहस्यमयी सेक्सुअल लाइफ से लेकर तमाम तरह की भौतिकवादी प्रवृत्तियां अपनाते हैं और विचारधारा की आड़ में व्यवस्था बदलने का सपना दिखाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

विवेक भटनागर की चार ग़ज़लें

उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बंथरा क्षेत्र में 11 जनवरी, 1968 को जन्मे विवेक भटनागर हिंदी ग़ज़ल के सशक्त हस्ताक्षर हैं. उनकी ग़ज़लें समय–समय पर देश के प्रतिष्ठित पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं. वह हिंदी अकादमी दिल्ली समेत विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मानित हो चुके हैं.

(एक)

दिल पे तुम जब भी मेरे दोस्त कहानी लिखना
अपनी हर बात का, हर लफ्ज का मानी लिखना
किसी बेबस, किसी विधवा की जवानी लिखना
किस तरह बहता है, इस दरिया का पानी लिखना
लिखना मां–बाप के माथे की शिकन का मतलब
कैसे होती है कोई बेटी सयानी लिखना
अपनी यादों को करीने से लगा लेने दो
फिर इसके बाद कोई बात पुरानी लिखना

तुमको हर सिम्त उजालों के मक़ां दीखेंगे
लेकिन अंदर के अंधेरों की जुबानी लिखना

(दो)

रात मेरे सूर्य के हाथों जिबह होगी
मेरा दावा है कि अब निश्चित सुबह होगी
धूप की पगड़ी पहन कर कितना भी ऐंठे
वृक्ष के चरणों में छाया की जगह होगी
आपके कालीन की तारीफ़ भी होगी तभी
पांव नंगे और धरती की सतह होगी

देखते ही चांद को तूफान–सा उठा
दिल समंदर होने की कुछ तो वजह होगी

(तीन)

नफ़रत के दाग धो के कमीजें सुखाइए
पर सिलसिला ये रोज–रोज मत चलाइए
कमरों के बीच–बीच न दीवार उठाइए
कमरों की दीवारों में झरोखे लगाइए
हम अपने अक्स–ए–रुख से वाकिफ हैं बखूबी
अंधों को जा के आईना बेशक दिखाइए

नंगे थे कल हमाम में दो–चार ही केवल
अब तो सरे बाज़ार सभी को गिनाइए

(चार)

शाम से ज़्यादा थकी है दोपहर
है यही शायद छलावों का नगर
जानवर में आदमीयत आ गई
आदमी अब हो गया जानवर
मंच पर जब मौन खलनायक हुआ
लेखनी नायक हुई बनकर अधर
छू लिया ज्यों ही व्यवस्था ने भवन
झर गया त्यों सभ्यता का प्लास्तर
यह ज़रूरी है कि दर्पण साफ़ हो
क्या ज़रूरी रूप भी होगा सुघर
मूक का संवाद बहरे से हुआ
देश को ले जाएं आख़िर हम किधर
सत्य अपमानित हुआ करता रहेगा
झूठ पर लगती रही जब तक मुहर

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
CHAUTHI DUNIYA
چوتھی دنیا
First International Urdu Weekly

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

> पावर बैंक में बैटरी इंडिकेटर लेड हैं और यह ओवरचार्जिंग और ओवरहीटिंग से सुरक्षा भी देता है. इसके बॉक्स में वनप्लस पावर बैंक और एक यूएसबी केबल है. यह वनप्लस वन स्मार्टफोन्स की तरह सिल्क वाइट और सैंडस्टोन ब्लैक रंगों में उपलब्ध होगा.

यामाहा ने पेश किया फैसिनो

यामाहा इंडिया ने एक नया स्कूटर लॉन्च किया है. कंपनी का कहना है कि इस स्कूटर की डिजाइन मॉडर्न और रेट्रो का अच्छा कॉम्बिनेशन है और यह नया स्कूटर इंडियन यूथ को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया है. नए स्कूटर में एयर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक 113सीसी इंजन लगा हुआ है, जिससे 7 बीएचपी की ताकत और 8.1 एनएम का टॉर्क मिलता है. कंपनी का दावा है कि यह अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला स्कूटर है और ऐसा इसके हल्के वजन (103 किलोग्राम) और यामाहा की ब्लू कोर टेक्नॉलजी के कारण है. कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर 66 किमी/लीटर का माइलेज देता है. फैसिनो नाम के इस स्कूटर की कीमत कंपनी ने 52,500 रुपये है. ■

कंपनी का दावा है कि यह अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला स्कूटर है, और ऐसा इसके हल्के वजन (103 किलोग्राम) और यामाहा की ब्लू कोर टेक्नॉलजी के कारण है. कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर 66 किमी/लीटर का माइलेज देता है.

फूजीफिल्म ने चार नए कैमरे लॉन्च किए

फूजीफिल्म ने अपनी नई इंस्टैक्स सीरीज के चार कैमरे लॉन्च किए हैं. इन कैमरे के मॉडल मिनी 8, मिनी 25, मिनी, 50एस और मिनी 90 है. इनकी खास बात ये है कि ये फोटो को तुरंत प्रिंट कर सकते हैं. कंपनी ने भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखते हुए इन कैमरे की रेंज को 6,441 रुपये से शुरु किया है. इस सीरीज के बेस्ट कैमरा की कीमत 10,999 रुपये है. कंपनी ने अपने इंसटैक्स मिनी 8 को कॉम्पेक्ट डिजाइन में पेश किया है. देखने में इसका मॉडल किसी खिलौने की तरह है. कंपनी ने इस कैमरे को 7 कलर में पेश किया है, जिनमें ब्लैक और व्हाइट कलर भी शामिल हैं. डिफरेंट मोड्स में भी यूजर्स ब्राइटनेस को एडजेस्ट कर सकता है. दूसरी तरफ, मिनी 25 भी स्टाइलिश लुक में आ रहा है. यूजर्स इस कैमरे से सेल्फी ले सकते हैं. साथ ही, उसका प्रिंट भी ले सकते हैं. इस कैमरे में सेल्फ टाइमर मोड भी दिया गया है. इसके साथ इसमें 90 स्पोर्ट्स और क्लासिक/रेट्रो लुक भी दिए गए हैं. कंपनी ने कैमरे के फ्लैश को भी पावरफुल बनाया है.

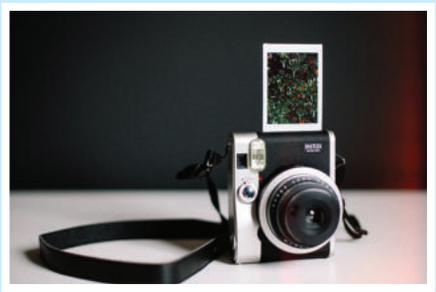

कंपनी ने अपने इंसटैक्स मिनी 8 को कॉम्पेक्ट डिजाइन में पेश किया है. देखने में इसका मॉडल किसी खिलौने की तरह है. कंपनी ने इस कैमरे को 7 कलर में पेश किया है, जिनमें ब्लैक और व्हाइट कलर भी शामिल हैं. डिफरेंट मोड्स में भी यूजर्स ब्राइटनेस को एडजेस्ट कर सकता है.

फूजीफिल्म के इन कैमरे की कीमत :-

मॉडल	कीमत
मिनी 8	6,441 रुपये
मिनी 25	8,045 रुपये
मिनी 50एस	9,147 रुपये
मिनी 90	10,999 रुपये

कंपनी ने कहा कि इन कैमरों को यूथ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. साथ ही, इनकी कीमत भी इनके मुताबिक भी तय की गई है. इन चारों कैमरे में कुछ ना कुछ अलग है, जो यूजर्स को पंसद आ सकता है. साथ ही, कंपनी इस डिवाइस पर 1 साल की वारंटी भी दे रही है. ■

वनप्लस ने पावर बैंक लॉन्च किया

वनप्लस ने अपना पावर बैंक लॉन्च किया है. वनप्लस पावर बैंक की कैपसिटी 10,000 एमएएच की है. वनप्लस पावर बैंक में दो यूएसबी पोर्ट्स हैं जिनसे एक-साथ दो डिवाइसेज चार्ज किए जा सकते हैं. यह खुद चार्ज होने के लिए करीब साढ़े 5 घंटे लेता है. इसके डायमेंशन्स 142.8x72.6x16.2 एमएम और वजन 220 ग्राम है. पावर बैंक में बैटरी इंडिकेटर लेड हैं और यह ओवरचार्जिंग और ओवरहीटिंग से सुरक्षा भी देता है. इसके बॉक्स में वनप्लस पावर बैंक और एक यूएसबी केबल है.
यह वनप्लस वन स्मार्टफोन्स की तरह सिल्क वाइट और सैंडस्टोन ब्लैक रंगों में उपलब्ध होगा. इसकी कीमत 1,399 रुपये रखी गई है. ■

ऑडी आरएस7 स्पोर्ट्सबैक का अपडेटेड वर्जन लॉन्च

ये कार महज 3.9 सेकेंड में 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है. हालांकि टॉप स्पीड के मामले में कंपनी ने तीन ऑप्शन दिए हैं, जिसमें 250 किलोमीटर/घंटा, 280 किलोमीटर/घंटा और 305 किलोमीटर/ घंटा शामिल है. जाहिर है आप जितना तेज भागेंगे आपको उसी हिसाब से ईंधन भी खर्च करना होगा.

ऑडी ने आरएस7 स्पोर्ट्सबैक का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है. आरएस7 के इस परफॉर्मेंस वर्जन में कई नए फीचर्स शामिल किए गए हैं. इस कार में एयर सस्पेंशन के साथ-साथ डायनेमिक राइड कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है. साथ ही स्पोर्ट्स मोड के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाइजेशन कंट्रोल भी दिया गया है. अगर कार के इंजन की बात करें तो ये शानदार कार 4.0 लीटर टीएफएसआई बीआई-टर्बो वी8 इंजन से लैस है जो 560बीएचपी और 700 एनएम टॉर्क की ताकत देता है. ये कार महज 3.9 सेकेंड में 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है. हालांकि टॉप स्पीड के मामले में कंपनी ने तीन ऑप्शन दिए हैं, जिसमें 250 किलोमीटर/घंटा, 280 किलोमीटर/घंटा और 305 किलोमीटर/ घंटा शामिल है. जाहिर है आप जितना तेज भागेंगे आपको उसी हिसाब से ईंधन भी खर्च करना होगा. बाहरी बनावट की बात करें तो इसमें नया बंपर और मैट्रिक्स लेड हेडलैंप लगाया गया है. साथ ही आरएस ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाया गया है. इसमें एमएमआई टच के साथ एमएमआई नैविगेशन प्लस की सुविधा भी दी गई है. कार में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया गया है. इस कार की कीमत 1.4 करोड़ रुपये रखी गई है. ■

ब्लैकबेरी का स्मार्टफोन लीप

ब्लैकबेरी ने अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन लीप भारतीय बाजार में लॉन्च किया है. यह स्मार्टफोन सिंगल सिम है, जो कंपनी के बीबी10 ऑपरेटिंग सिस्टम (वर्जन 10.3.1) पर काम करता है. इसका डिस्प्ले 5 इंच है, जो एचडी(720x1280 रेजोल्यूशन) क्वालिटी देता है. साथ ही, ये 294 पिक्सल प्रति इंच डेन्सिटी भी देता है. फोन में 1.5 गीगाहर्ट्ज डुअल-कोर प्रोसेसर है. इसके साथ, इसमें 2जीबी रैम दी गई है. फोन में 8 मेगापिक्सल ऑटोफोकस रियर कैमरा लेड फ्लैश के साथ है. वहीं, फ्रंट कैमरा 2 मेगापिक्सल है. फोन की इंटरनल मेमोरी 16जीबी है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 128 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, वाई-फाई डायरेक्ट, ब्लूटुथ के ऑप्शन दिए गए हैं. साथ ही, एंटरटेनमेंट के लिए एफएम रेडियो भी है. आज हर इंसान के पास खुद का मोबाइल है. इन मोबाइल में दर्ज जानकारी को पर्सनल और कॉरपोरेट डाटा हैकर्स से बचाना बड़ी चुनौती है. ऐसे में, हर कोई मोबाइल सिक्युरिटी चाहता है. ब्लैकबेरी लीप में वो सारी खूबियां हैं जो एक प्रोफेशनल को चाहिए. इसकी बैटरी 2800 एमएएच की है. फोन में लाइट सेंसर भी दिए गए हैं. इस फोन की कीमत कंपनी ने 21490 रुपये रखी है. ■

गर्लफ्रेंड से बिछड़ गए टाइगर वुड्स

लिंडसे वोन ने अपने फेसबुक वाल पर कहा कि यह फैसला दोनों ने आपसी सहमति से लिया. वोन ने लिखा कि मैंने टाइगर के साथ शानदार समय बिताया. दुर्भाग्य से हम दोनों अपनी-अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि एक दूसरे के साथ अधिक समय नहीं गुजार पाते. टाइगर और उनका परिवार मेरे दिल में हमेशा खास जगह रखेगा.

पूर्व विश्व नंबर एक गोल्फ़र टाइगर वुड्स और उनकी गर्लफ्रेंड लिंडसे वोन ने अलग होने का ऐलान कर दिया. लिंडसे अमेरिका की स्कीइंग ओलंपिक चैंपियन हैं. दोनों ने अलगाव के लिए अपनी व्यस्त दिनचर्या को जिम्मेदार बताया.

लिंडसे वोन ने अपने फेसबुक वाल पर कहा कि यह फैसला दोनों ने आपसी सहमति से लिया. वोन ने लिखा कि मैंने टाइगर के साथ शानदार समय बिताया. दुर्भाग्य से हम दोनों अपनी-अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि एक दूसरे के साथ अधिक समय नहीं गुजार पाते. टाइगर और उनका परिवार मेरे दिल में हमेशा खास जगह रखेगा.

वहीं टाइगर वुड्स ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि वो वोन के साथ बिताए बेहतरीन पलों को हमेशा याद रखेंगे. वोन और टाइगर वुड्स ने साल 2013 में अपने प्रेम संबंध स्वीकार किए थे. टाइगर वुड्स और लिंडसे वोन सार्वजनिक तौर पर आख़िरी बार पिछले महीने मास्टर्स गोल्फ़ टूर्नामेंट के दौरान साथ देखे गए थे. तब लिंडसे को टाइगर वुड्स, उनकी बेटी और बेटे के साथ देखा गया था. वुड्स का अपनी पत्नी स्वीडिश मॉडल एलन नूरदेग्रेन से साल 2010 में ही तलाक हो चुका है. टाइगर वुड्स के कई विवाहेतर संबंधों की बात क़बूल करने के बाद नूरदेग्रेन ने उनसे तलाक का फ़ैसला लिया था.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

करोड़ों का आयकर दबाए बैठा है बीसीसीआई

बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (बीसीसीआई) ने अभी तक होने वाली आमदनी पर पूरा आयकर नहीं चुकाया है. केंद्र सरकार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 2004-05 के बाद से बीसीसीआई ने 2140.58 करोड़ रुपये की राशि आयकर के रूप में चुकाई है जबकि उस पर कुल बकाया 2510.48 करोड़ रुपये की है. यानी अभी भी बीसीसीआई को 369.89 करोड़ रुपये बतौर आयकर चुकाना है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने संजय राउत के एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कर निर्धारण वर्ष 2004-05 के बाद से 2510.48 करोड़ रुपये की आयकर मांग में से 2140.58 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि शेष 369.89 करोड़ रुपये की मांग को आयकर प्राधिकारियों ने बीसीसीआई की अपील के निपटान तक स्थगित रखा है.

सिन्हा ने कहा कि कर निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए लंबित मांग 53 करोड़ रुपये है जबकि 2010-11 और 2011-12 के लिए 100-100 करोड़ रुपये और 2012-13 के लिए 116.89 करोड़ रुपये की मांग लंबित है. उन्होंने कहा कि अपीलीय प्राधिकरणों से बीसीसीआई की अपील के शीघ्र निपटान के लिए अनुरोध किया गया है ताकि कानून के अनुसार शेष करों की वसूली के लिए कार्रवाई की जा सके. मंत्री ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुल लंबित कर मांग 5,75,340 करोड़ रुपये थी जबकि एक साल पहले यह राशि 4,86,180 करोड़ रुपये थी. उन्होंने कहा कि कई वजहों से कर बकायों की वसूली नहीं हो पाती. उन्होंने कहा कि आयकर निस्तारण आयोग (आईटीएससी) के पास 130 ऐसे आवेदन लंबित हैं जो जून 2007 से पहले दाखिल किए गए थे.■

अकरम ने तेंदुलकर को दिए टिप्स

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम को वानखेडे स्टेडियम में भविष्य के उभरते तेज गेंदबाज अर्जुन तेंदुलकर को टिप्स देते देखा गया. कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले मैच से पूर्व अकरम ने संवाददाताओं से कहा कि मैं पिछली गर्मियों में इंग्लैंड में अर्जुन तेंदुलकर से मिला था. हम एक प्रदर्शनी मैच में खेले और जब वह बॉलिंग कर रहा था तो मैं मिड ऑन पर खड़ा था. उसने ब्रायन लारा को आउट किया. उन्होंने कहा कि वह 15 साल का युवा है. वह उत्सुक है और बाएं हाथ का मध्यम गति का बॉलर है. मैंने उससे उसके ऐक्शन और स्विंग के बारे में बात की. बेशक फिटनेस बेहद अहम है. वह सीखने को बेताब है जो काफी अच्छी चीज है. अर्जुन पिछले कुछ वर्षों से मुंबई की आयु वर्ग टीम का हिस्सा हैं. वह बल्लेबाज से अधिक गेंदबाज हैं जबकि उनके पिता सचिन महान बल्लेबाज रहे हैं. अकरम केकेआर के मेंटर हैं जबकि सचिन मुंबई इंडियंस के आइकन खिलाड़ी रहे हैं.■

मैच फिक्सिंग में शामिल हैं चेन्नई के चार खिलाड़ी : ललित मोदी

आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने चौकाने वाला खुलासा करते हुए आरोप लगया है कि चेन्नई सुपरकिंग्स टीम के चार खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में शामिल हैं. मोदी के सिलसिलेवार ट्विट के बाद क्रिकेट की दुनिया में मानो भूचाल सा आ गया हो. मोदी ने बीसीसीआई के संयुक्त सचिव अनुराग ठाकुर और चेन्नई सुपरकिंग्स के मालिक इंडिया सीमेंट्स को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये सभी सट्टेबाजी के मामले में जनता को गुमराह कर रहे हैं. आईपीएल-8 के समापन से महज कुछ दिनों पहले आए इन विवादास्पद ट्विट्स के मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट सट्टेबाजी में शामिल लोगों के नाम उजागर कर दें तो चेन्नई सुपरकिंग्स टीम के चार खिलाड़ी फसेंगे. मोदी ने ये ट्विट्स जस्टिस मुद्गल कमेटी द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट के संदर्भ में किए. मोदी ने यह भी दावा किया कि आईपीएल के हर मैच पर 9 से 10 हजार करोड़ रुपये का सट्टा लगता है. बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन पर भी निशाना साधते हुए मोदी ने ट्विट किया-मैं यह बात सालों से कह रहा हूं. जागो, मीडिया के साथियों, हर मैच पर तकरीबन 9 से 10 हजार करोड़ का सट्टा लगता है. नहीं तो क्या कारण है कि वह दानव इस्तीफा देना ही नही चाहता था. आईपीएल के पैसों से ही वह वोट, नेताओं और खिलाड़ियों को खरीदता था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चेन्नई सुपरकिंग्स के मालिकाना हक को इंडिया सीमेंट्स ने अपनी सहायक कंपनी चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया था.■

क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले 34 वर्षीय पीटरसन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज 5-0 से हारने के बाद अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हैं. इस स्टार बल्लेबाज को टीम में वापसी की आशा तब जग गयी थी जब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कोलिन ग्रेव्स ने कहा था कि काउंटी क्रिकेट में अच्छा स्कोर करने पर पीटरसन को नैशनल टीम में वापस लाया जा सकता है.

मैं बर्बाद हो गया हूं पीटरसन

स्टार बल्लेबाज केविन पीटरसन ने कहा है कि राष्ट्रीय टीम में वापसी की संभावना पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के नए डायरेक्टर एंड्र्यू स्ट्रॉस द्वारा रोक लगाए जाने के बाद वे बर्बाद हो गए हैं. उनका मानना है कि बहुत अधिक अविश्वास के कारण यह निर्णय लिया गया है. उन्होने कहा कि मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया हूं. ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम में मेरी वापसी की संभावना खत्म हो गई है. विशेष तौर पर तब जब मुझसे या मेरे बारे में जो कहा गया है. उन्होंने आगे कहा कि उन लोगों ने मुझे चयनित नहीं करने का कारण विश्वास की कमी बताया है. यह अच्छी बात है लेकिन विश्वास द्विपक्षीय चीज है. मेरे लिए अविश्वसनीय था कि हमारी बातचीत के आधा घंटा बाद ही इसका परिणाम इंटरनेट और बीबीसी पर था. अब जब मैंने किसी को ये बातें नहीं बताई तो आखिर ऐसा किसने किया? उन्होंने कहा है कि वे लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते लेकिन कोई उन पर विश्वास क्यों करे? इससे पहले इंग्लिश क्रिकेट के डायरेक्यर बनने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्ट्रॉस ने तमाम अटकलों को खत्म करते हुए कहा था कि उनके साथी पीटरसन की अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है. हालांकि साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि उन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है लेकिन वे पीटरसन को भविष्य के बारे में किसी तरह का आश्वासन नहीं दे सकते हैं.

क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले 34 वर्षीय पीटरसन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज 5-0 से हारने के बाद अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हैं. इस स्टार बल्लेबाज को टीम में वापसी की आशा तब जग गयी थी जब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कोलिन ग्रेव्स ने कहा था कि काउंटी क्रिकेट में अच्छा स्कोर करने पर पीटरसन को राष्ट्रीय टीम में वापस लाया जा सकता है. दूसरी ओर सरे की तरफ से अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेलने के बाद ही स्ट्रॉस ने उन्हें इस बात की सूचना दी कि निकट भविष्य में उन्हें इंग्लिश टीम में शामिल नहीं किया जाएगा. इसका मतलब है कि पीटरसन का अन्तरराष्ट्रीय करियर खत्म हो गया है.■

सलमान से मिलना चाहती हैं ऐश्वर्या

ऐश्वर्या चौबे सलमान की बहुत बड़ी फैन हैं. वैसे, तो वे पेंटर हैं, लेकिन सलमान की दीवानगी के चलते वे फिल्मों में आ गईं. जी हां, ऐश्वर्या सोनाक्षी सिन्हा स्टारर अपकमिंग फिल्म अकीरा में नजर आएंगी. ऐश्वर्या ने सलमान की कई पेंटिंग्स बनाई हैं, जिनमें से एक पेंटिंग लेकर वे बजरंगी भाईजान के सेट पर गई थीं, ताकि सलमान से मिल सकें और उन्हें वह पेंटिंग गिफ्ट कर सकें.

हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को उनके 13 साल पुराने हिट एंड रन मामले में पांच साल की सजा सुनाई गई थी. हालांकि, दो दिन बाद ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस सजा पर अंतरिम रोक लगा दी. सलमान की कानूनी भागदौड़ का खामियाजा उनकी एक फैन को उठाना पड़ा. दरअसल, कश्मीर की रहने वाली ऐश्वर्या चौबे सलमान की बहुत बड़ी फैन हैं. वैसे, तो वे पेंटर हैं, लेकिन सलमान की दीवानगी के चलते वे फिल्मों में आ गईं. जी हां, ऐश्वर्या सोनाक्षी सिन्हा स्टारर अपकमिंग फिल्म अकीरा में नजर आएंगी. ऐश्वर्या ने सलमान की कई पेंटिंग्स बनाई हैं, जिनमें से एक पेंटिंग लेकर वे बजरंगी भाईजान के सेट पर गई थीं, ताकि सलमान से मिल सकें और उन्हें वह पेंटिंग गिफ्ट कर सकें. हालांकि, सलमान की व्यस्तता के चलते वे उनसे नहीं मिल सकीं. इसके बाद ऐश्वर्या ने सलमान की खास दोस्त सोनाक्षी से संपर्क किया और उन्हें एक अच्छी पेंटिंग गिफ्ट की. इसके पीछे ऐश्वर्या का मकसद इतना सा था कि हो सकता है सोनाक्षी उनकी मुलाकात सलमान से करवा दें. इससे पहले कि सलमान ऐश्वर्या से मिल पाते कि सेशंस कोर्ट में उनकी सजा का दिन आ गया और वे मुंबई आ गए. फिर क्या ऐश्वर्या का सलमान से मिलने का सपना फिलहाल अधूरा है. वैसे, कहा जा रहा है कि उन्होंने बतौर एक्ट्रेस दो बड़ी फिल्में साइन की हैं, ताकि इस राह पर चलते-चलते कभी उन्हें सलमान के साथ काम करने का मौका भी मिल सके. एक अंग्रेजी वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने कहा था, मैं एक्टिंग के फील्ड में सिर्फ सलमान से मिलने के उद्देश्य से आई हूं. सच्चाई यह है कि मुझे इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है. इतना ही नहीं, खबरों की मानें तो जिस दिन सलमान को सजा सुनाई गई, उस रोज ऐश्वर्या पूरी रात रोती रहीं.■

दवा कंपनी पर मानहानि का दावा ठोंकेगीं करीना

करीना ने फिल्म टशन के किरदार की मांग की वजह से अपना वजन कम किया था जिसे लोगों ने जीरो साइज कहा था. लेकिन जब करीना ने टशन की शूटिंग पूरी कर ली तो फिर अपनी उसी रूप में आ गईं जैसी वह टशन से पहले थीं.

करीना कपूर एक दवा कंपनी पर 20 करोड़ रुपये के हर्जाने का मुकदमा करने वाली हैं. यह दवा कंपनी का दावा है कि उसकी एक गोली वजन घटाती है. फैंस की शिकायत पर करीना ने उस गोली के ब्रांड पर केस करने का फैसला लिया और 20 करोड़ रुपये के हर्जाने का दावा किया है. सूत्रों के मुताबिक, करीना कपूर हाल ही में अरब की यात्रा पर थीं. जहां उन्होंने अनेक शहरों से आए अपने फैंस से मुलाकात की. इसी दौरान उनके कुछ फैंस ने उन्हें बताया कि एक दवा कंपनी झूठा दावा कर रही है कि उसकी एक गोली वजन घटाती है और करीना ने भी जीरो साइज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था. सूत्रों की माने तो, करीना कपूर ने हमेशा से जीरो साइज का विरोध किया है.

हालांकि करीना ने फिल्म टशन के किरदार की मांग की वजह से अपना वजन कम किया था जिसे लोगों ने जीरो साइज कहा था. लेकिन जब करीना ने टशन की शूटिंग पूरी कर ली तो फिर अपनी उसी रूप में आ गईं जैसी वह टशन से पहले थीं. बॉलीवुड अभिनेत्री करीना ने कभी किसी को वजन काम करने के लिए कोई गोली लेने की सलाह नहीं दी. उनका कहना है कि मैं एक अभिनेत्री हूं और मैं मेरे प्रशंसको को कभी झूठी सलाह नहीं देनी चाहूंगी. यह गोली मेरा नाम गैर कानूनी इस्तेमाल कर रही है. जिससे मेरे प्रशंसक को गलतफहमी हो सकती है.■

हाईकोर्ट में बॉम्बे वेलवेट का मामला

बॉम्बे वेलवेट के निर्माता दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए हैं. निर्माता चाहते हैं कि लोकल केबल आपरेटरों और वेबसाइट्स पर फिल्म का प्राइरेटेड वर्जन दिखाया न जाए. न ही इस फिल्म को कोई ऑनलाइन उपलब्ध करा पाए. फिल्म बॉम्बे वेलवेट के निर्माता ने इसकेलिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. अनुराग कश्यप द्वारा डायरेक्टेड बॉम्बे वेलवेट इतिहासकार ज्ञान प्रकाश की पुस्तक मुंबई फैबल्स पर आधारित है. फिल्म में 1960 के दौर के मुंबई को दिखाया गया है. फिल्म की डिस्टिब्यूटर कंपनी फॉक्स स्टार स्टूडियो इंडिया लिमिटेड ने याचिका में कहा है कि फिल्म की पाइरेसी से उसे और फिल्म के को-प्रोड्यूसर फैन्टम फिल्म्स को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. बता दें कि फिल्ममेकर करण जौहर ने इसमें एक्टिंग भी की है. ■

सनी लियोन के पीछे रणविजय

रणविजय और सनी लियोन जल्द ही एमटीवी के एक रियलिटी शो को होस्ट करते नजर आएंगे. इसकेलिए दोनों ने ही प्रोमो शूट में हिस्सा लिया. रणविजय इस शो का पहला सीजन होस्ट कर चुकेहैं. सनी एक बार फिर से इस शो पर नजर आएंगी.

सनी लियोन एडल्ट फिल्मों में बतौर पॉर्न स्टार काम कर चुकी हैं, इसलिए बॉलीवुड में कई हीरो उनकेसाथ काम करने से झिझक रहे हैं. लेकिन रणविजय सिंह के साथ ऐसा नहीं है, वे तो उल्टा सनी लियोन को रिझाने में जुटे हुए हैं. दरअसल, रणविजय और सनी लियोन जल्द ही एमटीवी के एक रियलिटी शो को होस्ट करते नजर आएंगे. इसकेलिए दोनों ने ही प्रोमो शूट में हिस्सा लिया. रणविजय इस शो का पहला सीजन होस्ट कर चुके हैं. सनी एक बार फिर से इस शो पर नजर आएंगी. रणविजय शूट के दौरान सनी को रिझाते नजर आए, वहीं सनी स्पॉट बॉयज को डांस कराते नजर आईं. कुछ दिन पहले ही रणविजय ने ट्विट कर बताया था कि लंबे समय के बाद इस शो को होस्ट करना उनकी पुरानी यादें ताजा कर रहा है.■

प्रियंका चोपड़ा बनी पुलिस वाली

फिल्म गंगाजल 2 में प्रियंका चोपड़ा पुलिस के अवतार में नज़र आने वाली हैं, जिसका फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है. दरअसल, इस फिल्म में बिहार की पुलिसिया सिस्टम को नज़दीक से दिखाया जाएगा.

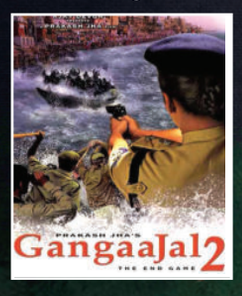

आईपीएस आभा माथुर के किरदार में देशी गर्ल प्रियंका चोपड़ा अपने बिल्कुल नए अंदाज़ में स्क्रीन पर नज़र आएंगी. इससे पहले भी प्रकाश झा ने अपनी पहली फिल्म गंगाजल में पुलिसिया सिस्टम को ही दिखाया था, जिसमें अजय देवगन नज़र आए थे और इस फिल्म को दर्शकों तथा क्रिटिक्स की ओर से खूब सराहना मिलीं. अब प्रकाश झा अपनी इस हिट फिल्म का सीक्वल बना रहे हैं, जिसमें अजय देवगन नहीं हैं.■

एफबीआई एजेंट बनी प्रियंका

अमेरिकी धारावाहिक क्वांटिको के तीन मिनट के ट्रेलर में बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा एफबीआई एजेंट एलेक्स पैरिश की भूमिका में सच की तलाश में दिखीं. प्रियंका ने ट्विटर पर लिखा, क्वांटिको का ट्रेलर हाजिर है. मैं बहुत बेचैन हूं. ट्रेलर में प्रियंका के एफबीआई अकादमी क्वांटिको में प्रशिक्षु बनने से लेकर एक आतंकवादी हमले का मुख्य संदिग्ध होने तक का क्रमवार चित्रण है. क्वांटिको के ट्रेलर में प्रियंका जाहिर तौर पर सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं. वह इसके जरिए पहली बार छोटे पर्दे पर कदम रख रही हैं. यह कार्यक्रम इन गर्मियों में एबीसी चैनल पर प्रसारित होगा. इसमें प्रियंका के अलावा डोगरे स्कॉट, जेक मैकलॉघलिन और जोहाना ब्रैडी भी नजर आएंगे.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया बिहार झारखंड

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

25 मई–31 मई 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

महाविलय को बचाने में जुटे नीतीश

सरोज सिंह

जनता दल परिवार की एका को लेकर तमाम तरह की अटकलें और कयासों की गूंज सत्ता के गलियारों में सुनाई पड़ रही है. हद तो यह है कि पहली बार बिहार में होने वाले किसी राजनीतिक गठबंधन पर सट्टा भी लगने लगा है. सपा नेता रामगोपाल यादव के विलय में तकनीकी परेशानियों वाले बयान के बाद तो यह सिलसिला चरम पर जा पहुंचा, और लगे हाथ लालू प्रसाद ने जब इसी भावना को दोहरा दिया, तो ऐसा लगा कि महाविलय की गाड़ी को ब्रेक लग गया है. इसके बाद महाविलय के विरोधी नेताओं ने बयानों की झड़ी लगा दी और कहना शुरू कर दिया कि महाविलय की भ्रूण हत्या हो गई. लेकिन नीतीश कुमार ने रहीम का दोहा सुनाकर इन सारी अटकलों और कयासों को हवा कर दिया. नीतीश कुमार ने कहा, धीरे–धीरे चल मना,धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा,ऋतु आए फल होए. नीतीश कुमार ने दो टूक कहा कि सभी चीजें रास्ते पर हैं, कोई मतभेद नहीं है. जनता परिवार के सभी दलों के मन आपस में मिल चुके हैं और समय आने पर परिणाम भी सामने आ जायेगा. नीतीश कुमार के इन विश्वास भरे बयानों के बाद विरोधियों के मन में जो लड्डू फूट रहे थे वह कुछ कम हुए. दरअसल भाजपा और उसके सहयोगी दल यह बात अच्छी तरह समझ रहे हैं कि महाविलय की स्थिति में उन्हें चुनावी अखाड़े में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है. लालू प्रसाद और नीतीश कुमार अलग–अलग चुनाव लड़ें, इससे अच्छी स्थिति भाजपा के लिए कुछ नहीं हो सकती है. इसलिए जब भी महाविलय की गाड़ी पटरी से उतरती है एनडीए खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है. इस बार भी जब रामगोपाल यादव का बयान आया कि राजद और जदयू को गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए, तो भाजपा खेमा समझ बैठा कि महाविलय का चैप्टर अब खत्म हो गया. लेकिन नीतीश कुमार ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला और पूरे खेल को ही बदल दिया. लालू प्रसाद ने भी साफ किया कि विलय को लेकर कोई संदेह नहीं है पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं होना चाहिए. लालू ने कहा कि जब मन चंगा तो कठौती में गंगा. लेकिन तकनीकी कारणों को अच्छी तरह समझना जरूरी है. लालू ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे भाजपा को लाभ मिले.

जानकार बताते हैं कि विलय में आड़े आ रही तकनीकी दिक्कतों में सबसे अहम जनता परिवार के दलों की संपत्ति को माना जा रहा है. जानकार सूत्र बताते हैं कि अकेले सपा के पास तकरीबन 500 करोड़ की संपत्ति है. इस विवाद को सुलझाने के लिए प्रोफेशनल वित्त विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है. इसके अलावा जदयू और राजद में भी कुछ नेता ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि महाविलय की गाड़ी आगे बढ़े. ये ऐसे नेता हैं जिन्हें लगता है कि महाविलय से इन्हें और इनके समर्थकों को टिकट पाने में परेशानी हो सकती है. लेकिन नीतीश कुमार के रणनीतिकारों का साफ कहना है कि फैसले में इस तरह के नेताओं की कोई निर्णायक भूमिका नहीं होती है. नीतीश कुमार ने महाविलय को एक मिशन के रूप में लिया है और बिना किसी पूर्वाग्रह के वह सभी संबंधित लोगों से खुले दिल से बात कर रहे हैं, और महाविलय की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं. जदयू के एक बड़े नेता कहते हैं कि चूंकि यह महाविलय है और कई राज्यों में इसके तार फैले हुए हैं इसलिए इस काम के अंजाम तक पहुंचने की कोई तारीख बताना बेहद मुश्किल है. हां, मैं दावे के साथ इतना जरूर कह सकता हूं कि सभी दलों का शीर्ष नेतृत्व महाविलय को लेकर बेहद गंभीर है. चुनाव में भाजपा को कोई फायदा हो, हम ऐसा कोई स्पेस नहीं देने जा रहे हैं. जानकार सूत्र बताते हैं कि अभी 24 सीटों के लिए जो स्थानीय निकाय क्षेत्र के चुनाव होने हैं उसमें जदयू और राजद के साथ कांग्रेस एवं वामदलों के साथ तालमेल की बात अंतिम चरण में पहुंच गई है. दस–दस सीटों पर राजद और जदयू के प्रत्याशी होंगे और बाकी बची चार सीटें कांग्रेस और वामदलों के लिए छोड़ी जाएगी. दरअसल स्थानीय चुनावों में जीत हासिल कर नीतीश कुमार महाविलय के लिए माहौल बनाना चाहते हैं इसलिए वह अपनी कुछ जीती हुई सीटों को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं. नीतीश कुमार चाहते हैं कि परिषद चुनावों में सही तालमेल कर पूरी ताकत से भाजपा का मुक़ाबला किया जाए. अगर इस सेमी–फाइनल मुक़ाबले में क़ामयाबी मिल गई तो आगामी विधानसभा चुनावों के कई कील–कांटे स्वत: खत्म हो जाएंगे और महाविलय का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा.■

feedback@chauthiduniya.com

> नीतीश कुमार ने महाविलय को एक मिशन के रूप में लिया है और बिना किसी पूर्वाग्रह के वह सभी संबंधित लोगों से खुले दिल से बात कर रहे हैं और महाविलय की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं. जदयू के एक बड़े नेता कहते हैं कि चूंकि यह महाविलय है और कई राज्यों में इसके तार फैले हुए हैं इसलिए इस काम केअंजाम तक पहुंचने की कोई तारीख बताना बेहद मुश्किल है.

नीतीश के साथ कोई तालमेल नहीं : भूपेंद्र

चूंकि बिहार के लिए यह साल चुनावी है इसलिए हर छोटी बड़ी राजनीतिक चर्चा यहां सुर्खियां बटोर लेती है. पिछले दिनों भूकंप के दौरान जब राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार के कामों की सराहना कर दी तो यह बात फैलने लगी कि कहीं भाजपा और जदयू फिर से एक तो नहीं हो रहे हैं. इस बात को तब और हवा मिली जब नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के कुछ कामों की तारीफ कर दी. राजनीतिक गलियारों में चर्चा गरम हो गई कि पुराने दिन आने वाले हैं. लेकिन बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के साथ दोबारा कोई राजनीतिक रिश्ता बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता. एक मुलाक़ात में यादव ने कहा कि हम भी जानते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है. पर जहां तक नीतीश कुमार की पार्टी से तालमेल का सवाल है तो इस मामले में भाजपा का नजरिया बेहद स्पष्ट है. भाजपा और जदयू का तालमेल किसी भी कीमत में संभव है ही नहीं. दो दशक से ज्यादा दोस्ती निभाने के बाद ऐसा क्या हो गया कि आप लोग नीतीश कुमार को अछूत समझने लगे इस पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ विश्वासघात किया. जनादेश भाजपा और जदयू को साथ मिला, पर नीतीश कुमार ने धोखा देकर हमसे रिश्ता तोड़ लिया और अपनी सरकार बना ली. अगर उनमें नैतिकता होती तो इस्तीफा देकर जनता की अदालत में जाते और फिर जनता का जो फैसला आता उसे स्वीकार करते. लेकिन ऐसा न करके उन्होंने महादलित प्रेम का ढोंग रचा और गद्दी पर खुद विराजमान हो गए. आगे सत्ता बनी रहे, इसके लिए लालू यादव के दरवार में शरणागत हो चुके हैं. जिस जंगल राज को खत्म करने के लिए भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खून-पसीना बहाया, उसी के सुप्रीमो के साथ आज नीतीश घूम रहे हैं. जनता भला ऐसे दोहरे चेहरे वाले नेता को कैसे स्वीकार करेगी. भूपेंद्र यादव साफ कहते हैं कि बिहार में टीम भाजपा ही चुनाव में उतरेगी. उन्होंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व हमारी पार्टी को मिला है और चुनाव में इसका लाभ भाजपा को जरूर मिलेगा. वह कहते हैं कि हम नकारात्मक मुद्दों पर चुनाव में नहीं जायेंगे बल्कि विकास और सुशासन ही हमारा मुख्य मुद्दा होगा. यही बात तो नीतीश कुमार भी कहते हैं तो इस पर भूपेंद्र यादव कहते हैं कि लालू का साथ लेकर वह विकास और सुशासन की बात कैसे कह सकते हैं. बिहार की जनता यह हरगिज नहीं चाहती है कि जंगल राज की वापसी हो, इसलिए सूबे की जनता ने यह मन बना लिया है कि इस बार भाजपा और उसके सहयोगी दलों की दो तिहाई बहुमत वाली सरकार बिहार में बनानी है. भूपेंद्र यादव कहते हैं कि हम अपने सहयोगी दलों का पूरा सम्मान करते हैं और जरूरत के हिसाब से हम अपने सहयोगियों की संख्या बढ़ा भी सकते हैं. भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर 185 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, और मुझे पूरा भरोसा है विकास और सुशासन प्रिय बिहार की जनता हमें इस बार निराश नहीं करेगी.■

एक नज़र

वास्तु विहार अब OHSS 18001:2007 सर्टिफाईड कंपनी

वास्तु विहार®
एक विश्वस्तरीय टाउनशिप
AN ISO : 9001 : 2008 : 14001 : 18001 : 2007 COMPANY

पूर्वी भारत की प्रतिष्ठित कंस्ट्रक्शन कंपनी वास्तु विहार अब OHS-S 18001:2007 सर्टिफाईड कंपनी हो गई है. पूर्वी भारत के विभिन्न राज्यों के 50 से ज्यादा शहरों में वास्तु विहार टाउनशिप डेवलप करती है. कंपनी द्वारा डेवलप की गई टाउनशिप स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरती है. यही कारण है कि कंपनी को यह सर्टिफिकेशन मिला है. इससे पूर्व वास्तु विहार आईएसओ-9001 तथा आईएसओ 14001 सर्टिफिकेशन पा चुकी है. अत्यंत किफायती मूल्य पर, सभी आय वर्ग के लोगों को घर उपलब्ध कराने के कारण वास्तु विहार ने देश भर में एक अलग पहचान बनाई है. वर्तमान में कंपनी अपने फाईव स्टार बंगलो के कारण चर्चा में है. ये बंगलो वेल्डेड स्टील द्वारा भूकंप से सुरक्षा, मॉड्यूलर किचन, इंसुलेटेड दीवारें और छत, हाईब्रिड एयरकंडीशनर तथा रूफटॉप सोलर पावर प्लांट से 70 प्रतिशत बिजली की बचत जैसी खूबियों से लैस है. बताते चलें कि कंस्ट्रक्शन के अलावा, वास्तु विहार अन्य क्षेत्रों में भी सक्रिय है. वास्तु विहार बायोटेक ऑर्गेनिक खेती के क्षेत्र में दिन-रात अनुसंधान कार्य में लगा हुआ है, और इस दिशा में उसने चौंकाने वाली उपलब्धियां हासिल की हैं. इसके अतिरिक्त वास्तु विहार मीडिया वेंचर्स,और मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय है. यही नहीं, बोध गया तथा धनबाद स्थित वास्तु विहार ग्रुप के रिसॉर्ट संबोधी रिट्रीट को लोग उसकी भव्यता और अनोखेपन के कारण पूर्वी भारत का ताजमहल कहकर बुलाते हैं.

रंगीन राजनीति के द्वितीय भाग का लोकार्पण

अमूमन दिल्ली का जंतर-मंतर धरना, भूख-हड़ताल, अनशन एवं प्रदर्शन सहित विविध राजनीतिक गतिविधियों के लिए ही जाना जाता है लेकिन बिहार के मशहूर कथाकार डॉ लालजी प्रसाद सिंह की 41 वीं पुस्तक 'रंगीन राजनीति' उपन्यास के द्वितीय संस्करण का लोकार्पण पटना बिहार के महंत हनुमान शरण कॉलेज, शिवम क्लासेज एवं साई-शिवम पब्लिक स्कूल के सौजन्य से उक्त शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं निदेशक डॉ बिमल नारायण आर्य ने दिल्ली के जंतर मंतर पर किया. उक्त अवसर पर प्राचार्य डॉ बिमल नारायण आर्य ने कहा कि रंगीन राजनीति में बिहार के मशहूर कथाकार डॉ लालजी प्रसाद सिंह ने निर्भीकता के साथ राजनीतिज्ञों की पर्दे के पीछे की रंगीन मिजाजी एवं काली करतूतों का वर्णन किया है. यह पुस्तक बिहार की राजनीति में पुस्तक बम साबित हो सकती है. डॉ आर्य ने ऐसे साहसिक लेखन को देखते हुए कथाकार डॉ सिंह को जनता का लेखक बतलाया. लोकार्पण के अवसर पर कथाकार डॉ लालजी प्रसाद सिंह एवं पटना की प्रो रीता सिंह तथा छात्रा प्रियंका सहित दिल्ली के स्थानीय बाशिंदों ने भी भाग लिया.■

-चौथी दुनिया ब्यूरो

बेगूसराय

तेघड़ा में चुनावी सरगर्मी तेज़

सुरेश चौहान/सुधीर झा

बिहार विधान सभा का चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहा है, त्यों-त्यों राजनीतिक दलों की सरगर्मी तेज होती जा रही है. पार्टी किसे अपना प्रत्याशी घोषित करेगी, इसकी परवाह किए बगैर सभी दलों के स्थानीय नेताओं में प्रत्याशी बनने की ललक हिलोरें मार रही है. प्रमुख दलों के कई नेता स्वयं को प्रत्याशी बनाए जाने की बात कहकर जनसंपर्क अभियान प्रारंभ कर चुके हैं. वे मतदाताओं को यह विश्वास दिलाने को आतुर हैं कि अगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी उन्हें ही प्रत्याशी घोषित करेगी.

राम लखन सिंह

राम रतन सिंह

रतन सिंह

संजय सिंह

गत लोक सभा चुनाव में भाकपा में उभरी जबर्दश्त अंतर्कलह को पार्टी ने लगभग पाट लिया है. अगामी विधान सभा चुनाव में भाकपा के संभावित प्रत्याशियों में राम रतन सिंह, प्रदीप राय एवं किसान नेता अशोक कुमार सिंह के नाम की चर्चा जोरों पर है. राम रतन सिंह पार्टी के जमीनी नेता हैं. इनमें गजब की नेतृत्व एवं सांगठनिक क्षमता है और सर्वदा पार्टी के प्रति निष्ठावान एवं समर्पित रहे हैं जबकि गत विधान सभा चुनाव में प्रदीप राय की निष्ठा बदल चुकी थी.

बेगूसराय के तेघड़ा विधान सभा क्षेत्र में भी भाकपा, भाजपा, जदयू, कांग्रेस, राजद एवं माकपा के स्वमं-भू संभावित प्रत्याशी अपने पक्ष में जनाधार मजबूत करने की होड़ में शामिल हैं. ऐसे तेघड़ा विधान सभा को भाकपा का लेनिनग्राद माना जाता है. प्रत्येक चुनाव में भाकपा एवं कांग्रेस के बीच कांटे का संघर्ष होता रहा है. 1957 के विधान सभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने दिग्गज नेता एवं सूबे के बिजली एवं सिंचाई मंत्री राम चरित्र सिंह को प्रत्याशी नहीं बनाकर जो भूल की थी, उसकी सजा आजतक भुगत रही है. क्षेत्र के कांग्रेसी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने इसे अपमान माना. जमीन से जुड़े कांग्रेसी नेताओं सूर्यनारायण पोद्दार, रामजी लाल, बैजनाथ सुल्तानिया, रामदेव राय, नूनूलाल पोद्दार, रावणेश्वर दत्त, शत्रुघ्न सिंह, विजयनन्दन प्रसाद नारायण सिंह (बीजा बाबू), हरिनन्दन सहाय, रामाकांत सिंह सहित अन्य ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और राम चरित्र सिंह को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतार दिया. पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी अहमद मियां की जीत सुनिश्चित करने का कमान तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ श्रीकृष्ण सिंह और कांग्रेस के ख्याति प्राप्त नेता महेश प्रसाद सिंह ने संभाल रखी थी. फिर भी कांग्रेस प्रत्याशी की हार हुई और राम चरित्र सिंह रिकार्ड मतों से जीत दर्ज की. यहीं से इस क्षेत्र में कांग्रेस की पराजय का अध्याय प्रारंभ हुआ. 1962 से 2010 तक इस सीट पर भाकपा का कब्जा रहा. 48 वर्षों बाद 2010 के चुनाव में राजग के भाजपा प्रत्याशी ने भाकपा के एकाधिकार को ध्वस्त किया और लेनिनग्राद में प्रथम वार केसरिया फहराया. भाजपा के ललन कुंवर विजयी हुए. कांग्रेस पार्टी 1957 की भूल से कोई सबक नहीं लिया. वर्तमान में तेघड़ा विधान सभा क्षेत्र में भाजपा, लोजपा एवं रालोसपा गठबंधन तथा भाकपा और कांग्रेस का जनाधार मजबूत नजर आ रहा है.

गत लोक सभा चुनाव में भाकपा में उभरी जबर्दश्त अंतर्कलह को पार्टी ने लगभग पाट लिया है. अगामी विधान सभा चुनाव में भाकपा के संभावित प्रत्याशियों में राम रतन सिंह, प्रदीप राय एवं किसान नेता अशोक कुमार सिंह के नाम की चर्चा जोरों पर है. राम रतन सिंह पार्टी के जमीनी नेता हैं. इनमें गजब की नेतृत्व एवं सांगठनिक क्षमता है और सर्वदा पार्टी के प्रति निष्ठावान एवं समर्पित रहे हैं जबकि गत विधान सभा चुनाव में प्रदीप राय की निष्ठा बदल चुकी थी. जल्दी विधायक बनने की ललक से लबरेज प्रदीप राय भाकपा से निष्ठा तोड़कर लोजपा का दामन थाम लिया और लोजपा के टिकट पर 2010 में विधान सभा का चुनाव लड़े और पराजित हुए. इसके बाद वे भाकपा में वापस आ गए. अशोक कुमार सिंह किसान-मजदूर के नेता है और पार्टी के प्रति समर्पित हैं. कांग्रेस पार्टी के संजय सिंह, राम बदन सिंह, नंदकिशोर सिंह, नारायण सिंह एवं चुनचुन राय भी संभावित प्रत्याशियों की सूची में शामिल है. संजय सिंह पार्टी संगठन से हमेशा जुड़े रहे हैं. वे युवक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं. जिला परिषद बेगूसराय के उपाध्यक्ष निर्वाचित हो चुके हैं. नन्द किशोर सिंह, नारायण सिंह एवं राम बदन भी निष्ठावान कांग्रेसी हैं. चुनचुन राय किसान-मजदूर नेता हैं. वर्तमान में तेघड़ा विधान सभा सीट भाजपा के पास है. वर्तमान विधायक ललन कुंवर, राम लखन सिंह, जमशेद अशरफ एवं केशव शांडिल्य भाजपा के संभावित प्रत्याशियों की सूची में शामिल हैं. राम लखन सिंह में अद्भुत सांगठनिक क्षमता है. जिला अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने भाजपा को शहर की सड़कों से गांव की गलियों तक पहुंचाया और संगठन को काफी मजबूत बनाया. पार्टी की सदस्यता में आशानुरूप वृद्धि की. पार्टी कार्यकर्ताओं (खासकर युवा वर्ग) में काफी लोकप्रिय हैं. भाजपा एवं आरएसएस में राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है. खेल एवं खिलाड़ियों के विकास के लिए वह सदैव तत्पर रहते हैं. केशव शांडिल्य आरएसएस के कैडर हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ सीपी ठाकुर के राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं. जमशेद अशरफ, नीतीश सरकार में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रह चुके हैं. जदयू से पूर्व जिलाध्यक्ष भोलाकांत झा एवं रतन सिंह दावेदार हैं. रतन सिंह जिला परिषद बेगूसराय के अध्यक्ष रह चुके हैं. वर्तमान में जिला पार्षद हैं. सांगठनिक क्षमता के धनी एवं लोकप्रिय नेता हैं. राजद एवं जदयू का यदि विलय होता है तो रतन सिंह सशक्त प्रत्याशी हो सकते हैं. भाकपा का यदि किसी राजनीतिक दल से चुनावी गठबंधन होता है तो भी वह तेघड़ा विधान सभा क्षेत्र किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहेगी. आज की स्थिति में भाकपा, भाजपा, कांग्रेस एवं जदयू के बीच चुनावी संघर्ष होने के आसार हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

मगध विधान परिषद चुनाव

दो गठबंधनों के बीच ही होगा मुक़ाबला

सुनील सौरभ

बिहार विधान परिषद के निकाय निर्वाचन क्षेत्र के होने वाले चुनावों को विधान सभा चुनाव का सेमी-फाइनल माना जा रहा है. चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि विधान परिषद के निकाय क्षेत्र चुनाव परिणाम से आगामी विधान सभा चुनाव को लेकर बिहार की जनता के रुख का पता चलेगा. लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि विधान परिषद के इस चुनाव में अधिक मडाकफलगाने वाले प्रत्याषियों की ही जीत होती है. इसलिए इस चुनाव को विधान सभा चुनाव का सेमी-फाइनल के रूप में मानना गलत होगा.

मगध के दो निकाय क्षेत्रों में भी विधान परिषद चुनाव को लेकर तैयारी शुरु हो गयी है. गया तथा औरंगाबाद निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले संभावित प्रत्याषी अपनी-अपनी रणनीति बनाकर वोटरों से संपर्क करने में जुट गये हैं. इस चुनाव में शहरी निकाय तथा पंचायतो के विभिन्न स्तरीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि ही वोटर होते हैं. मगध के दोनों निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से फिलहाल जदयू के विधान पार्षद हैं. गया निर्वाचन क्षेत्र से पिछले चुनाव में जदयू के अनुज कुमार सिंह तथा औरंगाबाद से रंजन कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह विजयी हुए थे. मुन्ना सिंह लगातार दूसरी बार विजयी हुए थे, तो अनुज कुमार सिंह पहली बार. लेकिन इस बार मगध के दोनों क्षेत्रों का राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा गया है.

जदयू गया निकाय निर्वाचन क्षेत्र से अपना प्रत्याषी बदल सकता है तो अनुज कुमार सिंह भी पाला बदल कर भाजपा या निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ सकतें हैं. जदयू भी अपना प्रत्याषी यहां से बदल सकता है या फिर राजद के लिए इस सीट को छोड़ सकता है, क्योंकि साल 2009 में हुए चुनाव में राजद प्रत्याशी मनोरमा देवी दूसरे स्थान पर रही थीं. इससे पूर्व 2003 में मनोरमा देवी इस सीट से विधान पार्षद बनी थीं. मनोरमा देवी राजद नेता और गया जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष विंदेश्वरी प्रसाद यादव उर्फ बिंदी यादव की पत्नी हैं. 2009 के चुनाव में भाजपा-जदयू के बीच गठबंधन था. तब गया तथा औरंगाबाद सीट जदयू के खाते में गई थी. इस बार समीकरण उलट गये हैं. जदयू-राजद-भाकपा का गठबंधन है तो भाजपा का लोजपा-रालोसपा के साथ गठबंधन है. औरंगाबाद से 2003 में रंजन कुमार सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रुप से विधान पार्षद बने थे. लेकिन 2009 में जदयू प्रत्याशी के रुप में खड़े होकर उन्होंने लगातार दूसरी बार सफलता प्राप्त की थी. लेकिन इस बार दोनों सीटों का समीकरण उलट गया है.

गया निकाय निर्वाचन क्षेत्र के अंतगर्त गया, जहानाबाद और अरवल जिले के मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत तथा नगर निगम के निर्वाचित वार्ड सदस्य वोटर है. यहां करीब आठ हजार वोटर हैं. जिसमें गया नगर निगम, शेरघाटी नगर पंचायत, टिकारी नगर पंचायत के वार्ड सदस्य, जहानाबाद नगर पालिका, अरवल नगर परिषद के वार्ड सदस्य के अलावा इन तीनों जिलों के पंचायतों के मुखिया, वार्ड सदस्य तथा पंचायत समिति सदस्य वोटर है. औरंगाबाद में नगर परिषद औरगाबाद, दाउदनगर नगर परिषद , रफीगंज व नवीनगर नगर पंचायत के वार्ड सदस्य तथा मुखिया, पंचायतो के वार्ड सदस्य तथा पंचायत समिति सदस्य वोटर हैं. यहां करीब साढ़े तीन हजार वोटर हैं. इस चुनाव मे 20 प्रतिशत पार्टी का लाभ तथा अस्सी प्रतिषत वोटरों के 'डाक' से हार-जीत निश्चित होती है. हालांकि प्रत्यक्ष रुप से इस संबध मे कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं हैं. लेकिन अप्रत्यक्ष रुप से सच्चाई यही है. इन दोनों सीटों पर सीधी लड़ाई भाजपा-लोजपा-रालोसपा तथा राजद-जदयू-कांग्रेस-भाकपा गठबंधन के बीच ही होगा. इस बीच कोई निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी मजबूत दावेदारी से दलीय प्रत्याशी को परेशानी मे डाल सकता है. ऐसे गया से करीब आधा दर्जन प्रत्याशी दोनों गंठबंधनों से मजबूत दावेदारी रखने का दावा कर रहे हैं. जिसमें कई प्रत्याषी ऐसे हैं, जो किसी भी दल से टिकट लेने की चाहत रखकर सभी ओर ताक-झाक कर रहें हैं. इसी प्रकार औरंगाबाद से भी करीब आधा दर्जन प्रत्याशी विधान परिषद के चुनाव के लिए अपनी दावेदारी विभिन्न दलों से कर रहे हैं. ऐसे में टिकट लेकर कौन दल से कौन सफल हो पाता है. लेकिन इतना तो तय है कि वोटरों के डाक में अधिक बोली लगाने वाला ही विधान परिषद चुनाव में सफलता का झंडा गाड़ सकेगा.■

feedback@chauthiduniya.com

खगड़िया

नवोदय विद्यालय का बुरा हाल है

पूनम देवी यादव
बिद्यानंद दास
नागेंद्र सिंह त्यागी

मनेन्द्र कुमार

एक तरफ जहां सूबे में जहां विभिन्न जिलों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर तरह-तरह कोर्सेज के कॉलेज खोले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खगड़िया जिले की गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था का नमूना यहां का नवोदय विद्यालय बन गया है. जो कि अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है. खगड़िया जिले के अन्तर्गत चौथम प्रखंड के सोनवर्षा घाट में नवोदय विद्यालय स्थित है. जिसका निमार्ण दो दशक पहले हुआ था. जो कि अपने स्थापना काल यानि वर्ष 1994 से सोनवर्षा घाट स्थित पीडब्लूडी विभाग के 7 बीघे जमीन में बने अस्थाई भवन में चल रहा है. यह अस्थाई भवन उत्तर प्रदेश पुल निर्माण योजना द्वारा कोशी एवं बागमती नदी पर बन रहे बीपी मंडल सेतु के निर्माण के दौरान अधिकारियों, अभियंताओं एवं पुल में काम करने वाले कर्मियों के रहने के लिए बनाये गये थे. नवोदय विद्यालय के पदेन अध्यक्ष तत्कालीन जिलाधिकारी ने नवोदय विद्यालय खोलने के लिए उक्त अस्थाई भवन का चयन किया था. वर्ष 1994 में विद्यालय के प्रथम सत्र की शरुआत हुई. प्रथम वर्ष वैधानिक प्रक्रिया के तहत जिले के 80 प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं का नामांकन वर्ग छः में किया गया. अगले वर्ष भी प्रतिभा के आधार पर दो वर्षों तक 80 छात्र-छात्राओं का नामांकन जारी रहा. विभागीय अधिकारियों की सर्वेक्षण टीम के अस्थाई भवन में छात्र-छात्राओं की आवासीय असुविधा को देखते हुए हर वर्ष 80 छात्र-छात्राओं के नामांकन कोटे में कटौती कर महज 40 छात्र-छात्राओं के नामांकन की स्वीकृति जारी की. तब से जिले के 40 छात्र छात्राओं का नुक्सान हो रहा है.

विद्यालय के खुलने के दो दशक बाद विद्यालय के पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी द्वारा नवोदय विद्यालय के नाम 7 बीघे जमीन की रजिस्ट्री का स्वागत करते हुए विद्यालय के डायरेक्टर ने विद्यालय के लिए कम से कम 10 बीघे जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव जिलाधिकारी को दिया. यदि जिलाधिकारी निकटवर्ती 7 बीघा जमीन का अधिग्रहण करने में कामयाब होते हैं. तो जवाहर नवोदय विद्यालय का निर्माण खगड़िया नगर से सटे सदर प्रखंड के भदास पंचायत में हो सकता है अन्यथा जितनी जमीन विद्यालय के नाम भदास में उपलब्ध है उतनी ही सोनवर्षा घाट में भी उपलब्ध है.

विद्यालय के प्रभारी प्रचार्य ने बताया कि इतनी कुव्यवस्था के बावजूद विद्यालय के 4 छात्र-छात्रायें 10 सीजीपीए लाकर में टॉप पर रहे. वहीं विद्यालय के 95 फीसदी छात्र छात्राओं में सीबीएससी की 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने में सफल रहे. उन्होंने कहा कि विद्यालय के लिए जमीन एवं भवन के किल्लत से जिले के 40 छात्र छात्राओं की प्रतिभा कुंठित हो रही है. वही प्लस टू की पढ़ाई के लिए छात्र छात्राओं को अन्यत्र जाना पड़ रहा है. जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से 10 के कुल 200 नामांकित छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं.

जवाहर नवोदय विद्यालय के अगल-बगल की जमीन के मालिकों से संपर्क अभियान चलाकर स्थानीय जदयू विधायक पन्नालाल पटेल ने जमीन देने की पहल की थी. लेकिन यह पहल अंजाम तक नहीं पहुंच पाई. वहीं पूर्वी बौरना पंचायत की मुखिया सरिता देवी और सरपंच रूबी देवी ने जिलाधिकारी से अविलंब विद्यालय को जमीन मुहैया कराने की मांग की है. वहीं जदयू की सदर विधायक पूनम देवी यादव का कहना है कि जिला मुख्यालय के करीब ही जमीन उपलब्ध करने का प्रयास चल रहा है इस संबंध में मुख्यमंत्री का भी ध्यान आकर्षित कराया गया है. यथाशीघ्र नवोदय विद्यालय निर्माण की कवायद शुरु की जायेगी, ताकि प्रतिभावान छात्रों को पूरा लाभ मिल सके. वहीं युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष नागेन्द्र सिंह त्यागी का कहना है कि जवाहर नवोदय विद्यालय की कुव्यवस्था के लिए आज तक जिलाधिकारी दोषी माने जा रहे हैं, किसी भी जिला धिकारी ने हर वर्ष जिले के 40 मेघावी छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के बारे में चिंता नहीं की. इतना समय गुजर जाने के बाद भी कोई भी जन-प्रतिनिधि इसके निर्माण में रुचि नहीं ले रहे हैं आने वाले दिनों में युवाशक्ति इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाई जाएगी, वहीं जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष डॉ विद्यानंद दास का मानना है कि जिला परिषद के द्वारा भी उक्त विधालय के निर्माण को लेकर प्रयास किये जा रहे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

देवघर नगर निगम चुनाव 2015

किसके सिर सजेगा महापौर का ताज

रणजीत झा

feedback@chauthiduniya.com

देवघर नगर निगम चुनाव में मेयर पद को लेकर अपनों के ही बीच खींच-तान का खेल चरम पर है. कल के सगे आज प्रतिद्वंदी बनकर हराने को आतुर हो रही महिलाओं के इस महासंग्राम में पैसों की गंगा बह रही है. कहने को तो केवल पांच लाख रुपये का खर्च मेयर पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन आयोग ने निर्धारित किया है लेकिन यह सब केवल कागजों तक सीमित है. देवघर की जनता ने आज तक देवघर की महिलाओं के बीच ऐसे चुनावी महासंग्राम के बारे में सोचा नहीं होगा. वैसे महिलायें तो सिर्फ उम्मीदवार की औपचारिकता मात्र होती रही हैं,परन्तु देवघर में मेयर पद की चुनावी दौड़ में महिलाओं का जोश और लगन साथ-साथ उत्तेजना देखकर नहीं लगता है कि देवघर नगर निगम की अगली मेयर जो कि महिला होने वाली है, वह सिर्फ मूर्तरूप होगी.

रीता चौरसिया
रीता नरौने
सावित्री देवी
रीता खवाड़े

मेयर पद की दौड़ में मुख्यरूप से चार महिला उम्मीदवार हैं जो शिक्षित, विरासत में मिले राजनीतिक अनुभव और नगर निगम के क्रियाकलापों से पूरी तरह अवगत हैं. कोई किसी से कम नहीं की स्थिति में चारों मैदान में डटी हुई हैं और निगम क्षेत्र के मतदाताओं को रिझाने तथा अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करती नहीं थक रही हैं.

मेयर पद की दौड़ में मुख्यरूप से चार महिला उम्मीदवार हैं जो शिक्षित, विरासत में मिले राजनीतिक अनुभव और नगर निगम के क्रियाकलापों से पूरी तरह अवगत हैं. कोई किसी से कम नहीं की स्थिति में चारों मैदान में डटी हुई हैं और निगम क्षेत्र के मतदाताओं को रिझाने तथा अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करती नहीं थक रही हैं. रीता चौरसिया को जहां अपने चिकित्सक पति डॉ आरके चौरसिया से भरपूर मनोवैज्ञानिक समर्थन मिल रहा है. वहीं रीता राज खवाड़े को पति मेयर राजनारायण खवाड़े जिन्हें पिछले निगम चुनाव में मतदाताओं ने रिकार्ड मतों से जीत दिलाई थी, उनके कार्यकर्ताओं की फौज का साथ मिल रहा है. सूबे के श्रम व नियोजन मंत्री राज पलिवार की बहन एवं आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता की पुत्री सावित्री देवी भी चुनाव लड़ने की रणनीति से वाकिफ हैं जिन्हें दो दशकों से राजनीति कर रहे पति संजयानंद झा जो कि वर्तमान में उप-महापौर हैं, उनका भी भरपूर स्वाभाविक साथ है. स्व कमल कांत नरौने, जिनकी आज भी निगम क्षेत्र के लोगों के दिल में अमिट छाप है, उनके समर्थकों के अलावा युवा समाजसेवी राकेश नरौने की माता रीता नरौने भी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं.

सुबह से शाम तक मतदाताओं को रिझाने का काम जारी हैं. वैसे महिलायें चुनाव लड़ रही हैं, परन्तु सभी प्रकार के चुनावी तिकड़मों का उपयोग चुनाव में हो रहा है. माना जाये तो इस बार चुनाव में दो प्रकार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी दिख रही है. एक तरफ मेयर पद की दावेदारी है, दूसरी ओर घरों में पर्दे में रहने वाली अपनी पत्नी,मां और बहन को जीत का ताज पहनाने का सपना भी है. इस प्रकार दिग्गजों ने अपनी सारी ताकत जीत के लिए झोंक दी है. सबसे रोचक है कि प्रदेश भाजपा ने रीता चौरसिया को भाजपा ने अपना समर्थित उम्मीदवार घोषित किया है, इसी भाजपा सरकार के मंत्री राज पलिवार की बहन सावित्री देवी भी भाजपा समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ खड़ी हैं. भाजपा समर्थित उम्मीदवार को अपने पार्टी समर्थकों का आसरा है. रीता नरौने को अपने समाजसेवी पुत्र राकेश नरौने की युवा फौज का ही आसरा है.

देवघर नगर निगम चुनाव में स्थानीय पंडा समाज के मतदाताओं का झुकाव खासा महत्व रखता है. वैसे निगम क्षेत्र में विगत दो दशकों में तेजी से बढ़ रहे बाहरी एवं दूसरे जिलों के अलावा पड़ोसी राज्य बिहार के लोगों की आबादी की मतदान में अहम भूमिका हो गई है. अब देखना है कि देवघर नगर निगम के इस महासंग्राम में किस महिला उम्मीदवार के सिर पहली महिला मेयर का ताज सजता है.■

एक नज़र

मां की कुर्बानी अनमोल

पूर्वी चम्पारण जिले के केसरिया प्रखंड के राजकीय उच्च विद्यालय केसरिया के प्रांगण में सेवा सदन के बैनर तले मातृ दिवस समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन कल्याणपुर की विधायक रजिया खातुन व जिला परिषद सदस्या पूनम देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्रीमती खातुन ने कहा कि मां द्वारा अपने बच्चों के लिए दी गयी कुर्बानी अनमोल होती है और इसकी भरपाई कभी नही होती. जिसके सिर पर मां का आंचल नहीं है उनसे जानना चाहिए कि मां की अहमियत क्या होती है. हमारे समाज में कुछ लोग मां को मां नहीं समझते और उसकी कदर नहीं करते जो हमेशा परेशान रहते हैं. कार्यक्रम को जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सीताराम यादव, पूर्व मुखिया राज कुमार प्रसाद, आशा देवी, शिक्षक सलीम, कवि रामपुकार गिरि, भाकपा नेता रामशरण यादव, अतिक खां, सेवा सदन अध्यक्ष किशोर कुमार सिंह, सचिव विनोद पटेल आदि ने संबोधित किया.

मजबूती से उतरेगा हम

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा(हम) आगामी विधान सभा का चुनाव लड़ेगी और सभी सीटों पर मजबूती के साथ उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे. उसके लिए रणनीति बन गयी है और आम जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है. बिहार की जनता पूर्व मुख्यमंत्री मांझी में आस्था व्यक्त कर रही है और उनकी नीतियों को अच्छी तरह से जान रही है. स्थानीय परिसदन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व मोर्चा के वरिष्ठ नेता महाचन्द्र प्रसाद सिंह तथा वीर सिंह पटेल ने उक्त बातें कहीं. उन्होंने कहा कि श्री मांझी की भावना मोतिहारी से जुड़ी हुई हैं और बड़ी संख्या में लोग मोर्चा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि विधानसभा वार सभा करने की नीति मोर्चा द्वारा तैयार की गयी है और शीघ्र संगठन का विस्तार किया जायेगा. जदयू के ध्रुवलाल मांझी, रालोसपा के विनोद राम, सफीरूल हक व मो फारूक आदि ने अपनी-अपनी पार्टियों से रिश्ता तोड़कर मांझी में आस्था व्यक्त करते हुए मोर्चा में शामिल हो गये हैं. इस मौके पर जिला पार्षद ज्योति सिंह, राज कुमार झा, विमल कांत त्रिपाठी, यशवंत निषाद, विनोद राम, अखिलेश यादव, रवीश कुमार मिश्र, इदय सिंह, सूरज चन्द्र रंजन आदि उपस्थित थे.

अश्लील विज्ञापन का विरोध

अश्लील विज्ञापन प्रकाशित होने के विरोध में हिन्दू नव जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर नुक्कड़ सभा आयोजित की और नारेबाजी की. नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए मंच के मुख्य जिला कार्यकारी दिनेश कुमार ने कहा कि मर्यादा पुरूषोतम श्रीराम के मॉन्टी कारलों कंपनी द्वारा जो विज्ञापन प्रकाशित कराये गेये हैं वे घोर निंदनीय हैं, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए. भारतीय सभ्यता व संस्कृति को नुक्सान पहुंचाने के साथ-साथ पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देने की भरपूर कोशिश इस विज्ञापन के माध्यम से की गयी है. मौके पर वीरेन्द्र जलान, नगर प्रधान विजय उपाध्याय, अमित कुमार, राज रोशन सिंह, शैलेन्द्र तिवारी, सहदेव वर्मा, बबलू कुमार, मुनिन्द्र पांडेय, चंदन पांडेय, सुधीर अग्रवाल, संजय कुमार तिवारी आदि ने संबोधित किया.

-इन्तेजारूल हक

सघन मतदाता संपर्क अभियान

बिहार विधान परिषद् के स्थानीय निकाय से होने वाले चुनाव के लिए भाजपा ने अपने निवृत्तमान पार्षद रजनीश कुमार को ही पुनः प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया है. यद्यपि यह चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पर नहीं होता है. लेकिन राजनीतिक दल अपना प्रत्याशी चुनाव में उतारते हैं. वर्त्तमान में बेगूसराय-खगड़िया निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनधित्व भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री एवं बिहार विधान परिषद में विरोधी दल के मुख्य सचेतक रजनीश कुमार कर रहे हैं. एमआरजेडी कॉलेज के सभागार में भाजपा जिला अध्यक्ष संजय कुमार की अध्यक्षता में जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में पार्टी के सांसद, विधायक, विधान पार्षद एवं कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित थे. बैठक में पार्टी के दूसरे चरण की सदस्यता अभियान पर विचार विमर्श किया गया. स्थानीय निकाय कोटा से होने वाले विधान परिषद के चुनाव में रजनीश कुमार की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी द्वारा सघन मतदाता संपर्क अभियान तेज करने का निर्णय लिया गया.

सम्मान समारोह आयोजित

बेगूसराय के मेयर संजय कुमार के कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने पर विभिन्न संगठनों ने दिनकर भवन में समारोह आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया. बेगूसराय ऑटो डीलर्स एसोसियेशन, बेगूसराय आईएमए, बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसियेशन, बेगूसराय जिला खेल महासंघ, बेगूसराय मोटर वाहन विक्रेता संघ, एसबीआईडब्लू, जिला परिवहन महासंघ, बीएमआरए , नागरिक समिति, बेगूसराय केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसियेशन, बेगूसराय जिला कब्ड्डी संघ, बेगूसराय गैरेज संघ, बेगूसराय कुश्ती संघ ने सम्मिलित रूप से समारोह आयोजित किया. ऑटो डीलर्स एसोसियेशन के अध्यक्ष रमेश सिंह ने समारोह की अध्यक्षता की. महापौर को शॉल एवं पुष्प गुच्छ प्रदान कर उपरोक्त संघों के पदाधिकारियों ने सम्मानित किया. समारोह से पूर्व रतनपुर वार्ड नंबर -21 स्थित मेयर संजय कुमार के आवास से हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैंड एवं मोटर साइकिल पर भव्य जुलूस निकाला गया जो मुख्य बाजार से होते हुए दिनकर भवन पहुंचा. खुली जीप पर सवार मेयर संजय कुमार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे. समारोह का संचालन रणधीर कुमार ने किया.

व्यवहार न्यायालय का उद्घाटन

बेगूसराय जिले के बखरी एवं मंझौल अनुमंडल मुख्यालय में अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय का उद्घाटन पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी ने किया. इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि त्वरित न्याय एवं न्यायालयों पर मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए न्यायालय का विस्तार किया जा रहा है. मुख्य न्यायाधीश के साथ जिले के निरीक्षी न्यायाधीश समरेन्द्र प्रताप सिंह, सूबे के भूमि सुधार, राजस्व एवं कानून मंत्री नरेन्द्र नारायण यादव, विधि सचिव अशोक कुमार जैन, जिला जज गोपाल कृष्ण द्विवेदी, बेगूसराय के सांसद डॉ भोला सिंह, जिलाधिकारी सीमा त्रिपाठी, आरक्षी अधीक्षक मनोज कुमार सहित अन्य गणमान्य नागरिक एवं अधिवक्तागण उपस्थित थे. मुख्य न्यायाधीश ने उद्घाटन के उपरांत वृक्षारोपण किया. साथ ही बेगूसराय जिला वकील संघ के नारायण प्रशाल में वकील नारायण प्रसाद सिन्हा के तैलचित्र का अनावरण किया.■

-सुरेश चौहान

समय बीतता गया, प्यार बढ़ता गया

राधिका

इस बार की कहानी है बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह और उनकी पत्नी पूर्णिमा शेखर की. इनका प्यार, पहली नज़र का प्यार तो नहीं है लेकिन समय के साथ पनपा हुआ प्यार है और ऐसे प्यार की नींव बहुत मजबूत होती है, जिसे चाह कर भी कोई हिला नहीं सकता. समय के साथ उनके बीच का रिश्ता गहरा होता चला गया, फिर क्या था उनके प्यार का कारवां ऐसा चला जिसने कभी पलट कर नहीं देखा. हर रुकावट को पार करता, हर मुश्किल से लड़ता, समाज के हर कटाक्ष का मिलकर जवाब देता. इस तरह दोनों के बीच एक अटूट रिश्ता बन गया.

पूर्णिमा बताती हैं कि, मैं और अंजनी दोनों पटना कॉलेज में पढ़ते थे. हम दोनों एक ही डिपार्टमेंट में थे. अंजनी मुझसे सीनियर थे और उन्हें उनके बैच के बेस्ट ग्रेजुएट का अवॉर्ड मिला था. तब हम लोगों ने उन्हें फेयरवेल पार्टी दी थी. इस फेयरवेल के दौरान हमारी पहली मुलाकात हुई थी. पूर्णिमा आगे कहती हैं कि अंजनी पढ़ाई में शुरू से ही बहुत अच्छे रहे हैं और मेरी भी रुचि पढ़ाई में बहुत ज्यादा रही है. जिस दौर में हम कॉलेज में थे, तब टॉपर होना बहुत एहमियत रखता था. पढ़ाई के सिलसिले में मेरी और अंजनी की बातचीत होने लगी. धीरे–धीरे हम दोस्त बन गए. फिर ऐसे ही समय बीतता गया.

मैं वहां चली तो गई, लेकिन वह जगह मेरे लिए बिल्कुल ही दूसरी दुनिया जैसी थी. सब कुछ बिलकुल अलग, लोग अलग, भाषा अलग आदि. उस कल्चर में एडजस्ट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था. लेकिन वहां पर काफी लोग ऐसे थे जो बिहार के थे. उन्हीं में से अंजनी भी एक थे. ऐसे में हमारा एक ग्रुप बन गया और हम लोग साथ–साथ रहने लगे. साथ रहने के दौरान मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर अंजनी के प्रति फीलिंग आ रही थी.

हम दोनों का मिलना–जुलना तो होता ही था. इसी दौरान मुझे यह बात पता चली कि अंजनी दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी(जेएनयू) में आगे की पढ़ाई करने जा रहे हैं. यह सुनकर मेरी भी बहुत इच्छा हुई कि मैं भी वहां जा कर पढ़ूं. फिर मैंने भी अपना एडमिशन जेएनयू में करवा लिया. और पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई. पूर्णिमा आगे बताती हैं कि, मैं वहां चली तो गई, लेकिन वह जगह मेरे लिए बिल्कुल ही दूसरी दुनिया जैसी थी. सब कुछ बिलकुल अलग, लोग अलग, भाषा अलग आदि. उस कल्चर में एडजस्ट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था. लेकिन वहां पर काफी लोग ऐसे थे जो बिहार के थे. उन्हीं में से अंजनी भी एक थे. ऐसे में हमारा एक ग्रुप बन गया और हम लोग साथ–साथ रहने लगे. साथ रहने के दौरान मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर अंजनी के प्रति फीलिंग आ रही थी. मुझे अंजनी की मैनेजमेंट क्षमता और उनके व्यक्तित्व आदि ने मुझे बेहद प्रभावित किया था. धीरे–धीरे हम दोनों को यह महसूस हुआ कि कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं. हमारे रिलेशनशिप की शुरुआत 1978 में हुई थी. इसके बाद आई शादी की बात. सत्तर के दशक में लव मैरिज करना बहुत बड़ी बात होती थी. हालांकि हम दोनों एक ही जाति के थे, इस वजह से हमारी शादी में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आईं. साथ ही अंजनी ने यूपीएससी का एक्जाम भी क्रैक कर लिया था, इस वजह से हमें अपने घरवालों को शादी के लिए मनाने में काफी सहूलियत हुई. करीब तीन साल लंबे रिलेशन के बाद सन 1981 में हमारी शादी हो गई.

बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह 1981 बैच के आईएएस ऑफीसर हैं. अंजनी सिंह शिक्षा, कला एवं संस्कृति विभाग के अलावा कृषि विभाग के प्रधान सचिव रह चुके हैं. वे लंबे समय तक बिहार शिक्षा परियोजना के राज्य परियोजना निदेशक भी रहे हैं. पूर्णिमा अंजनी के बारे में बताते हुए कहती हैं कि वो बहुत ही विनम्र और मृदुभाषी इंसान हैं. यदि मैं अपनी कोई भी इच्छा जाहिर कर दूं तो वे उसे पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं. इसके साथ–साथ वह मेरी बहुत इज्जत करते हैं. आज से नहीं बल्कि शुरुआत से ही उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी है, और मेरे सम्मान का बहुत ख्याल रखा है. हम दोनों के रिश्ते के बीच शक ने आज तक कदम नहीं रखा है. हम दोनों एक दूसरे को पूरा स्पेस देते हैं. शादी के इतने सालों बाद भी हमारा रिश्ता बहुत हीं सुंदर, खूबसूरत और प्यार से भरा है.

अंजनी कुमार सिंह और पूर्णिमा के दो बच्चे हैं एक बेटा और एक बेटी. आज उनका परिवार पूरी तरह से फल फूल रहा है. अंजनी और पूर्णिमा का रिश्ता हर दिन के साथ और मजबूत होता जा रहा है.■

feedback@chauthiduniya.com

भ्रष्टाचार का मुख्य केन्द्र बना बीएसएनएल

विरोध करने वाले कर्मियों पर होता है मुक़दमा

इन्तेजारूल हक़

टेलीफोन व मोबाईल उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधायें मुहैया कराने में हमेशा नाकाम साबित होने वाला भारत संचार निगम लिमिटेड इन दिनों भ्रष्टाचार का मुख्य केंद्र बना हुआ है और खुलेआम विभागीय आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए सरकार को चूना लगाया जा रहा है. विभागीय कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्राप्त धनराशि का मामला हो या फिर विभागीय संसाधनों के उपयोग करने का, या फिर नोफान प्रोजेक्ट के तहत ओएफसी केबल लेईंग के लिए की गयी संविदा का.सभी की स्थिति कमोबेश एक जैसी है. यहां खुलेआम विभागीय आदेशों की धज्जियां उड़ायी जाती हैं. यहां भ्रष्टाचार की जड़ें इस कदर मजबूत हो गई हैं कि इसका विरोध करने व भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई भी नहीं जुटा पाता है, यदि किसी छोटे(कनीय) अधिकारियों अथवा कर्मचारियों ने बोलने की हिम्मत की तो उसे या तो झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है या फिर अन्य तरह से उसे प्रताड़ित किया जाता है. चौथी दुनिया के हाथ कई ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिन्हें पढ़ने व देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि दूरसंचार विभाग भ्रष्टाचार का मुख्य केंद्र बना हुआ है.

हम अपनी बात शुरू करते हैं विभागीय कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्राप्त धन राशि से. जानकार बताते हैं कि मोतिहारी दूरसंचार विभाग जिला प्रबंधक के कार्यालय को कर्मचारियों के कल्याण के लिए लाखों रुपये मिले थे. उक्त राशि के उपयोग में मनमानी करते हुए विभागीय पुस्तिका खरीदी तो गई, लेकिन आज तक पूरी पुस्तिका विभाग में नहीं पहुंच सकी है. आखिर वह पुस्तिका कहां गईं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है.

दूसरा मामला नोफान प्रोजेक्ट के तहत ओएफसी केबल लेईंग के लिए निकाली गई निविदा का है. वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए हुई इस निविदा में टीडीएम विद्यानन्द ने अपने परिचित ठेकेदार को लाभ पहुंचाया. निर्धारित दर से दस प्रतिशत ज्यादा पर निविदा को मैनेज कराया गया और बलिया के एक ठेकेदार को टेंडर दिया गया.

तीसरा मामला विभागीय संसाधनों से जुड़ा हुआ है. संविदा के आधार पर काम करने वाले मजदूरों का. यहां विभाग में काम करने के लिए मजदूर संविदा पर बहाल तो हैं किन्तु अधिकारी उनसे अपना निजि काम विश्राम गृह में लेते हैं और उनका भुगतान विभाग द्वारा कराया जाता है. इसके अलावा विभागीय वाहनों का अपने निजि काम में मोतीहारी से सलेमपुर (बलिया) जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, प्रति सप्ताह ले जाया जाता है. इसी तरह के कई अन्य मामले हैं जिनकी जांच यदि निष्पक्षता से हो तो अनेक चौंकाने वाले तथ्य और मामले सामने आयेंगे. सबसे ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य यहां यह है कि जब इसका विरोध कुछ कर्मचारी व कनीय अधिकारी करते हैं तो उन्हें पहले हरिजन एक्ट में फंसाने की धमकी दी जाती है. और जब इससे बात नहीं बनती है तो कोई विभागीय आरोप लगाकर उन्हें झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है. जैसा कि कार्यालय के वरीय सहायक गंगा प्रसाद श्रीवास्तव व फोन मेकेनिक के पद पर तैनात राजेश कुमार चौबे के साथ किया गया है. गंगा प्रसाद पर स्थायी कर्मचारी हाजी मिंया की संचिका गायब करने का

मोतीहारी

आरोप लगाकर मुकदमा कर दिया गया. जबकि उक्त संचिका दुसरे कर्मचारी रामयत्न यादव के पास होने की बात जानकार करते हैं, और कहते हैं कि एक साजिश के तहत गंगा बाबू को फंसाया गया है. हाजी मिंया पूर्व में रक्सौल में कार्यरत थे. साढ़े तीन साल तक अवकाश में रहने के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर अप्रैल 2014 में एसडीओ (फोन्स) रक्सौल में योगदान करने गये थे. जहां एसडीओ ने उनकी ज्वाईनिंग नहीं ली थी. बाद में संघ की सहायता से टीडीएम मोतिहारी से वार्ता हुई और और एक अप्रैल को योगदान कराया गया. वहीं फोन मैकेनिक के पद पर तैनात राजेश कुमार चौबे कर्मचारी संघ के सचिव हैं और बार–बार कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सक्रिय रहते हैं जो कि टीडीएम विद्यानन्द राम को रास नही आता है. जैसा कि उन्होंने हाजी मियां के मामले में पहल की थी. हालांकि राजेश कुमार चौबे ने सदर के अनुमंडल पदाधिकारी को एक इन्फॉर्मेशन पेटिशन भी दी है और कोई झूठा मुक़दमा उन पर न हो या उनकी जान–माल की क्षति न हो, इसके लिए विस्तार से लिखा है. दूसरी तरफ यह भी चर्चा है कि इस मामले में अन्य लोगों और यहां तक कि अवकाश प्राप्त कर चुके लोगों को भी बेवजह परेशान करने और गलत तरीके से फंसाने की योजना बनायी जा रही है. कुल मिलाकार मोतीहारी का दूरसंचार कार्यालय इन दिनों भ्रष्टाचार की वजह से काफी सुर्खियों में है. जिला प्रबंधक की मनमानी की वजह से कभी भी कर्मचारी सड़क पर उतर सकते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

Mob. : 9386745004, 9204791696
www.iiher.org,
Email : anilsulabh6@gmail.com

INDIAN INSTITUTE OF HEALTH EDUCATION & RESEARCH
Health Institute Rd, Beur (Near Central Jail), Patna -2.
(Recongnised by Govt. of Bihar, RCI, Govt. of India, IAP & ISPO)
AFFILIATED TO MAGADH UNIVERSITY, BODHGAYA

POST GRADUATE COURSES :

Name of Courses		Eligibility	Duration
MPT	Master of Physiotherapy	BPT	2yrs.
MOT	Master of Occupational Therapy	BOT	2yrs.

DEGREE COURSES

BPT	Bachelor of Physiotherapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BOT	Bachelor of Occupational Therapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BPO	Bachelor of Prosthetic & Orthotic	I.Sc	4yrs.+6 Months of Internship
BASLP	Bachelor of Audiology & Speech Language Pathology	I.Sc	3yrs.+1 year of Internship
BMLT	Bachelor of Medical Laboratory Technology	I.Sc	3yr.+6 Months of Internship
BMRIT	Bachelor of Radio Imaging Technology	I.Sc	3yrs.+6 Months of Internship
B.Ophth.	Bachelor of Ophthalmology	I.Sc	4yr.+6 Months of Internship
B.Ed.	(Special Education)	Graduate	1yr.

1 YEAR ABRIDGED DEGREE FOR DPT / DOT

DIPLOMA COURSES :

DPT	Diploma In Physiotherapy	I.Sc (Bio)	3yrs.+6 Month of Internship
D-X-Ray	Diploma In X-Ray Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DMLT	Diploma In Medical Laboratory Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DECG	Diploma In E.C.G.	I.Sc (Bio)	2yr.
DOTA	Diploma In O.T. Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DHM	Diploma In Hospital Management	Graduate	1yr.
CMD	Certificate in Medical Derssing	Matirc with Science & English	1yr.

ADMISSION OPEN

Form & Prospectus -
Can be obtained from the office against a payment of Rs. 500/-. only by cash. Send a DD of Rs. 550/- only in the favour of Indian Institute of Health Education & Research, Patna, for postal delivery.

डा. अनिल सुलभ
निदेशक प्रमुख

"टी.आई." ब्राण्ड शटरपत्ती
क्वालिटी में सर्वोत्तम

मजबूती हमारी सुरक्षा आपकी.....

AL अलीगढ़ लॉक्स TM प्रा.लि.

पीरमुहानी,जगत जननी माता मन्दिर के नजदीक, पटना–3
फोन : 0612-3293208, 6500301, Email : aligarhlocks@gmail.com
अपने क्षेत्र बिहार का प्रथम एवं एकमात्र TM प्रतिष्ठान नक्कालों से सावधान
कृपया हमारे इस नाम से मिलते–जुलते प्रतिष्ठान को देख भ्रमित न हों।

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

25 मई–31 मई 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

जया प्रदा को विधान परिषद ले जाने की सपा में चर्चा

समाजवादी पार्टी कुनबा बढ़ाने में जुटी

सौ सदस्यों वाली विधान परिषद में मनोनीत कोटे की 10 सीटें होती हैं. 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती सरकार ने नौ सदस्यों का मनोनयन किया था जबकि एक का मनोनयन वर्ष 2010 में किया गया था. मंगल सैनी के निधन के बाद नौ में से एक सीट खाली हुई थी. उस पर 2012 में सपा सरकार ने बनवारी सिंह यादव को मनोनीत कर दिया था. विधान परिषद की खाली हो रही सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी में सियासत सरगर्म है.

प्रभात रंजन दीन

अमर सिंह की समाजवादी पार्टी में वापसी की भूमिका फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा के उत्तर प्रदेश विधान परिषद में मनोनयन से पुख्ता हो सकती है. इस भूमिका के लिए पार्टी के अंदर अब अधिक नेता सकारात्मक भूमिका में हैं तो कुछ नेता अब भी नकारात्मक भूमिका अदा कर रहे हैं. जया प्रदा को लेकर सपा के वरिष्ठ मंत्री आजम खान के मन के पूर्वाग्रह दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे. हालांकि जया प्रदा के विधान परिषद में चले जाने से रामपुर विधानसभा या लोकसभा को लेकर बना रहने वाला आजम का सिरदर्द थोड़ा थम जाएगा. उत्तर प्रदेश विधान परिषद की खाली हो रही नौ सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में ही जाएंगी. लेकिन इन नौ सीटों पर मनोनयन पार्टी की भावी राजनीति की दशा–दिशा भी तय करेगी. कई नए पत्ते खुलेंगे और कई पत्ते वापस खीसे में रख लिए जाएंगे. मनोनयन से ही भरी जाने वाली सभी नौ सीटों के लिए नाम तय ही हो चुके हैं. मनोनयन पर राज्यपाल की औपचारिक मुहर लगते ही नाम भी सार्वजनिक हो जाएंगे और सपा की प्राथमिकताएं भी सार्वजनिक हो जाएंगी. पार्टी के नेता ही बताते हैं कि मनोनयन के लिए चुने गए नामों में जया प्रदा का नाम भी शामिल है. अगर यह सत्य है तो अमर सिंह की सपा में वापसी की सुगबुगाहट भी सत्य है. इधर तो सपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी कहना शुरू कर दिया है कि अमर सिंह की सपा में वापसी पर कोई विरोध नहीं है. पिछले दिन सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने कहा था कि अब अमर सिंह ही बताएंगे कि वे सपा में कब आ रहे हैं. इसके बाद शिवपाल का फिर बयान आया कि अमर सिंह को सपा में वापस लिए जाने को लेकर कोई अड़चन नहीं है और न ही उनका कहीं कोई विरोध कर रहा है. सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और शिवपाल यादव से अमर सिंह की इधर जितनी मुलाकातें हुई हैं, वह क्रमशः अंतरंग होती गई हैं. पारिवारिक स्तर पर भी अमर सिंह के पक्ष में जनमत है. लिहाजा, जया प्रदा का विधान परिषद में मनोनयन अमर सिंह की सपा में वापस का ग्रीन–सिगनल होगा. जया प्रदा को विधान परिषद में मनोनीत कर उन्हें राज्य में मंत्री का पद भी दिया जा सकता है, पार्टी गलियारे में इस बात को लेकर चर्चा है. कुछ सपा नेता बताते हैं कि मुलायम ने पिछले दिनों अमर सिंह से हुई मुलाकात के बाद जया प्रदा के नाम पर सहमति दे दी थी.

हालांकि जयाप्रदा और अमर सिंह के नाम पर आजम खान की नाराजगियां सार्वजनिक होती रही हैं. लेकिन भविष्य के बदलते समीकरण और पार्टी की जरूरतें आजम को दरकिनार और अमर को धारा में लाने के संकेत दे रही हैं. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले ही बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं. राजपूत समुदाय का समर्थन हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी और सरकार की कोशिशें सामने दिख रही हैं. उत्तर प्रदेश में अरविंद सिंह गोप को ताकतवर महासचिव बना कर और महाराणा प्रताप जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर सपा ने राजपूतों में पैठ बनाई है. इस पैठ को सपा राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहती है, लिहाजा उसे अमर सिंह जैसे ठाकुर नेताओं की जरूरत है. अमर सिंह के पार्टी में वापसी बिहार चुनाव से होते हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव पर अपना असर दिखाएगी. समाजवादी पार्टी के छत्र के नीचे देशभर के समाजवादियों के संभावित विलय और सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव की राष्ट्रीय भूमिका के मद्देनजर भी अमर सिंह की जरूरतें महसूस की जा रही हैं. अमर सिंह के बाद अगला अध्याय कुर्मी नेता बेनी प्रसाद वर्मा का खुलने वाला है. मुलायम के कभी नजदीकी मित्र रहे बेनी भी सपा के नए राजनीतिक कलेवर में मुलायम के साथ दिख सकते हैं, इस पर नेतृत्व का मन बन चुका है. लिहाजा, विधान परिषद का यह मनोनयन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, जो एक साथ कई फिल्मों के ट्रेलर दिखाएगा.

उत्तर प्रदेश विधान परिषद में मनोनयन के लिए लालू यादव के समधी जीतेंद्र सिंह यादव का नाम भी चल रहा है. जीतेंद्र के नाम के साथ–साथ अशोक सिंह का नाम भी चल रहा है, जो कभी विश्वनाथ प्रताप सिंह के करीबी थे, अब लालू के करीबी बने हुए हैं. अब देखना है कि मुलायम यादव चुनते हैं या ठाकुर. 25 मई को विधान परिषद के नौ सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है. कार्यकाल पूरा करने वाले सदस्यों में बहुजन समाज पार्टी के आठ सदस्य हैं जबकि समाजवादी पार्टी के एक सदस्य हैं. विधान परिषद की ये सभी नौ सीटें समाजवादी पार्टी की हो जाएंगी. अब विधान परिषद में भी समाजवादी पार्टी ताकतवर पार्टी बन जाएगी और बहुजन समाज पार्टी की ताकत कम हो जाएगी. विधान परिषद में अभी तक बीएसपी के 54 सदस्य हैं, इनमें नौ का कार्यकाल 25 मई को पूरा होगा. खाली सीटों पर सपा के नौ नए सदस्य हो जाएंगे. अभी सपा के 26 सदस्य हैं. 25 मई के बाद इनकी संख्या 35 हो जाएगी जबकि बीएसपी के 45 सदस्य रहेंगे. जिन विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें बसपा के कमलाकांत गौतम, डॉ. गोपाल नारायण मिश्र, नौशाद अली, एमएल तोमर, डॉ. मेघराज सिंह, रामचंद्र प्रधान, विनय शाक्य और शिवबोध राम शामिल हैं. समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य बनवारी सिंह यादव का कार्यकाल भी 25 मई को पूरा हो जाएगा.

सौ सदस्यों वाली विधान परिषद में मनोनीत कोटे की 10 सीटें होती हैं. 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती सरकार ने नौ सदस्यों का मनोनयन किया था जबकि एक का मनोनयन वर्ष 2010 में किया गया था. मंगल सैनी के निधन के बाद नौ में से एक सीट खाली हुई थी. उस पर 2012 में सपा सरकार ने बनवारी सिंह यादव को मनोनीत कर दिया था. विधान परिषद की खाली हो रही सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी में सियासत सरगर्म है. सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लेकर अन्य वरिष्ठ नेताओं तक लॉबिंग और पैरवियां चल रही हैं. लेकिन समाजवादी पार्टी नेतृत्व की निगाह 2017 के विधानसभा चुनाव पर है, लिहाजा केवल सियासी समीकरणों को ही ध्यान में रखा जा रहा है. अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, सवर्ण सभी समुदायों का समर्थन पाने के साथ–साथ शीर्ष स्तरीय सद्भाव और उपकार जो पार्टी को भविष्य में फायदा पहुंचाएगा, को ही प्राथमिकता में रखा जा रहा है.

विधान परिषद में मनोनयन के लिए सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका है. इस सूची

जया प्रदा और अमर सिंह के नाम पर आजम खान की नाराजगियां सार्वजनिक होती रही हैं. लेकिन भविष्य के बदलते समीकरण और पार्टी की जरूरतें आजम को दरकिनार और अमर को धारा में लाने के संकेत दे रही हैं. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले ही बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं. राजपूत समुदाय का समर्थन हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी और सरकार की कोशिशें सामने दिख रही हैं. उत्तर प्रदेश में अरविंद सिंह गोप को ताकतवर महासचिव बना कर और महाराणा प्रताप जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर सपा ने राजपूतों में पैठ बनाई है.

में जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन के साथ–साथ नेतृत्व–स्तरीय तालमेल स्थापित करने की कवायद भी शामिल है. पार्टी के सूत्र कहते हैं कि राज्यपाल के मनोनयन के लिए सूची राज्यपाल को भेजी भी जा चुकी है, लेकिन एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बीते एक मई को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, राष्ट्रीय महासचिव प्रो. राम गोपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने विधान परिषद के लिए मनोनीत होने वाले नेताओं की सूची पर निर्णायक विचार–विमर्श किया और जो प्रमुख लोग मनोनयन से वंचित रह जाएंगे उन्हें विभिन्न सरकारी संस्थाओं, निगमों, परिषदों व आयोगों में समायोजित किए जाने के मसले पर भी विचार किया. नौ मई को भी मुलायम ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ विधान परिषद सदस्यों के मनोनयन पर चर्चा की. लिस्ट में 16 नाम शामिल हुए हैं, जिनमें से नौ आखिरी तौर पर चुने जाएंगे. राजभवन के एक अधिकारी ने कहा कि विधान परिषद के मनोनीत होने वालों की सूची राज्यपाल के पास 25 मई तक आनी है. सरकार की ओर से जो भी नाम भेजे जाएंगे, उनका परीक्षण कराया जाएगा.

बहरहाल, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने डॉ. राजपाल कश्यप को मत्स्य विकास निगम का अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्यता से मुक्त हो रहे बनवारी सिंह यादव को पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का चेयरमैन बनाकर विधान परिषद का रास्ता साफ किया. उन्होंने सपा नेता शतरुद्ध प्रकाश को श्रम संविदा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया तो सुरेंद्र मोहन अग्रवाल को लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष बना कर चार नेताओं के नाम विधान परिषद की लिस्ट से हटवा लिए. इस बार विधान परिषद जाने के लिए काफी नेता कतार में लगे धक्का–मुक्की कर रहे हैं. सपा नेतृत्व इस बार राजनीतिक–सामाजिक समीकरण मजबूत करने वाले तेज तर्रार नेताओं को ही विधान परिषद भेजेगी, यह तय है. अभी जनवरी में हुए विधान परिषद चुनाव में सपा के आठ सदस्यों में से छह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और दो पूर्वांचल से थे. पूर्वांचल सपा का गढ़ है और सपा को पूर्वांचल से ही विशेष राजनीतिक लाभ मिलता है. ऐसे में इस बार के मनोनयन में पूर्वांचल को प्राथमिकता दिए जाने की सम्भावना है. अभी पूर्वांचल से अति–पिछड़ा समुदाय के रामसुंदर दास (देवरिया) व रामजतन राजभर (मऊ) सपा से विधान परिषद सदस्य हैं. लौटन राम निषाद जैसे कुछ और अति–पिछड़ों को मौका मिल सकता है. कुछ संभावित यादवों में सपा के कार्यालय प्रभारी एसआरएस यादव और लालू प्रसाद यादव के समधी जीतेंद्र यादव (गाजियाबाद) का नाम चल रहा है. संभावित भूमिहारों में उज्जवल रमण सिंह और डॉ. सीपी राव, राजपूतों में आनन्द सिंह भदौरिया और भगवती सिंह और मुसलमानों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष जावेद आब्दी के नामों की चर्चा है. ■

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश की खबरें इंटरनेट पर पढ़ने के लिए www.up.chauthiduniya.com लॉगऑन करें.

www.chauthiduniya.com चौथी दुनिया

पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने कहा, दाऊद पाकिस्तान में नहीं है

सूफी वायावर

लखवी की हिमायत करने वाले पाकिस्तान उच्चायुक्त का लखनऊ में खूब स्वागत हुआ. लखनऊ की धरती पर पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कुख्यात आतंकी दाऊद इब्राहीम को साहेब बताया और भारत की धरती पर भारत को खूब नसीहतें दीं. लखनऊ के मीडिया वालों ने इन नसीहतों पर खूब खीसें निपोरीं और लखनवी नफासत दिखाने में बिछ-बिछ गए. पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात भी की, उनके साथ बिरयानी भी खाई और पाकिस्तान आने का न्यौता भी दिया. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स (फिक्की) के कार्यक्रम में शरीक हुए भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने आतंकवाद को भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए साझा चुनौती बताया और कहा कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच बातचीत दोबारा शुरू किए बगैर दोनों मुल्कों के बीच व्यापारिक सम्बन्धों का सिलसिला मजबूती से आगे नहीं बढ़ सकता. बासित ने कहा कि दहशतगर्दी एक बड़ी समस्या है. पिछले 35 वर्षों में पाकिस्तान में आतंकवाद की वारदात में 50 हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 100 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है. दहशतगर्दी भारत और पाकिस्तान दोनों के ही सामने साझा चुनौती है.

बातचीत को शांति की स्थापना का एकमात्र रास्ता बताते हुए बासित ने कहा, दहशतगर्दी के मुद्दे पर अगर आपको (भारत) कुछ शिकायतें हैं तो कुछ शिकायतें हमारी भी हैं. भारत और पाकिस्तान के व्यापारिक रिश्ते दोनों देशों के राजनीतिक मिजाज में होने वाले बदलावों पर निर्भर करते हैं. मुख्य समस्या यह है कि वे एक-दूसरे की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं और दो कदम पीछे हट जाते हैं. व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने के लिए हमें लगातार आगे बढ़ना होगा. पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का शरीक होना बहुत अच्छी पहल थी, लेकिन अफसोस यह है कि वह व्यर्थ हो गई. बासित इसके लिए पाकिस्तानी सेना की करतूतों और आतंकी सरगनाओं की शह का सच गोल कर गए. कहा कि भारत और पाकिस्तान पिछले एक साल से बातचीत नहीं कर रहे हैं. इससे आपसी रिश्ते आगे नहीं बढ़ेंगे. हमें राजनीतिक माहौल को भी साथ लेकर चलना होगा. अब्दुल बासित ने कहा, भारत-पाक संबंधों में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम जब भी एक कदम आगे बढ़ते हैं, हालात ऐसे बन जाते हैं कि दूसरे पक्ष के लोग दो कदम पीछे हो जाते हैं. दोनों सरकारों के बीच बातचीत रुकी हुई है. हम हमेशा अतीत में नहीं रह सकते हैं. जब तक दोनों देश साथ बैठकर बात नहीं करेंगे, व्यापार और शांति आगे नहीं बढ़ सकती है.

पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने कहा कि वर्ष 2011 में दोनों मुल्कों ने छह अरब डॉलर का परस्पर व्यापार करने का लक्ष्य रखा था लेकिन राजनीतिक उतार-चढ़ाव के कारण वह अभी तक पूरा नहीं हो सका. इस वक्त दोनों देशों का आपसी व्यापार दो अरब 70 करोड़ डालर तक ही सीमित है. व्यापार के लिहाज से एक-दूसरे पर निर्भरता और परस्पर निवेश बढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि एक-दूसरे पर निर्भरता बढ़ाना जरूरी है और दोनों मुल्कों के व्यापारियों का एक-दूसरे के देशों में निवेश करना भी आवश्यक है. सिर्फ व्यापार करने से बात नहीं बनेगी, निवेश भी करना होगा. बासित ने दावा किया कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक असंतुलन भारत के पक्ष में बढ़ रहा है. दोनों मुल्कों के बीच जब भी फिर से बात शुरू होगी तो इस बिंदु पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा. उम्मीद है कि पाकिस्तान को भी बराबर का मौका मिलेगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मेक इन इंडिया की परिकल्पना का जिक्र करते हुए बासित ने कहा कि भारत ने इस सपने को साकार करने के लिये जरूरी तैयारी शुरू कर दी है लेकिन पाकिस्तानी अभी उस स्थिति में नहीं पहुंच सका है. फिक्की के कार्यक्रम का आधार वैसे तो दोनों देशों के व्यापार को बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना था, लेकिन पाक उच्चायुक्त आतंकवाद पीड़ित देश और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के साथ आर्थिक रुकावटों का एकतरफा रोना रोकर चले गए. बासित ने बताया कि इस समय भारत-पाक व्यापार 2.7 बिलियन है, जो काफी कम है. भारत ने हमें मोस्टा फेवर्ड कंट्री का दर्जा 1996 में ही दे दिया था और वह भी पाकिस्तान से यही चाहता है. वहीं, हमारे यहां एक तबका ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि ऐसा करने से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचेगा. बासित को यह भी शिकायत थी कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई पर भारत कभी हमारी प्रशंसा नहीं करता. ऐसा कहते समय बासित को जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को हवा दिए जाने और अलगाववादी शक्तियों को भड़काए जाने की करतूतें जरूर याद रही होंगी, जिसमें बासित खुद भी मुब्तिला रहते हैं.

फिक्की के उत्तर प्रदेश परिषद के अध्यक्ष एलके झुनझुनवाला ने इस मौके पर कहा कि भारत और पाकिस्तान के आपसी व्यापारिक रिश्तों पर राजनीतिक उतार-चढ़ाव का काफी असर पड़ता है और फिक्की इन सम्बन्धों को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है. ■

बासित ने दाऊद को साहब कहा

कुख्यात आतंकी सरगना दाऊद इब्राहीम के पाकिस्तान में छुपे होने के सवाल पर पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा, वो साहब तो पाकिस्तान में नहीं हैं. इससे ज्यादा क्या कहूं. यूपी प्रेस क्लब में बासित ने कहा कि जहां तक मुंबई हमले के मुकदमे का सवाल है, दुनिया में कोई दहशतगर्दी को उचित नहीं ठहरा सकता. बेगुनाह लोगों के मारे जाने को सही नहीं ठहराया जा सकता. 2008-09 में सात लोग गिरफ्तार किए गए थे. मुकदमा चल रहा है. जहां तक पाकिस्तान सरकार का सवाल है, इस सिलसिले में चल रहे अदालती मामले में वह पूरी गंभीरता बरत रही है. एक प्रक्रिया है, जिसे चलनें दें. हाफिज जमानत पर है, पर मुकदमा तो चल ही रहा है. अदालत का जो भी फैसला होगा, सरकार उसका सम्मान करेगी. अदालतों के मामले अदालतों तक ही रहने दीजिए. हमें इंतजार करना चाहिए. मामला चूंकि अदालत में है, इसलिए हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी जकीउर रहमान लखवी की लगातार की गई हिमायतों के बारे में भी पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने कुछ नहीं बोला. जम्मू कश्मीर मसले पर बासित ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को लेकर आपका एक नजरिया है, हम उसकी कद्र करते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हम उससे इत्तेफाक रखते हों. कश्मीर मसले का हल वही होगा, जो वहां की अवाम चाहेगी. ऐसा कोई भी हल जो जम्मू कश्मीर के लोगों को मंजूर नहीं, हल नहीं होगा. बासित ने कहा कि वह समझते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से ही हो सकता है. अमन बातचीत से ही आ सकता है. इस एक तरफा बयानबाजी के बीच जब पाकिस्तानी उच्चायुक्त से पाकिस्तान सेना की ओर से संघर्ष विराम तोड़ने को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा, यह आपका नजरिया है. हालांकि फिर उन्होंने यह भी कहा कि सीमा के इस पार और उस पार दोनों ही ओर कुछ ताकतें हैं जो नहीं चाहतीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति कायम हो. ■

अखिलेश को पाकिस्तान आने का न्यौता

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनसे सरकारी आवास पर मिलने गए पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने उन्हें पाक आने का न्यौता दिया, जिसे उन्होंने मान लिया. बासित ने संवाददाताओं से कहा, मैंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें पाकिस्तान आमंत्रित किया है. उन्होंने सिद्धांततः निमंत्रण स्वीकार कर लिया है. बासित ने बताया कि लखनऊ में उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मानो वह अपने देश पाकिस्तान के किसी शहर में हों. उन्होंने कहा कि इस शहर के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं और शिष्टाचार में उनका जवाब नहीं. ■

feedback@chauthiduniya.com

सपा नेता निकला महा-जालसाज

प्रांजल अंशुमान

एक साथ 14-14 गनर रखने वाले सपा के एक स्वयंभू नेता ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सरकारी आवास के टेलीफोन नंबर से न्यूजीलैंड के दिल्ली स्थित दूतावास पर कई बार बात की. राज्य के दो पूर्व पुलिस महानिदेशकों से आलू में मोटी कमाई के नाम पर करोड़ों रुपये हथियाए. कई और आईपीएस अफसरों से निवेश के नाम पर लम्बी रकम वसूली और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एके जैन के सीयूजी नंबर से दर्जनों फोन किए. इतने बड़े-बड़े स्तर पर चमत्कार दिखाने वाला जालसाज दो दारोगाओं से जालसाजी करता हुआ पकड़ लिया गया. सफेद लकदक कुर्ता-पायजामा पहनकर डीजीपी दफ्तर में धड़ल्ले से प्रवेश पाने वाला सपा नेता शैलेन्द्र अग्रवाल फिलहाल जेल में है.

खुद डीजीपी बनकर फोन पर दो दारोगाओं को धमकाने और उनसे दस लाख रुपये वसूलने के आरोप में जालसाज शैलेंद्र अग्रवाल पकड़ा तो गया, लेकिन जानकारियां बताती हैं कि कॉल स्पूफिंग यानि इंटरनेट के जरिए दूसरों के मोबाइल और लैंडलाइन नंबर की फेक कॉल के माहिर इस सफेदपोश अपराधी ने कई बड़े लोगों से पचासों करोड़ रुपये की ठगी की है. ठगे जाने वालों में सपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रहे दो सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी बताए जाते हैं, जिनसे इसने 36 फीसदी ब्याज दर की शर्त पर करोड़ों रुपये का निवेश आलू भंडारण के लिए कराया. एक अफसर से तो 14 करोड़ रुपये का निवेश आलू के नाम पर कराने के बाद यह जालसाज मुकर गया. करोड़ों रुपये गंवाने वाले कई रिटायर्ड और मौजूदा पुलिस अधिकारी किसी तरह अपना नाम इस जालसाजी मामले से दूर रखने के ही प्रयास में लगे हैं. आगरा के विभवनगर कॉलोनी का रहने वाला शैलेन्द्र अग्रवाल समाजवादी पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों में अक्सर सक्रिय दिखता रहा है और सत्तारूढ़ दल के कई कद्दावर नेताओं से भी इसका मिलना-जुलना तस्दीक हुआ है. कॉल स्पूफिंग के जरिए शैलेन्द्र अग्रवाल ने मुख्यमंत्री आवास-5, कालिदास मार्ग के लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल दर्जनों बार किया है. इसने खुद को मुख्यमंत्री दफ्तर में तैनात सीनियर अफसर बताकर दिल्ली स्थित न्यूजीलैंड दूतावास के अधिकारियों से भी कई बार बात की. अब छानबीन चल रही है कि दूतावास के अधिकारियों से बातचीत में क्या गुल खिलाया गया. पुलिस के सूत्र बताते हैं कि शैलेंद्र अग्रवाल ने काम निकालने के लिए राज्य के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाइल नंबर की क्लोनिंग की.

प्रो.रामगोपाल यादव का जालसाज पीए

जालसाज सपा नेता

> दो साल पहले अग्रवाल ने दोनों दारोगाओं से आलू में मोटी कमाई होने का हवाला देते हुए कर्ज के रूप में पांच-पांच लाख रुपये ले लिए, लेकिन वापस करने में आनाकानी करने लगा. पुलिस ने बताया कि अग्रवाल ने 16 अप्रैल को दारोगा विजय सिंह के मोबाइल पर डीजीपी के सीयूजी और लैंड लाइन नंबर से इंटरनेट फेक कॉल किया और धोखाधड़ी के मामले में डीजीपी बन कर पूछताछ करने लगा. बातचीत के दौरान शक होने पर दारोगा ने डीजीपी मुख्यालय फोन कर जानकारी ली, जहां से पता चला कि वहां से तो कोई कॉल ही नहीं किया गया.

शैलेन्द्र अग्रवाल ने कॉल स्पूफिंग का इस्तेमाल करते हुए डीजीपी, शासन के वरिष्ठ अधिकारी और मुख्यमंत्री के घर और दफ्तर के नम्बरों के झांसे में कई जिलों के डीएम और एसपी को अर्दब में रखा था. इसी के चलते अग्रवाल के पास अलग-अलग जिलों से कुल 14 गनर की तैनाती मिली हुई थी. डीजीपी के सीयूजी मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर की भी कॉल स्पूफिंग कई बार की गई. इसकी आधिकारिक पुष्टि हुई है. इसी नम्बर की कॉल स्पूफिंग से उसने जीआरपी के दारोगा विजय सिंह और उसके एक और साथी दारोगा धीरजपाल सिंह को डीजीपी बनकर हड़काया और जब उधर से उलटी कॉल आई तो मामला पकड़ में आ गया. खुद को समाजवादी पार्टी का उपाध्यक्ष बताने वाले अग्रवाल ने धोखाधड़ी के इस तरीके से सैकड़ों लोगों को बेवकूफ बनाया और करोड़ों रुपये इकट्ठा किए. 36 प्रतिशत ब्याज का भारी मुनाफा पाने की लालच में फंसे लोगों को जब एक भी पैसा नहीं मिला तो उन्होंने शैलेन्द्र अग्रवाल के घर तगादे शुरू किए. ज्यादातर फंसे लोग गनरों की भरी फौज की तलाशी के चक्कर में अग्रवाल से मिल भी नहीं पाते थे. आगरा पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि राजामंडी चौकी पर तैनात रहे जीआरपी दारोगा विजय सिंह और उनके साथी उपनिरीक्षक धीरजपाल सिंह की शैलेंद्र अग्रवाल से वर्ष 2013 में मुलाकात हुई थी. उसने दोनों दारोगाओं को अपना परिचय सपा प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में दिया था. मथुरा के मूल निवासी शैलेंद्र अग्रवाल का ताजगंज के विभव नगर स्थित एक अपार्टमेंट में फ्लैट है.

दो साल पहले अग्रवाल ने दोनों दारोगाओं से आलू में मोटी कमाई होने का हवाला देते हुए कर्ज के रूप में पांच-पांच लाख रुपये ले लिए, लेकिन वापस करने में आनाकानी करने लगा. पुलिस ने बताया कि अग्रवाल ने 16 अप्रैल को दारोगा विजय सिंह के मोबाइल पर डीजीपी के सीयूजी और लैंड लाइन नंबर से इंटरनेट फेक कॉल किया और धोखाधड़ी के मामले में डीजीपी बन कर पूछताछ करने लगा. बातचीत के दौरान शक होने पर दारोगा ने डीजीपी मुख्यालय फोन कर जानकारी ली, जहां से पता चला कि वहां से तो कोई कॉल ही नहीं किया गया.

दारोगा विजय सिंह की तरफ से डीआईजी के यहां दिए गए प्रार्थनापत्र पर ताजगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने छापा मार शैलेंद्र अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया और उसके फ्लैट की तलाशी ली. वहां से सचिवालय के पास और अन्य कागजात बरामद हुए. पुलिस ने यह भी कहा कि शैलेंद्र अग्रवाल को दस वर्ष पूर्व न्यू आगरा से एक आयकर अधिकारी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसकी हत्या कर उसका शव फिरोजाबाद में फेंका गया था. शैलेंद्र पर पिछले तीन साल से जालसाजी के जरिए तीन सौ करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है. शैलेंद्र अग्रवाल का पासपोर्ट भी पुलिस ने जब्त कर लिया है. ठगी के जाल में फंस चुके पीड़ित व्यापारी रिंकेश अग्रवाल ने पुलिस को बताया है कि शैलेंद्र अग्रवाल ने कई व्यापारियों से आलू-प्याज की ट्रेडिंग में इनवेस्टमेंट और कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के नाम पर करोड़ों रुपये लिए हुए थे. लोगों से सरकारी काम करवाने के एवज में भी वह लोगों से पैसे ऐंठता था. ■

ऐसे और भी है जालसाज सपा नेता

लखनऊ पुलिस ने भी कुछ दिनों पहले ऐसे ही एक ठग सपा नेता को पकड़ा था. उस ठग सपा नेता की विशेषज्ञता यह थी कि वह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठत नेता प्रो. रामगोपाल यादव का पीए बनकर लोगों को खुलेआम ठगता था. जालसाज ने खुद को रामगोपाल यादव का करीबी बताकर सपा के ही दो मौजूदा विधायकों को मंत्री बनवाने का झांसा दिया था. मूल रूप से बाराबंकी के रामपुर इलाके का रहने वाला वीरेन्द्र कुमार अपने कारनामे से कई लोगों को करोड़ों रुपये का चूना लगा चुका है. मामूली पढ़ाई करने के बाद शिक्षा मित्र की नौकरी शुरू करने के बाद वहां नियुक्ति का झांसा देकर उसने कई लोगों को ठगा. लेकिन उसकी करतूतों का खुलासा होने के बाद उसको नौकरी से निकाल दिया गया. उसके बाद वह जालसाजी के बड़े खेल खेलने लगा. शिक्षा मित्र की नौकरी से बर्खास्त होने के बाद वीरेन्द्र ने राजधानी लखनऊ को ही अपना नया ठिकाना बना लिया. उसने एक ट्रैवेल एजेंसी खोल ली और फिर मंत्रियों की गाड़ी चलाने लगा. इसी दौरान वीरेंद्र ने अपने आपको सपा के वरिष्ठ नेता प्रो. रामगोपाल यादव का पीए बताकर लोगों को नौकरी दिलाने और सरकारी काम करवाने का प्रलोभन देकर ठगना शुरू कर दिया. वीरेंद्र के ट्रैवल एजेंसी की गाड़ियां कई मंत्रियों और विधायकों के साथ लगी थीं, लिहाजा लोग इसके झांसे में आकर आसानी से शिकार बन जाते थे. लेकिन जब उसने प्रदेश के दो मौजूदा विधायकों को मंत्री बनवाने का झांसा दिया तो वह पुलिस के चक्रव्यूह में आ गया. पुलिस ने जांच की तो पता चला कि प्रो. रामगोपाल यादव का वीरेंद्र नाम का कोई पीए नहीं है. इसके बाद पुलिस हरकत में आई और जालसाज को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से दो कारें, मंत्रियों विधायकों सांसदों के लेटर पैड, विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड, विधानसभा में प्रवेश वाले पास के अलावा अन्य सामान भी बरामद किए. ■

feedback@chauthiduniya.com

सपा में संगठनात्मक बदलाव

सन्तोष देव गिरि

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव को 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव की चिंता सताने लगी है. इसे देखते हुए उन्होंने पार्टी संगठन के पेंच कसने और खराब पेंच बदलने शुरू कर दिए हैं. हाल ही में प्रदेश के जालौन, कानपुर महानगर, मिर्जापुर और मऊ जिले की जिला कमेटी को भंग करने के साथ उन्होंने जिलाध्यक्ष भी बदल दिए. अचानक हुई इस कार्रवाई से पार्टी संगठन में मठाधीश बने बैठे पदाधिकारियों में खलबली मच गई. वैसे देखा जाए तो यह होना ही था, क्योंकि पार्टी संगठन में व्याप्त गुटबाजी, आपसी मनमुटाव को लेकर पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव भी खफा चल रहे थे. समय-समय पर वह अपनी इस पीड़ा को न केवल प्रकट करते रहे हैं, बल्कि पार्टी के विधायकों, मंत्रियों, पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं तक को चेतावनी भी देते रहे हैं. लेकिन सपा सुप्रीमो की इन बातों का भी कोई असर होता नहीं दिखलाई दे रहा था.

पिछले महीने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में सपा सुप्रीमो ने न केवल प्रदेश के सभी जिला संगठनध्यक्षों की जमकर क्लास ली थी बल्कि मुख्यमंत्री को भी आड़े हाथों लिया था. तभी से यह कयास लगाये जा रहे थे पार्टी में कुछ न कुछ बदलाव जरूर होंगे. इस बदलाव की जद में मिर्जापुर, मऊ जिले का भी नाम जोरशोर से उछल रहा था. आखिरकार वही हुआ जिसकी संभावना थी. शनिवार 2 मई 2015 को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश के कुछ जिलों में ढीले चल रहे पार्टी संगठन के पेंच कसने के बजाए उन्हें बदल देने में ही पार्टी की भलाई समझी और मिर्जापुर संगठन के जिलाध्यक्ष शिवशंकर सिंह यादव को हटा कर उनकी जगह युवा चेहरे पूर्व जिलाध्यक्ष आशीष यादव को फिर से जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिया. इसी प्रकार मऊ में शिवप्रताप यादव मुन्ना, जालौन में सुरेन्द्र यादव बजरिया व कानपुर महानगर के महानगर अध्यक्ष ओमप्रकाश मिश्रा को हटा कर कमान दूसरे को सौंप दी.

2014 के लोकसभा चुनाव से पार्टी नेताओं ने उम्मीद लगा रखी थी कि लोकसभा सीटों पर सपा को ठीकठाक जीत मिलेगी. पार्टी नेताओं, संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं, मंत्री, विधायकों व पदाधिकारियों पर मुलायम को भरोसा था लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो वह झटका देने वाला रहा. सपा के सारे सपने चकनाचूर हो गए. पार्टी केवल परिवार तक ही सिमट कर रह गई. पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी को इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार माना गया था.

मिर्जापुर में संगठनात्मक फेरबदल के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी पृष्ठभूमि भी देखते चलें. वर्ष 2008 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कमान शिवपाल यादव के हाथ में थी तब प्रदेश की लगभग 64 जिला कमेटियां भंग कर दी गई थीं. उस वक्त भी मिर्जापुर में शिवशंकर सिंह यादव को हटाकर आशीष यादव को जिलाध्यक्ष बनाकर लोकसभा 2009 का चुनाव लड़ा गया था. 16 मई 2009 को 15 वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो दस्यु ददुआ के अनुज बालकुमार पटेल ने बसपा के कद्दावर नेता तत्कालीन राजगढ़ विधानसभा सीट से बसपा विधायक अनिल मौर्या को कड़ी टक्कर देते हुए 20 हजार मतों से हराया था. इस विजय का श्रेय आशीष को मिला, लेकिन यह ख्याति कुछ लोगों की नजरों में खटकने भी लगी. उस समय शिवशंकर यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने और पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवार का विरोध करने के कारण न केवल जिलाध्यक्ष से हटाया गया बल्कि पार्टी से उन्हें बाहर का भी रास्ता दिखा दिया गया था. इसी प्रकार 2012 में विधानसभा का चुनाव भी आशीष यादव के नेतृत्व में लड़ा गया था. जिले की पांच विधानसभा सीटो में से एक शहर सीट पर जहां समाजवादी पार्टी का पहले से कब्जा चला आ रहा था, लेकिन इस बार इसमें इजाफा होते हुए पार्टी एकसाथ तीन सीटों पर काबिज हो गई. छानबे, शहर और चुनार सीट पर कब्जा जमाने के साथ ही पार्टी ने चुनारगढ़ के भगवागढ़ के भाजपाई दिग्गज पूर्व मंत्री ओमप्रकाश सिंह को पटखनी देते हुए सपा का झंडा फहराने का काम किया. इससे आशीष यादव का कद और बढ़ गया. इलाहाबाद के हण्डिया में होने वाले उप चुनाव में इन्हें वहां का प्रभारी बनाया गया था जहां सपा की जीत हुई.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रो. रामगोपाल यादव से की गई शिकायत पर आशीष यादव को जिलाध्यक्ष पद से हटाकर उनकी जगह अशोक यादव को जिलाध्यक्ष बना दिया गया था. हालांकि अशोक यादव भी बहुत ज्यादा दिन नहीं चल पाये और एक वर्ष के अंदर ही इन्हें भी हटाकर कमान फिर से शिवशंकर सिंह यादव को सौंप दी गई. संगठन में लगातार हो रहे बदलाव के बाद लोगो को उम्मीद थी कि पार्टी में चल रही गुटबाजी समाप्त हो जाएगी, लेकिन बढ़ती ही जा रही थी. आखिरकार पार्टी नेतृत्व ने आशीष यादव को पुनः जिलाध्यक्ष की कमान सौंपने का फैसला किया. पूर्व में आशीष यादव को तब जिलाध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई थी जब 2009 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा था. इस बार भी ऐसा ही कुछ संयोग है कि ग्राम पंचायत चुनाव के साथ-साथ एमएलसी का चुनाव भी होने वाला है. लेकिन आशीष के सामने चुनौतियां बहुत हैं. ■

चौथी दुनिया ने उजागर की थी अंतर्कलह

समाजवादी पार्टी में चल रही गुटबाजी, अंतर्कलह से जुड़ी खबर चौथी दुनिया ने अपने 20 से 26 अप्रैल 2015 के अंक में प्रकाशित कर धड़ों में बंटे सपा संगठन की सच्चाई उजागर की थी. बताया जाता है कि पार्टी संगठन में चल रही गुटबाजी की शिकायतों के बाद पार्टी ने इस खबर को भी संज्ञान में लिया और नतीजा यह रहा कि पार्टी नेतृत्व ने संगठन के ढीले पेंच कसने और बदलने का काम शुरू कर दिया. ■

एक हुए दो गुट

आशीष यादव को जिलाध्यक्ष बनाये जाने के बाद पार्टी संगठन में चल रही गुटबाजी पर विराम लगने की संभावनाएं काफी हद तक देखने में आने लगी है. बहरहाल इनका आगे क्या स्वरूप होगा यह तो बता पाना अभी कठिन होगा. लेकिन आशीष यादव को भरोसा है कि सभी एक साथ एक मंच पर होंगे और सभी के सहयोग से ही आगामी चुनावों को लड़ा जायेगा और पार्टी की जीत सुनिश्चित की जाएगी. बताते चलें की अभी तक यहां का सपा संगठन धड़ो में बंटा नजर आता था, लेकिन आशीष की ताजपोशी के बाद से नजारा बदला-बदला सा नजर आने लगा है. एक धड़ा का मानो विलय हो गया है इसका नजारा भी आशीष की ताजपोशी के बाद मन रहे जश्न के समय तो देखने को मिला ही लोहिया ट्रष्ट स्थित सपा के जिला कार्यालय में हुई बैठक में राज्य मंत्री एवं नगर विधायक कैलाश चौरसिया और उनकी टीम की उपस्थित ने इस बात के साफ संकेत दिए है कि अब यह गुट भी एक साथ कदमताल करता दिखलाई देगा. हालांकि इस बैठक में टीम शिवशंकर यादव का अभाव जरूर दिखलाई दिया जिसको लेकर तरह-तरह की चर्चा होती रही. ■

उत्तराखंड न्यूज

जनजाति परिवारों की अपने मूल निवास स्थान पर वापसी

जोशीमठ-नीती मोटरमार्ग अभी तक भी पूरी तरह नहीं खुल पाया है. लेकिन शीतकाल के बाद यहां पसरा सन्नाटा भी टूटने लगा है. क्योंकि जनजाति परिवार अपने मूल गांवों को लौटने लगे हैं, इस वर्ष भारी बर्फबारी के कारण नीती तथा माणा घाटियों के मार्ग भी अवरुद्ध हो गए थे. माणा घाटी के मार्ग को तो खोल दिया गया है, अभी सीमांत नीती घाटी का मार्ग फरकिया से आगे अवरुद्ध पड़ा हुआ है. बताया जा रहा है कि फरकिया से आगे नीती तक मार्ग खोलने की कवायद सरकार स्तर पर जारी है. मजदूर लगातार मार्ग को ठीक करने में जुटे हुए हैं. उल्लेखनीय है कि तिब्बत सीमा से यहां के तमाम गांव सटे हुए हैं. शीतकाल में भारी बर्फबारी तथा ठंड से बचने के लिए जनजाति परिवार निचले स्थानों पर स्थित आवासों पर लौट आते हैं और गर्मियों के मौसम में वे फिर अपने मूल गांवों को लौट जाते हैं. इस अवधि में वे इन गांवों में ही खेती आदि कर अपनी आजीविका को मजबूती प्रदान करते हैं. तिब्बत सीमा से सटे सरहदी गांवों में नीती, गमशाली, बांपा, फरकिया, मेहर गांव, कैलाशपुर, मलारी, कोसा, जेलम, द्रोणागिरी, कागा, गरपक व रूईंग आदि शामिल हैं. अब इन गांवों में रहने वाले जनजाति परिवार अपने मूल गांवों की ओर लौटने लगे हैं. वैसे लौंग, फागती, तोलमा, सूकी, लाता, रैणी, पैंग, मुरंड़ा, जुगजू, जुवाग्वाड़ आदि गांव भी इसी घाटी में स्थित हैं. फिर भी यहां के लोग शीतकाल में भी अपने ही इन मूल गांवों में निवास करते हैं. वे वहीं बारहमासा जीवन व्यतीत करते हैं. तब उन्हें कठिन जीवन संघर्ष के बीच गुजर बसर करना पड़ता है. नीती गांव के लोग शीतकाल में भीमतला और कौड़िया गांवों में निवास करते हैं तो गमशाली के लोग बौला, चमेली व सेमला में, बांपा के लोग छिनका तो फरकिया के लोग थिरपाक, बिजार व बिरही में निवास करते हैं. मेहर गांव के सेलवानी, सेमला, सिंहधार तथा कैलाशपुर के लोग बिरही, बाजपुर, चंडिका देवर, पैनी, विजार व सैतोली में प्रवास करते हैं. मलारी के ग्रामीण देवलीबगड़, तेफना, बिरही, मुनियाली, मासौं, झूलाबगड़, पुणकिला, घाट, विजार और सैकोट आदि क्षेत्रों में रहते हैं. कोसा के जनजाति परिवार मंगरोली, तेफना, डिडोली में रहते हैं तो जेलम गांव के बिरही, मुनियाली, तेफना, झूलाबगड़, घाट व विजार में निवास करते है. द्रोणागिरी के लोग बिरही, मैठाणा, पुरसाड़ी, सैकोट, घाट, सैतोली व छिनका में शीतकाल बिताते हैं. अब जनजाति परिवारों के अपने मूल गांवों को लौटने से नीती घाटी में पसरा सन्नाटा टूट रहा है. लेकिन इन्हें अभी संचार तथा स्वास्य आदि सुविधाओं को लेकर परेशानी झेलनी पड़गी. गौरतलब है कि इस घाटी में संचार तथा स्वास्य सेवाओं का अभाव बना रहने से ही लोग पलायन को विवश हैं. इस घाटी में पहुंचते ही सरकार के विकास का सारा दावा खोखला सिद्ध हो जाता है.

-(चौथी दुनिया ब्यूरो)

बहुगुणा-हरीश की मुलाकात से कांग्रेस में हलचल

राज्य में चारधाम यात्रा सहित सबकुछ ठीक-ठाक चलने की चर्चा के साथ विजय बहुगुणा की हरीश रावत से हुई मुलाकात ने हरीश सरकार के माथे पर पसीना ला दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा ने मंत्रिमंडल और अन्य मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात की. भेंट के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा ने कहा कि जब मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं तो मंत्री क्यों नहीं बदले जा सकते. मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की इस भेंट के बहुत से सियासी अर्थ निकाले जा रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक विजय बहुगुणा ने मुख्यमंत्री हरीश रावत से मांग की है कि वे प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में व्यापक बदलाव करें और महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा कांग्रेस के मंत्रियों को ही दें. इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को विधानसभा में कांग्रेस के पूर्ण बहुमत पा जाने की भी दलील दी है. बहुगुणा की मुलाकात से गर्म हुई राजनीति पर हरीश रावत ने अपने एक जुमले से ही पानी डाल दिया है, हरीश ने साफ कहा कि हमारे लिए सबका सुझाव महत्वपूर्ण है. ऊपर वाला एवं हाईकमान जब भी चाहे हम बदलाव के लिए तैयार हैं. भगवानपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत और ममता राकेश के विधायक की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत पर कांग्रेस के भीतर से ही मंत्रिमंडल में फेरबदल और सुरेंद्र राकेश के निधन से खाली कैबिनेट मंत्री की सीट भरने का दबाव बढ़ना शुरू हो गया है. विजय बहुगुणा ने अपनी इस मुलाकात में हरीश से साफ कहा कि 2017 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार के बेहतर प्रदर्शन के लिए अहम विभाग कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को ही मिलने चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव के वक्त कोई यह नहीं देखेगा कि अमुक विभाग किस दल के मंत्री के पास था, जनता सरकार को कांग्रेस की सरकार मानकर ही वोट देगी. बहुगुणा की इस मुलाकात ने दल में दबी चिन्गारी को शोला बनाने का प्रयास कर हरीश को बेचैन कर दिया. सूत्रों के मुताबिक विजय बहुगुणा ने अपने गुट खास विधायकों को भी प्रदेश कैबिनेट में जगह देने की बात कही और कैबिनेट को असंतुलित बताया. वैसे स्व. सुरेंद्र राकेश की पत्नी व भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायत ममता राकेश भी यह कहकर मंत्री पद पर खुले आम दावा पेश कर चुकी हैं कि भगवानपुर की जनता ने उन्हें मंत्री बनने के लिए ही भारी मतों से जिताया है. राजनीति के मर्मज्ञ मानते है कि वह यह दावा मुख्यमंत्री हरीश रावत की शह पर ही कर रही हैं ताकि कांग्रेस के बहुगुणा गुट को कैबिनेट में जगह पाने से रोका जा सके. इसके पहले भी जब कैबिनेट में जगह देने की मांग उठी थी तो मुख्यमंत्री के खास रहे पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने दलित की जगह दलित को देने की पैरवी की थी. वैसे भी प्रदेश कैबिनेट में जगह पाने के लिए कई कांग्रेसी बेताब हैं. खानपुर के कांग्रेस विधायक कुंवर प्रणव सिंह, अन्य पिछड़ा वर्ग और मैदान व हरिद्वार जिले के कोटे के नाम पर अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं तो बहुगुणा खेमे के नाम पर विकासनगर विधायक नवप्रभात, नरेंद्र नगर विधायक सुबोध उनियाल आदि के नाम आगे आते रहे हैं. हरीश रावत किसी भी हाल में अपने पीडीएफ के साथियों का राज्य में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद बाहर का रास्ता नहीं दिखाना चाहते हैं, बहुगुणा इससे अलग राय रखते है. कुल मिला कर कांग्रेस में एक अनार सौ बीमार की स्थिति उजागर हो रही है.

-रेनू शर्मा

फर्जी आईएएस मामले की सीबीआई जांच होगी

मसूरी में फर्जी आइएएस रूबी चौधरी मामले में हरीश रावत सरकार द्वारा सीबीआई को जांच सौपने के संबंध नीतिगत फैसला लगभय तय. उत्तराखण्ड सरकार की पुलिस द्वारा की जा रही विशेष जांच दल द्वारा दिग्गजों का नाम उजागर होने के बाद जांच दल के हाथ-पाव फुल गए. इस मामले में मोदी सरकार के एक मंत्री की संलिप्तता के साथ लालबहादुर शास्त्री भारतीय प्रशासनिक अकादमी संस्थान के डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन(वरिष्ठ आईएएस अधिकारी) की रूबी से घनिष्टता के कई साक्ष्य मिले हैं. सरकार पर बढ़े राजनीतिक दबाव ने सूबे के राज-नेताओं को हिला कर रख दिया है. जिसके चलते इस राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में अपनी जान बचाते हुए हरीश सरकार ने पूरे मामले में गेंद केन्द्र सरकार के पाले में डालना चाहती है. जिसके कारण सरकार पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने चाहती है. मामले में अब तक विशेष जांच दल ने हर कदम फूक-फूक कर रखा है. प्रथम चरण में ही मोदी सरकार के मंत्री का नाम उजागर होते ही राज्य सरकार की पुलिस के फूलने लगे थे. इसके बाद सौरभ जैन की संलिप्ता की चर्चा के मिले पुख्ता प्रमाण ने बड़ी मछली का फसना तय कर दिया था. इस मामले में अपना दामन बचाने के लिए हरीश सरकार ने राजनीति दबाव का राजनीतिक रास्ता ढूढ़ लिया है. अकादमी भी केन्द्र सरकार की है, दागी अधिकारी भी केन्द्र के हैं, जांच एजेंसी सीबीआई भी केन्द्र की रहेगी तो जल्द ही सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी. हरीश सरकार सीबीआई को जांच सौपकर उसके सच को भी परखना चाहती है. मोदी सरकार के मंत्री का दागी आचरण का दम था की रूबी अकादमी में दागी अधिकारियों के दम पर खेलती रही. इस मामले की सीबीआइ जांच के संबंध में पुलिस मुख्यालय की ओर से शासन को जवाब दे दिया है. मसूरी स्थित भारतीय प्रशासनिक अकादमी में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रह रही रूबी चौधरी के मामले में शासन और पुलिस के बीच मामले की सीबीआइ जांच को लेकर पहले भी सवाल खड़ा हुआ था. एसआइटी की ओर से की गई प्रारंभिक जांच में कई अधिकारियों पर इसकी छाया पड़ी है. जिस प्रकार से रूबी चौधरी के पास फर्जी पहचानपत्र, अकादमी के प्रशिक्षुओं की ड्रेस, प्रशिक्षण कार्यकाल की प्रोजेक्ट रिपोर्ट और लाइब्रेरी की किताबें मिली हैं इससे इस मामले में आईएएस अधिकारी जैन सहित कई लोगों की संलिप्तता की आशंका जताई गई है. पुलिस पहले भी स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि बिना किसी अंदर के बड़े आदमी की सहायता के रूबी अकादमी परिसर में नहीं ठहर सकती थी और न ही उसके पास से अकादमी से संबंधित इतना सामान मिल सकता था. रूबी चौधरी भी इस मामले में संस्थान के डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन पर सीधे सवाल खड़ा कर चुकी है. इस कारण यह मामला काफी संवेदनशील हो गया है. मंत्री का नाम आने के कारण पुलिस जांच को आगे बढ़ाने में दबाव में थी. इसी को देखते मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई. बहुचर्चित इस मामले की सूत्रधार रूबि चौधरी चाहती है कि इस मामले की जांच सीबीआई करे.

-राजकुमार शर्मा

हरे भरे बाग बने कंक्रीट के जंगल

उत्तराखंड के पछवादून में जहां बासमती की खुशबू और लिची के बाग लहलहाते थे, भूमाफिया की सरकारी जमीन से लेकर हरे-भरे बागों तक पर गिद्ध दृष्टि लगी हुई है. क्षेत्र में हरे-भरे बाग काटकर कंक्रीट के जंगल उगने से आबोहवा बिगड़ रही है. ताजा मामला बाड़वाला क्षेत्र का है. वहां बाग के जीर्णोद्धार की अनुमति लेकर आम के हरे पेड़ों पर आरियां चला दी गई और मौके से पेड़ों के ठूंठ हटाकर समतलीकरण करा दिया गया है. बाड़वाला क्षेत्र में कुछ माह पहले उक्त बाग के जीर्णोद्धार की अनुमति ली गई थी. जीर्णोद्धार के नाम पर पहले पेड़ों की हैवी लॉपिंग की गई, जिससे पेड़ सूखने लगे. इसके बाद में पेड़ों को जेसीबी लगाकर जड़ से ही समाप्त कर दिया गया. वन विभाग ने जीर्णोद्धार के नाम पर की गई हैवी लॉपिंग पर आपत्ति जताई थी, विभाग की आपत्ति कागजों तक ही सीमित रही और आम के दर्जनों हरे पेड़ों को साफ कर दिया गया. बाग में इन दिनों प्लाटिंग का काम शुरू कर दिया गया है, इसके लिए बाग के बीचों-बीच रास्ता बनाया जा रहा है. हैरत की बात है राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक बाग से पेड़ों का सफाया होने के बाद भी किसी जिम्मेदार की नजर नहीं पड़ी. कालसी वन प्रभाग के डीएफओ रामगोपाल वर्मा ने कहा कि इस प्रकरण की उन्हें जानकारी नहीं है, अधीनस्थ अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट मांग कर कार्रवाई की जाएगी.

-(चौथी दुनिया ब्यूरो)

बिहार के गया शहर में एक मई को ऑडी कार से घर लौट रहे धनाढ्य डॉ. पंकज गुप्ता और उनकी पत्नी शुभ्रा गुप्ता का कार समेत अपहरण कर लिया गया था. अपहरण के बाद उन्हें लखनऊ ले आया गया था. लखनऊ में नाटकीय कार्रवाई कर नौ सदस्यों वाला पूरा गिरोह पकड़ लिया गया. लेकिन उसके पहले ही गिरोह ने डॉक्टर दम्पत्ति को छोड़ दिया था. अपहृत डॉक्टर दम्पत्ति को गोमती नगर में मखदुमपुर पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित शारदा अपार्टमेंट की नौवीं मंजिल के फ्लैट में छुपाकर रखा गया था. अपहरण में इस्तेमाल में आई डॉक्टर की ऑडी कार के साथ-साथ एक फॉरचुनर गाड़ी भी बरामद की गई, जो पहले एक अपहरण के मामले में ही झटकी गई थी.

अपना दल का अपना कौन होगा

वैष्णवी वंदना

मां बेटी की जंग ने अपना दल को पराया-दल में तब्दील कर दिया है. मां कृष्णा पटेल और बेटी अनुप्रिया पटेल में पार्टी नेतृत्व और पकड़ को लेकर तल्खी इतनी बढ़ गई है कि अब यह नागवार शक्ल लेने लगा है. अपना दल में पार्टी पर वर्चस्व की जंग अब चरम पर है. मरहूम सोने लाल पटेल की पत्नी कृष्णा पटेल और बेटी अनुप्रिया पटेल दोनों ही अब खुद को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताकर अपना दल को अपने-अपने कब्जे में लेने के युद्ध में कूद पड़ी हैं. दोनों ही सोनेलाल पटेल और अपना दल का असली वारिस साबित करने में जुटी हैं. लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर से चुनी गईं भाजपा समर्थित सांसद अनुप्रिया पटेल ने पिछले दिनों पार्टी के लालबाग स्थित कार्यालय को सील करवाकर अपनी मां कृष्णा पटेल को यह संदेश भेज दिया कि अब पार्टी की विरासत अनुप्रिया ही संभालेंगी और इसमें किसी का हस्तक्षेप वे बर्दाश्त नहीं करेंगी. इस पर कृष्णा पटेल ने बैठक कर अनुप्रिया पटेल को पार्टी से ही निकालने की घोषणा कर दी. कृष्णा पटेल के नेतृत्व वाले अपना दल को दारुलशफा के कॉमन हाल में भी बैठक करने की इजाजत नहीं मिली. इस पर उन्हें लालबाग में दूसरी जगह बैठक करनी पड़ी. पार्टी पर वर्चस्व की इस जंग में न मां झुकने को तैयार हैं और न बेटी.

अपना दल के संस्थापक सोने लाल पटेल के दिवंगत होने के बाद से दल में वर्चस्व की जंग लगातार चल रही है. सोनेलाल पटेल के बाद उनकी पत्नी कृष्णा पटेल को पार्टी की बागडोर सौंप दी गई थी. उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल अपने पिता के समय से ही राजनीति में सक्रिय हो चुकी थीं. अपने पिता के समय में वह पार्टी के टिकट पर विधायक भी चुनी गई थीं. इस लोकसभा चुनाव में अनुप्रिया के भारतीय जनता पार्टी से हुए करीबी रिश्ते ने मां-बेटी के बीच दरार डाल दी. पार्टी में वर्चस्व की जंग उसी समय से मां-बेटी के बीच शुरू हो गई थी. दरअसल यह महत्वाकांक्षा की जंग थी. मां-बेटी के बीच जंग छिड़ने का कारण अनुप्रिया की दूसरी बहन पल्लवी का राजनीति में सक्रिय होना भी रहा. कृष्णा पटेल ने पार्टी की विरासत अनुप्रिया के बजाय पल्लवी को सौंपने का फैसला कर लिया था. इससे नाराज

अपना दल के संस्थापक स्व.सोने लाल पटेल

अनुप्रिया पटेल ने अपना दल के कार्यकर्ताओं के जरिए खुद को पार्टी का अध्यक्ष घोषित करा लिया और इसकी जानकारी चुनाव आयोग को भी भेज दी.

मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल ने कहा कि वे फरवरी में ही पार्टी की विधिवत राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन ली गई थीं. अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उन्होंने इसकी जानकारी चुनाव आयोग को भी दी थी. चुनाव आयोग को उन्होंने अपने अध्यक्ष निर्वाचित होने से सम्बन्धित दस्तावेज भी सौंपे थे. लेकिन पार्टी दफ्तर पर कृष्णा पटेल ने अपना कब्जा नहीं छोड़ा. अपने समर्थकों के साथ पार्टी आफिस पहुंचकर अनुप्रिया ने पुलिस की मौजूदगी में वहां पहले से लगा ताला हटवाकर नया ताला लगवाया और ऑफिस को सील करा दिया. पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय को सील कराने के बाद अनुप्रिया ने लालबाग में ही एक होटल में बैठक कर सोनेलाल पटेल की जयंती पर दो जुलाई को वाराणसी में होने वाली रैली के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया.

दूसरी ओर कृष्णा पटेल के नेतृत्व वाले अपना दल ने पिछले दिनों दारुलशफा ए-ब्लॉक के कॉमन हॉल में जिला, मंडल, प्रदेश एवं राष्ट्रीय कार्यसमिति की संयुक्त बैठक बुलाई. लेकिन विधायक निवास पहुंचने पर पता चला कि सांसद अनुप्रिया पटेल ने कॉमन हॉल को भी अपने नाम से आवंटित करा लिया है. कृष्णा पटेल के खेमे के महासचिव प्रेमचन्द्र मौर्य का कहना है कि उन्होंने इस बैठक के लिए कॉमन हॉल का किराया भी जमा किया था. इस बैठक में कृष्णा पटेल और सांसद अनुप्रिया पटेल के बीच तमाम जनहितकारी मुद्दों पर बात होनी थी, लेकिन उनके पहले से बुक हॉल को निरस्त करा दिया गया.

इस बैठक में कृष्णा पटेल ने अपने कार्यकर्ताओं से मिशन-2017 में जुटने का आह्वान किया. उन्होंने सेक्टर से लेकर जिला स्तर तक के संगठन को मजबूती से खड़ा करने को भी कहा. उन्होंने चेतावनी दी कि अपना दल में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पल्लवी पटेल ने उत्तर प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों की आत्महत्याएं रुक नहीं रही हैं. सरकार की तरफ से किसानों को जो सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, वह ऊंट के मुंह में जीरे की तरह हैं. उन्होंने सरकार से मांग की कि किसानों के सभी कर्ज तुरन्त माफ किए जाएं. उन्होंने कहा कि अपना दल कृष्णा पटेल को ही अपना नेता मानता है और इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और चुनाव आयोग, लखनऊ के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचित कर दिया गया है.

उत्तर प्रदेश के राजनीतिक क्षितिज पर तेजी से उभरी पार्टी अपना दल मां-बेटी के विवाद के कारण फंस गई है. सोनेलाल पटेल की विरासत संभालने वाली अनुप्रिया पटेल ने कभी यह सोचा भी नहीं था कि उसका सांसद बनना उसके लिए भारी पड़ जाएगा और कृष्णा पटेल की महत्वाकांक्षा उनके जी का जंजाल बन जाएगी. सोनेलाल पटेल की थाती बचाए रखने के लिए जरूरी है अपना दल के अस्तित्व को बचाए रखना, लेकिन इस गृह-कलह ने पार्टी के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है. लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ अपना दल का तालमेल अनुप्रिया पटेल के कारण ही बना. भाजपा ने अनुप्रिया की अपने समाज पर पकड़ को मान्यता दी और राजनीतिक अवसर ने इसकी पुष्टि भी कर दी. लेकिन मौजूदा दौर मां-बेटी की राजनीतिक-परिपक्वता के परीक्षण का भी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

अनुप्रिया ने तोड़ा था रिकार्ड

लोकसभा चुनाव में अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने न केवल रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी, बल्कि उन्होंने अब तक के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले थे. मिर्जापुर लोकसभा सीट से भाजपा-अपना दल की प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल ने चार लाख 36 हजार पांच सौ 36 वोट पाकर अब तक के चुनाव के सारे रिकार्ड तोड़ दिए. अनुप्रिया ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी बसपा की समुद्रा बिंद को दो लाख 19 हजार 79 मतों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. समुद्रा बिंद को दो लाख 17 हजार 457 मत मिले थे. वहां तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेस प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी को एक लाख 52 हजार 666 मत मिले थे और चौथे स्थान पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह पटेल को एक लाख आठ हजार आठ सौ 59 मत पर संतोष करना पड़ा था. ■

कलह के बीच ऑस्ट्रेलिया जाएंगी अनुप्रिया

अनुप्रिया पटेल केंद्र सरकार की ओर से छह सांसदों के दल के साथ ऑस्ट्रेलिया जाएंगी. छह सांसदों का यह दल 13 से 21 मई तक ऑस्ट्रेलिया रहेगा. इसका मुख्य मकसद खास तौर से कई विश्वविद्यालयों में जाकर वहां की शैक्षणिक गतिविधियों का अध्ययन करना है. दल के सदस्य इस दौरान सिडनी, कैनबरा और मेलबर्न भी जाएंगे और प्रतिनिधिमंडल वहां की संसद की कार्यवाही भी देखेगा. अंदरूनी कलह से जूझ रही अनुप्रिया कहती हैं कि अपना दल पार्टी के संस्थापक सोने लाल पटेल की जयंती दो जुलाई को मनाई जाएगी. इस मौके पर वाराणसी में एक रैली का आयोजन भी किया गया है. अनुप्रिया पटेल कहती हैं कि उन्होंने मदर्स डे पर अपनी मां कृष्णा पटेल को बधाई दी थी, लेकिन बहन पल्लवी पटेल को हिदायत दी कि वे हद में रहें. अनुप्रिया ने कहा कि राजनीति और पारिवारिक रिश्तों का फर्क तो समझना चाहिए. पार्टी के सांसद हरिवंश सिंह के आरोपों को भी अनर्गल बताते हुए अनुप्रिया ने उन्हें हद में रहने की चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि हरिवंश सिंह अपना स्वार्थ साधने के लिए उनके परिवार में झगड़ा करा रहे हैं और पार्टी के मिशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं. हरिवंश सिंह लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं और कुछ कार्यकर्ताओं की अनुभवहीनता और बहन पल्लवी की महत्वाकांक्षा का फायदा उठा रहे हैं. ■

डॉ. दंपत्ति के अपहरण की रिहाई का सच क्या है

दीनबंधु कबीर

बिहार के गया जिले से शुरू हुए नाटकीय अपहरणकांड का पटाक्षेप होता दिख रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसा नहीं है. उत्तर प्रदेश और बिहार पुलिस विरोधाभासी बयानों और सूचनाओं में घिर गई है. अपहरण करने वाले गिरोह को जिस तरह खूंखार और प्रोफेशनल बताया गया था, वैसा उसका रिजल्ट दिखने में नहीं आया. लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और हो सकती है. अपहरण गिरोह फिसड्डी निकला या इतना शातिर निकला कि उसने फिरौती की रकम भी वसूल ली, अपहृत डॉक्टर दम्पति को रिहा भी कर दिया और खुद को पकड़वा कर पुलिस को संतुष्ट भी कर दिया. दरअसल, यूपी एसटीएफ और बिहार पुलिस ने ऐसी भ्रमपूर्ण स्थितियां बना दी हैं कि असली सीन समझ में नहीं आ रहा है. सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या फिरौती की रकम पुलिस के हाथ लग गई?

आम लोग तो कहते हैं कि अपहृत दम्पत्ति सही-सलामत घर पहुंच गए और गिरोह सरगना अजय सिंह भी पुलिस के हत्थे आ गया. इसलिए बात खत्म. लेकिन प्रकरण इतने से ही समाप्त नहीं हो जाता. पर्दे के पीछे क्या हुआ और क्या चल रहा है, इसे भी उजागर होना बाकी है. अपहरण कांड की बिहार में मॉनिटरिंग कर रहे आईपीएस कुंदन कृष्णन के बारे में उनके खास लोग यह कह रहे हैं कि उन्होंने गिरोह सरगना के कई नजदीकी रिश्तेदारों को कब्जे में ले लिया था, जिसमें बंगलुरू में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा उसका बेटा भी शामिल था. पुलिस के कब्जे में अजय सिंह की पत्नी और साला भी था. एक तरफ तू छोड़ तो दूसरी तरफ मैं छोड़ूं की शर्त पर दोनों तरफ के लोगों की रिहाई हुई. चलिए, कुंदन कृष्णन के इस फार्मूले की मार्केटिंग तो हो रही है, लेकिन उन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे कि तू छोड़ तो मैं छोड़ूं का फार्मूला ही जब कारगर हो रहा था तो दो-दो राज्यों की पुलिस गुरिल्ला युद्ध जैसे ऑपरेशन चलाने की नौटंकी क्यों कर रही थी? जब अपहृत दम्पत्ति सकुशल घर पहुंच गए और सूचना मिलने के बाद ही लखनऊ के शारदा अपार्टमेंट पर एसटीएफ ने धावा बोला तो इतने भारी गिरोह का एनकाउंटर में सफाया क्यों नहीं कर दिया? एसटीएफ के लोग बड़े आराम से 906 नम्बर फ्लैट में गए, वहां सारे अपराधी पुलिस का स्वागत करने के लिए तैयार बैठे थे. सबने कहा हमें पकड़ो और ले चलो. पुलिस ने पूरे मामले को मजाक बना दिया या पब्लिक को उसने मजाक समझ रखा है.

यह पूरा प्रकरण निश्चित तौर पर राजनीतिक-आर्थिक दबाव का है, जिसके आगे उत्तर प्रदेश की खूंखार मानी जाने वाली एसटीएफ भी आत्मसमर्पण की मुद्रा में आ गई. वह राजनीतिक-आर्थिक दबाव क्या है, इस पर से पर्दा उठना जरूरी है. यूपी के डीजीपी एके जैन कहते रहे कि अपहरणकर्ताओं ने अगवा दम्पत्ति को चारबाग स्टेशन ले जाकर छोड़ दिया. बिहार के डीजीपी पीके ठाकुर कहते रहे कि दम्पत्ति को डेहरी ऑन सोन लाकर छोड़ दिया गया. फिर इलाहाबाद ले जाकर छोड़ आने की बात कही गई. अपहरणकर्ताओं का गिरोह अचानक अगवा दम्पत्ति का इतना खयाल कैसे रखने लगा कि गिरोह के सदस्य उन्हें इलाहाबाद ले जाकर पूर्वा एक्सप्रेस में बैठा आए और उन्हें नमस्ते करने के बाद फिर वापस लखनऊ आ गए. यह कितने समय में पूरा हुआ और फिर वे कितने समय में वापस लखनऊ खुद को पकड़वाने चले आए? आश्चर्य यह है कि दोनों राज्यों के डीजीपी ने अगवा दम्पत्ति को मीडिया के सामने नहीं आने दिया. क्यों? सनसनीखेज अपहरण करने वाले गिरोह के सदस्यों को बाकायदा मीडिया के सामने लाया गया, उनकी तस्वीरें खिंचवाई गईं. जबकि अपराधियों की पहचान-परेड (टीआई परेड) के लिए उनके चेहरे ढंके जाने का सख्त कानूनी निर्देश और प्रावधान है. फिर यूपी के डीजीपी, यूपीएसटीएफ के तमाम अधिकारी, बिहार पुलिस के अधिकारी अचानक इतने लापरवाह कैसे हो गए कि उन सबको एक साथ ही उस कानूनी प्रावधान की याद नहीं आई?

आप यह जरूर याद करते चलें कि बिहार के गया शहर में एक मई को ऑडी कार से घर लौट रहे धनाढ्य डॉ. पंकज गुप्ता और उनकी पत्नी शुभ्रा गुप्ता का कार समेत अपहरण कर लिया गया था. अपहरण के बाद उन्हें लखनऊ ले आया गया था. लखनऊ में नाटकीय कार्रवाई कर नौ सदस्यों वाला पूरा गिरोह पकड़ लिया गया. लेकिन उसके पहले ही गिरोह ने डॉक्टर दम्पत्ति को छोड़ दिया था. अपहृत डॉक्टर दम्पत्ति को गोमती नगर में मखदुमपुर पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित शारदा अपार्टमेंट की नौवीं मंजिल के फ्लैट में छुपाकर रखा गया था. अपहरण में इस्तेमाल में आई डॉक्टर की ऑडी कार के साथ-साथ एक फॉरचुनर गाड़ी भी बरामद की गई, जो पहले एक अपहरण के मामले में ही झटकी गई थी. इन कारों पर बाकायदा लाल-नीली बत्तियां और हूटर वगैरह लगे थे. कई हथियार और गोलियां भी बरामद हुईं. लेकिन पुलिस के साथ कोई हिंसक भिड़ंत नहीं हुई. शारदा अपार्टमेंट का वह फ्लैट गौरव शर्मा का है, जो लंदन में रहते हैं.

अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने के बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने अपनी लंबी-चौड़ी वीर-गाथा प्रस्तुत की, लेकिन अगवा दम्पत्ति की बरामदगी और उनकी उपलब्धता का कहीं कोई जिक्र ही नहीं किया. उसी समय ऑपरेशन प्रायोजित होने का संकेत मिल गया था. अगर यह ऑपरेशन स्वाभाविक होता तो सबसे पहले मीडिया के समक्ष अपहृत डॉक्टर दम्पत्ति को पेश किया जाता. ■

feedback@chauthiduniya.com

एक और कहानी

बिहार से लखनऊ आई बिहार एसटीएफ के एसपी राकेश कुमार ने अगवा दम्पत्ति की रिहाई की एक नई कहानी ही सुनाई. उन्होंने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने डॉ. पंकज और उनकी पत्नी को नशे की हालत में बिहार जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया. ट्रेन जब मुगलसराय पहुंची तब डॉ. पंकज गुप्ता को होश आया और उन्होंने बिहार पुलिस व अपने परिवारवालों को खबर की. यानी, बिहार एसटीएफ के एसपी की कहानी और बिहार पुलिस के डीजीपी की कहानी में भी फर्क है. बिहार की डीजीपी ने कहा था कि डेहरी ऑन सोन पहुंचने के बाद डॉ. पंकज गुप्ता ने अपना फोन खोला और उसके बाद उन्होंने अपने परिवारवालों को सूचित किया कि वे सुरक्षित हैं और डेहरी पहुंच चुके हैं. अगवा दम्पत्ति को अगर अपहरणकर्ताओं के गिरोह ने कोई नशे का पदार्थ खिला कर बेहोश कर दिया था तो उनके बिहार पहुंचते ही उनकी मेडिकल जांच कराई जानी चाहिए थी. एसपी राकेश कुमार ने वहां इस बारे में सूचित और सतर्क क्यों नहीं कर दिया था? अगर घातक नशे के कारण दम्पत्ति मारे जाते तो जिम्मेदारी किसकी होती? एसटीएफ का एसपी होते हुए राकेश कुमार मामले को इतना कैजुअल क्यों ले रहे थे? इन सवालों का जवाब बिहार और यूपी, दोनों प्रदेशों के लोगों को चाहिए. गिरोह के पकड़े जाने के बाद यूपी एसटीएफ के अधिकारियों ने कहा था कि गिरोह सरगना अजय सिंह अपार्टमेंट की छत पर बनी टंकी में छुप गया था. जबकि बिहार एसटीएफ के राकेश कुमार ने कहा था कि अजय सिंह गर्मी के कारण टंकी पर चढ़ कर सोया हुआ था, वहीं सोये हुए ही पकड़ा गया. अब यूपी एसटीफ सत्य या बिहार एसटीएफ सत्य? ■